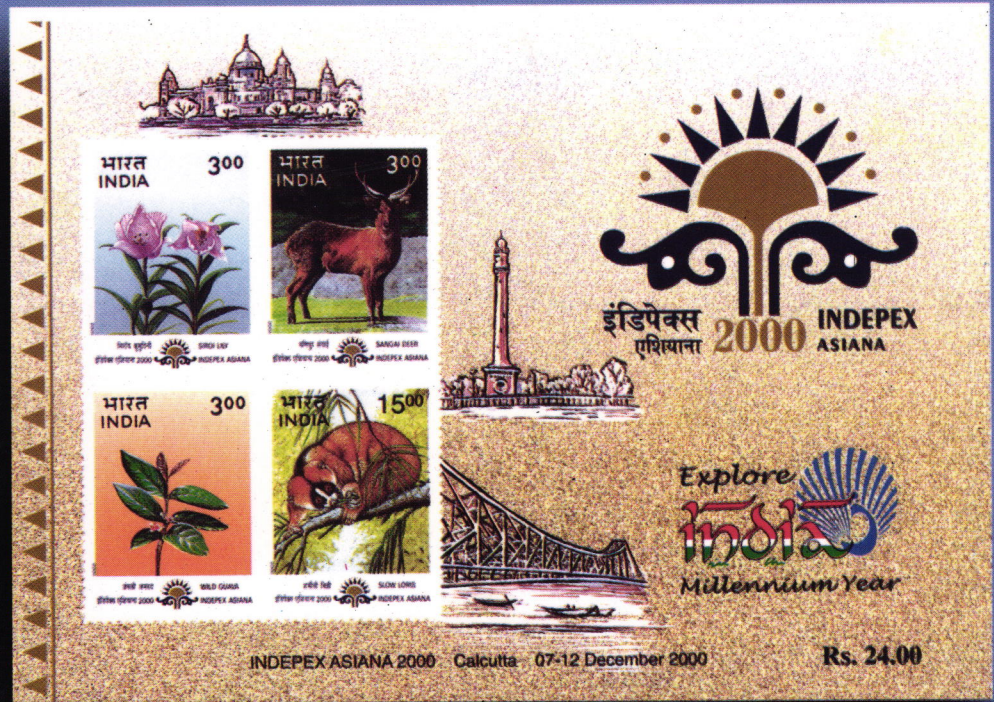




सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2000-2001

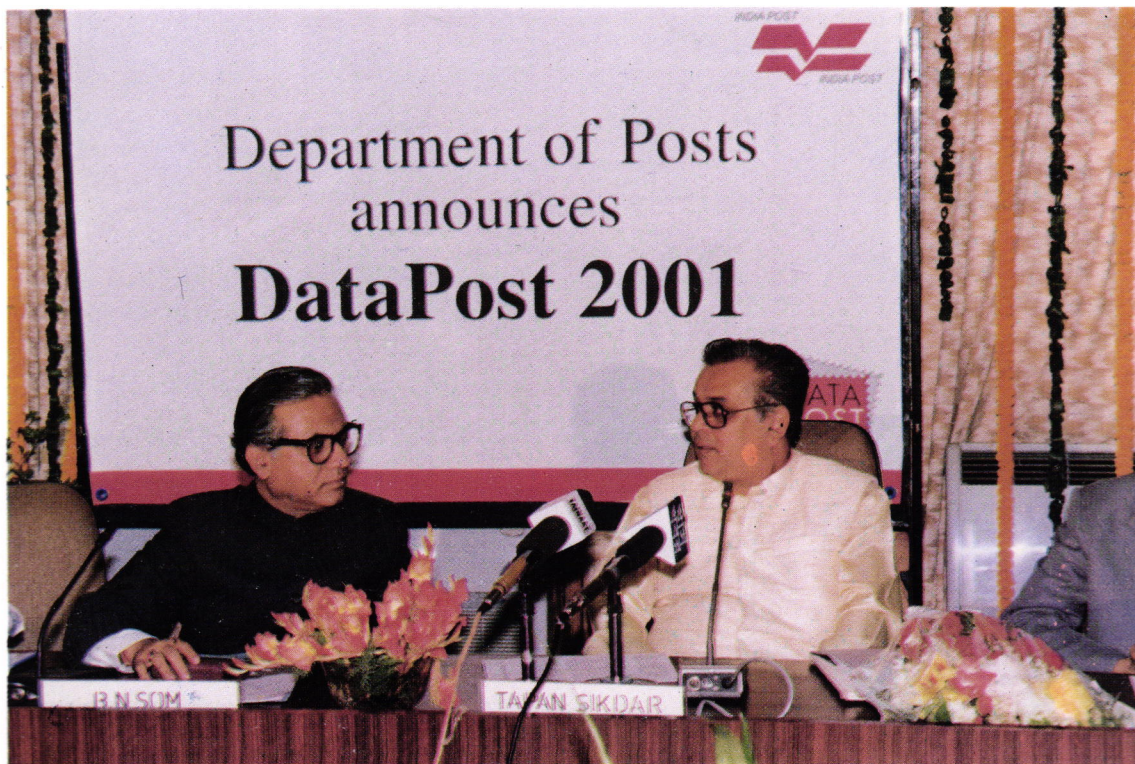


भारतीय डाक विभाग
Department of Posts, India



31.12.2000 को भारत की महान ऐतिहासिक विरासत डाक-टिकटों के विमोचन के अवसर पर श्री राम विलास पासवान, माननीय संचार मंत्री के साथ प्रो. वी. के. मल्होत्रा, संसद सदस्य और डा. कर्ण सिंह।

Shri Ram Vilas Paswan, Hon'ble Minister for Communications alongwith Prof. V.K. Malhotra, M.P. and Dr. Karan Singh at the release of India's Great Historical Heritage Postal Stamps on 31.12.2000.



डाटा पोस्ट 2001 के शुभारंभ के अवसर पर श्री तपन सिकदर, माननीय संचार राज्य मंत्री और श्री बी.एन. सोम, सचिव (डाक)। Shri Tapan Sikdar, Hon'ble Minister of State for Communications and Shri B.N. Som, Secretary (Posts) at the launching of Data Post 2001.



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2000-2001

भारतीय डाक विभाग
(संचार मंत्रालय)
DEPARTMENT OF POSTS
(MINISTRY OF COMMUNICATIONS)
INDIA

विषय सूची

भाग I

वार्षिक रिपोर्ट (1999 - 2000)

		पृष्ठ सं.
	तालिका सूची	iv
	लक्ष्य एवं उद्देश्य	1
अध्याय 1	पुनरीक्षा	3
अध्याय 2	संगठन	7
अध्याय 3	डाक प्रचालन	13
अध्याय 4	व्यवसाय विकास कार्यक्रमलाप	23
अध्याय 5	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	29
अध्याय 6	प्रौद्योगिकी	39
अध्याय 7	वित्तीय सेवाएं	45
अध्याय 8	वित्तीय प्रबंधन	51
अध्याय 9	मानव संसाधन विकास	61
अध्याय 10	सतर्कता कार्यक्रमलाप	63
अध्याय 11	अन्य कार्यक्रमलाप	65
अध्याय 12	पूर्वोत्तर में विकासात्मक कार्यक्रमलाप	71

भाग II

कार्यकलाप (अप्रैल - दिसम्बर 2000)	77
--	----

CONTENTS

PART I

ANNUAL REPORT (1999-2000)

	Page No.
List of Tables	v
Mission Statement	2
Chapter 1 Overview	4
Chapter 2 Organisation	8
Chapter 3 Postal Operations	14
Chapter 4 Business Development Activities	24
Chapter 5 International Relations	30
Chapter 6 Technology	40
Chapter 7 Financial Services	46
Chapter 8 Financial Management	52
Chapter 9 Human Resource Development	62
Chapter 10 Vigilance Activities	64
Chapter 11 Other Activities	66
Chapter 12 Developmental Activities in the North East	72

PART II

Activities (April-December 2000)	78
-------------------------------------	----

तालिका सूची

क्र. सं.	तालिका	पृष्ठ सं.
1.	मनीआर्डर परियात तथा प्रेषित मनीआर्डरों का मूल्य	15
2.	डाक परियात	15
3.	आधुनिकीकृत और कम्प्यूटरीकृत किए गए मेल कार्यालय	17
4.	व्यवसाय विकास कार्यकलापों की उत्पादवार राजस्व वृद्धि	23
5.	अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट-ई.एम.एस. परियात	33
6.	एल.सी. / ए.ओ. डाक	33
7.	विदेश पार्सल परियात	33
8.	विदेश मनीआर्डर	37
9.	बचत योजनाएं : कार्य व्यापार रूपरेखा	45
10.	डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा द्वारा किया गया कार्य-निष्पादन : 1999 - 2000	47
11.	समग्र वित्तीय निष्पादन (1999 - 2000)	53
12.	1999 - 2000 में एजेंसी सेवाओं/वित्तीय सेवाओं के संबंध में कार्यकारी व्यय की वसूली	55
13.	1999 - 2000 के दौरान अभ्यर्पित निधियां तथा बचत	57
14.	सेवाओं की लागत	59
15.	डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय : 2000 - 2001	85
16.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैराओं और 12.2.2001 तक बकाया पड़े पैराओं का व्योरा	91
17.	31.3.2000 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	91
18.	31.3.2000 को भूतपूर्व सैनिकों / विकलांग भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला कर्मचारियों की संख्या	91
19.	कार्मिक : 31.3.2000 को वास्तविक संख्या	95
20.	डाकघरों, कार्मिकों तथा मेल परियात की संख्या : एक रूपरेखा 1947-48 से 1999 - 2000 तक	97



LIST OF TABLES

Sl.No.	Tables	Page No.
1.	Money Order Traffic and Value of Money Orders Transmitted	16
2.	Mail Traffic	16
3.	Mail Offices Modernised and Computerised	18
4.	Product-wise Revenue Growth of Business Development Activities	24
5.	International Speed Post – EMS	34
6.	LC/AO Mails	34
7.	Foreign Parcel Traffic	34
8.	Foreign Money Orders	38
9.	Saving Schemes : Business Profile	46
10.	Performance of PLI/RPLI : 1999-2000	48
11.	Overall Financial Performance (1999-2000)	54
12.	Recovery of Working Expenses on account of Agency/Financial Services in 1999-2000	56
13.	Funds Surrendered and Savings during 1999-2000	58
14.	Cost of Services	60
15.	PLI/RPLI Business: 2000-2001	86
16.	Details of Paras in Report of C & AG of India and still Outstanding	92
17.	No. of Employees : Scheduled Castes/Tribes as on 31.3.2000	92
18.	No. of Employees : Ex-servicemen, Disabled Ex-servicemen and Women	92
19.	Personnel : Actual Strength as on 31.3.2000	96
20.	No. of Post Offices, Personnel and Mail Traffic: A Profile – 1947-48 to 1999-2000	98

लक्ष्य और उद्देश्य

भारतीय डाक विभाग का उद्देश्य भारत और पूरे विश्व में उच्च गुणवत्ता वाली डाक, पार्सल और सम्बद्ध सेवाएं प्रदान करना, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और समाज के समक्ष उनकी आशाओं से भी अधिक कार्यकुशल और उत्कृष्ट संगठन के रूप में पहचान बनाना तथा निम्नलिखित कार्य निष्पादित करना है :

- उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के प्रति पूर्ण समर्पण।
- कार्यकुशल और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करने के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, यही उपभोक्ता द्वारा खर्च किए धन का असली मूल्य है।
- प्रत्येक कर्मचारी के लिए चुनौतीपूर्ण तथा लाभप्रद कैरियर प्रदान करने के प्रति वचनबद्धता।
- देश के सामाजिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक जीवन के एक भाग के रूप में जिम्मेदारियों को पूर्ण मान्यता प्रदान करना।
- सभी क्षेत्रों में अग्रणी तथा अभिनव बने रहने के प्रति संपूर्ण उत्साह।



MISSION STATEMENT

The Mission of the India Post is to provide high quality mail, parcel and related services in India and throughout the world; to be recognised as an efficient and excellent organisation exceeding the expectations of the customers, employees and the society; to perform the task by:

- Total dedication to understanding and fulfilling customer needs.
- Total devotion to providing efficient and reliable services, which the customers consider to be value for money.
- Total commitment to providing challenging and rewarding career for every employee.
- Total recognition of the responsibilities as a part of the social, industrial and commercial life of the country.
- Total enthusiasm to be forward looking and innovative in all areas.

अध्याय-1

पुनरीक्षा

आर्थिक परिदृश्य

1.1 वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई दिए। आर्थिक वृद्धि, 1991 के बाद की अवधि की प्रवृत्ति के अनुरूप बनी रही। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 6.4% थी, जबकि 1998-99 के दौरान वृद्धि दर 5.8% थी। साफ़वेयर जैसे तेजी से उन्नति करने वाले कुछ घटकों के सहारे सेवा क्षेत्र में उभार आया जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिखाई दिए।

1.2 औद्योगिक वृद्धि 1998-99 के 6.6% से बढ़कर 8.1% हो गई, 205 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। बैंकों के पास उपलब्ध कुल जमा में पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 5.5 बिलियन यू.एस. डॉलर की बढ़ोतरी हुई। हाल के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक तथा वित्तीय बाजारी परिस्थितियों का बाह्य भुगतान पर बढ़ता प्रभाव और उभरती बाजारी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती संभावनाएं हैं। साथ ही, भारतीय निर्यात में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य सुधार हुआ है। मुद्रा-स्फीति में नाटकीय ढंग से कमी हुई।

1.3 अर्थव्यवस्था की इन सभी गतिविधियों से डाक संचार प्रणालियों सहित ढांचागत क्षेत्रों पर मांग का दबाव बढ़ा है। ज्यों-ज्यों विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है त्यों-त्यों ढांचागत सेवाओं से मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

चुनौतियां और कार्यनीतियां

1.4 समूचे विश्व में डाक-प्रशासन, डाक के बढ़ते हुए परिमाण, ग्राहकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता, निजी कुरिअर उद्योग के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संचार प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व विकास के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं। यू.पी.यू. के एक अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि डाक परियात की मात्रा में होने वाली वृद्धि अथवा कमी निम्नलिखित कारकों के कारण हो सकती है :-

आर्थिक कारक	45 प्रतिशत
डाक कारक	24 प्रतिशत
सामाजिक कारक	21 प्रतिशत
प्रौद्योगिकीय कारक	10 प्रतिशत

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी डाक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ (यू.पी.यू.) के तत्वावधान में कार्यनीतियां तैयार कर रहे हैं।

1.5 जहां एक ओर समाज को उसकी आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से डाक सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर डाक को अन्य क्षेत्रों जैसे व्यापार तथा उद्योग, सरकारी तथा संस्थागत निकायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है, जो कि अपेक्षाकृत अधिक कीमत चुकाकर अधिक त्वरित सेवा की मांग करते हैं। विभिन्न श्रेणियों की डाक जैसे घरेलू डाक, सरकारी डाक, कारपोरेट क्षेत्र की डाक, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं, द्वितीय श्रेणी की अन्य डाक, जिनकी समय-संवेदनशीलता भिन्न-भिन्न होती है, के प्रोसेसिंग को ग्राहकों की सुविधा के अनुरूप बनाने तथा उसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। चुनौतियों का सामना करने और सेवाओं में सुधार लाने के लिए डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का समावेश डाक प्रशासनों द्वारा विश्वभर में इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास हैं। आने वाले समय में ग्राहक की अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी और उसे संतुष्ट रखा जाना निहायत ही आवश्यक है।

विभाग के उद्देश्य

1.6 भारतीय डाक के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- देश के जनजातीय, पहाड़ी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी भागों में बुनियादी डाक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- कार्यकुशल, भरोसेमंद तथा किफायती सेवाएं प्रदान करना;
- बाजार की जरूरतों के अनुसार मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना;
- कार्य की बढ़ती मात्रा को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए सेवाओं का आधुनिकीकरण करना और ग्राहक एवं कर्मचारियों के संतुष्टि-स्तर में वृद्धि करना;
- एक प्रगतिशील संगठन बनना; तथा
- अधिक संसाधन जुटाना और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार करना।

1.7 डाक विभाग ने सदैव जनता की सामर्थ्य के भीतर बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया है और इसलिए बुनियादी डाक सेवाओं को अत्यधिक सब्सिडी मिलना जारी है। ग्राहकों



Chapter 1

OVERVIEW

Economic Scenario

1.1 During the year 1999-2000 the Indian economy exhibited a good degree of resilience. Economic growth continued to be in line with the trend in the post 1991 period. The growth rate in Gross Domestic Product was 6.4% against a growth rate of 5.8% during 1998-99. Industry showed recovery while the services sector surged ahead led by some of the fast rising segments such as software.

1.2 Industrial growth rose to 8.1% from 6.6% in 1998-99. Food grains production was more than 205 million tonnes. The aggregate deposits with banks rose by 13.9% over the previous year. Foreign exchange reserves increased by about US\$ 5.5 billion. A significant aspect of the recent economic developments is the increasing influence of economic and financial market conditions in industrial economies on external payment and growth prospects in emerging market economies, including India. Export performance improved on par with the better performing emerging economies. Inflation dropped dramatically.

1.3 All these developments in the economy have led to increasing demands on the infrastructure sectors, including postal communications systems. The demand on infrastructure services is likely to grow as growth takes place in various sectors.

Challenges and Strategies

1.4 Postal Administrations the world over are grappling with the challenges posed by growing volume of mail, the need to delivery services faster to the customers increasing competition from private courier, industry and unprecedented advances in communications technology. A UPU study has shown that the increase or decline in postal traffic volumes can be attributed to the following factors.

- Economic factors	-	45%
- Postal factors	-	24%
- Social factors	-	21%
- Technological factors	-	10%

Postal administrations everywhere, under the aegis of the Universal Postal Union (UPU), are evolving strategies to respond to these challenges.

1.5 While affordable postal service has to be provided to the society at large, the Post also has to cater to the specific needs of segments like the business and industry, government and institutional bodies who demand a much quicker service even at relatively higher cost. There is need for customisation and prioritisation in the processing of different categories of mail like household mail, government mail, corporate sector mail, newspapers and magazines, other second-class mail which have different time-sensitivity. Modernisation of postal operations and induction of technology are important steps initiated by postal administrations the world over, to meet the challenges and improve the services. The customer in future is going to be very demanding and he must be kept satisfied.

Objectives of the Department

- 1.6 The major objectives of India Post are to:
- ensure availability of basic postal services in all parts of the country, including tribal, hilly and remote areas;
 - provide efficient, reliable and economic service;
 - provide value-added services according to market requirements;
 - modernize the services to handle the growth volume of work with efficiency and enhance customer and employee satisfaction;
 - be a forward-looking organisation; and
 - generate more resources and improve financial performance.

1.7 The Department has already endeavored to provide basic postal services to the people at an affordable price, and thus the basic postal services continue to be heavily subsidised. Taking note of the changing customer needs, the Department of Posts has taken initiatives to introduce value added postal services at market competitive prices to the Business

की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने व्यापार तथा उद्योग के लिए बाजार के प्रतियोगी मूल्यों पर मूल्यवर्धित डाक सेवाएं शुरू करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। विभाग में व्यवसाय विकास निदेशालय की स्थापना इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है (देखें अध्याय-4)। व्यवसाय विकास निदेशालय द्वारा बधाई डाक, डाटा पोस्ट, और हाइब्रिड मेल सहित कई मूल्यवर्धित उत्पादों का विपणन किया गया है। ग्राहकों के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर और ऐसे उत्पादों को बाजार में उतारने की संभावना है।

वित्तीय स्थिति

1.8 वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 24 सेवाओं में से केवल 6 सेवाएं ही अपनी पूरी लागत वसूल कर पाने में समर्थ हुईं तथा उनसे विभाग को कुछ लाभ भी होगा। इसी तरह 18 सेवाओं को सब्सिडी दी गई। 1999-2000 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति 2020.12 करोड़ रु. थी जबकि निवल कार्यकारी व्यय 3615.94 करोड़ रु. था। इस प्रकार 1595.82 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

परियात

1.9 1999-2000 के दौरान अधिकांश सेवाओं के संदर्भ में

डाक परियात कम बना रहा और इन पर सब्सिडी दी जाती रही। 1999-2000 के प्रोजेक्शन के अनुसार पंजीकृत डाक-वस्तुओं, मनीआर्डर तथा पोस्टकार्ड पर सबसे ज्यादा सब्सिडी दी गई।

डाक प्रचालन

1.10 विभाग शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में डाक तथा वितरण सेवाओं में सुधार के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहा है। यह प्रधान डाकघरों के सम्पूर्ण कार्यकलापों का तेजी से कम्प्यूटरीकरण कर रहा है तथा और अधिक कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण केन्द्रों की संस्थापना कर रहा है। विभाग तीव्र गति वाले वी-सेट नेटवर्क की संस्थापना करने के लिए भी कार्रवाई कर रहा है।

1.11 विभाग अपने प्रचालन में प्रौद्योगिकी का निरंतर समावेश करते रहने के बावजूद डाक को जनोपयोगी सेवा का एक बेहतर साधन बनाने के लिए अपने प्रबंधन कार्य को जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अधिक अनुरूप बनाने, सेवाओं को ग्राहकों के अधिक अनुकूल बनाने तथा प्रणाली को अधिक बोधगर्भ बनाकर परिष्कृत करने का अधिक प्रयास कर रहा है।

and Industry. Establishment of Business Development Directorate in the Department is one vital step in this direction (refer Chapter 4). A large number of value added products have been marketed by the Business Development Directorate including greetings post, data post and hybrid mail. More such products keeping in view the requirements of various segments of customers are likely to be introduced.

Financial Position

1.8 During the year 1999-2000, out of a total of 24 services, only 6 services were able to recover full cost and leave some margin of profit of them for the Department. Thus 18 services were subsidised. The total revenue receipts during 1999-2000 was Rs.2020.12 crores against net working expenses of Rs. 3615.94 crores leaving a gap of Rs.1595.82 crores.

Tariff

1.9 During 1999-2000 the postal tariff on most

services continued to be low and subsidised. As per projections for 1999-2000 the subsidies were the highest in respect of registered articles, money order and postcard.

Postal Operations

1.10 The Department is taking various steps to improve the mail and delivery services in both urban and rural areas. It is busily computerising the entire functions of Head Post Offices and setting up more computerised registration centres. It is also in the process of setting up a high speed VSAT network.

1.11 The Department is sparing no efforts to make the management more responsive to public needs and expectations, make the services more customer friendly and humanise the system more perceptibly even as it inducts and assimilates increasing doses of technology into the operations to make the Post a better instrument of public utility service.

अध्याय-2

संगठन

2.1 डाक विभाग, संचार मंत्रालय का एक विभाग है। यह विभाग श्री राम विलास पासवान, संचार मंत्री के अधीन काम कर रहा है। श्री तपन सिकंदर संचार राज्य मंत्री हैं। श्री बी.एन. सोम, सचिव, डाक विभाग के साथ-साथ महानिदेशक, भारतीय डाक और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड हैं।

2.2 डाक सेवा बोर्ड इस विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय है। इसमें अध्यक्ष और तीन सदस्य हैं। बोर्ड के तीन सदस्यों के पास प्रचालन, विकास तथा कार्मिक विभाग हैं। विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, सचिव, डाक सेवा बोर्ड के वरिष्ठ बोर्ड की सहायता करते हैं। इस समय, उप महानिदेशक (आई. आर.), सचिव, डाक सेवा बोर्ड के वरिष्ठ बोर्ड की सहायता कर रहे हैं। मुख्यालय में उप महानिदेशक, निदेशक तथा सहायक महानिदेशक बोर्ड को आवश्यक कार्यात्मक सहयोग देते हैं।

2.3 डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 22 डाक सर्किलों में बांटा गया है। प्रत्येक सर्किल, राज्य का सह-टर्मिनस है। इसके अपवाद हैं - पूर्वोत्तर सर्किल जिसमें छह उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र सर्किल जिसमें गोवा राज्य शामिल है, पश्चिम बंगाल सर्किल जिसमें सिक्किम राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, केरल सर्किल में लक्ष द्वीप संघ राज्य क्षेत्र शामिल है और पंजाब में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। इन सर्किलों में प्रत्येक सर्किल की अध्यक्षता मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा की जाती है। प्रत्येक सर्किल को परिक्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें फोल्ड यूनिटें होती हैं, जिन्हें डिब्बोजन (डाक / रेल डाक सेवा डिब्बोजन) कहा जाता है। हरेक परिक्षेत्र की अध्यक्षता पोस्टमास्टर जनरल द्वारा की जाती है जो उस क्षेत्र का डाक प्रबंधक होता है। सर्किलों और परिक्षेत्रों में सर्किल स्टैम्प डिपो, डाक भंडार डिपो तथा मेल मोटर सेवा आदि जैसी अन्य प्रकार्यात्मक अवलंबी संभार तंत्र यूनिटें भी होती हैं।

2.4 इन 22 सर्किलों के अलावा एक अन्य डाक सर्किल भी है जिसे बेस सर्किल कहा जाता है, जो सशस्त्र सेनाओं की डाक संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बेस सर्किल की अध्यक्षता अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा द्वारा की जाती है। सेना डाक सेवा के अधिकारी संयुक्त रूप से प्रतिशत सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी होते हैं तथा सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों के लिए भी 75 प्रतिशत कार्मिक डाक विभाग से लिए जाते हैं और शेष कार्मिक सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं।

2.5 भारतीय डाकघरों को प्रधान, उप तथा शाखा डाकघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शाखा डाकघर, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं। उप डाकघर विभागीय डाकघर हैं जो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रधान डाकघरों को उनके कार्यभार तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुसार पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया है, इनमें से सबसे बड़े डाकघर मुंबई और कलकत्ता के जनरल पोस्ट आफिस (जी.पी.ओ.) हैं और उनके बाद अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ स्थित जी.पी.ओ. आते हैं।

2.6 विभाग के संगठनात्मक ढांचे में, प्रौद्योगिकी के समावेश के कारण संचार बाजार में भारतीय डाक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में पिछले कुछ समय से पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन को परिवर्तन की संक्रमण-कालीन समस्याओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे उच्चतर प्रबंधन की समन्वय भूमिका को समुचित महत्व देते हुए मुख्यतया प्रकार्यात्मक आधार पर तैयार किया गया है। निर्णयकर्ताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए पारंपरिक पिरामिड प्रणाली को डेस्क प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये सुधार प्रणाली को उस गतिशीलता और सामर्थ्य से अनुप्राणित कर देंगे जो एक अनुक्रियाशील, संवेदनशील, दक्ष और कुशल प्रबंध प्रणाली के लिए आवश्यक है।



Chapter 2

ORGANISATION

2.1 The Department of Posts under the Ministry of Communications continues to function under Shri Ram Vilas Paswan, Minister for Communications. Shri Tapan Sikdar is the Minister of State for Communications. Shri B.N. Som is the Secretary, Department of Posts, Director General, India Post and the Chairman of the Postal Services Board.

2.2 The Postal Services Board, the apex management body of the Department, comprises the Chairman and three Members. The three members of the Board hold portfolios of Operations, Development and Personnel. The Joint Secretary and Financial Advisor to the Department is a permanent invitee to the Board. The Board is assisted by a senior staff officer of the Directorate as Secretary to the Board. Presently, DDG (IR) is assisting the Board in this capacity. Dy. Directors General, Directors and Assistant Directors General provide necessary support for the Board at the Headquarters.

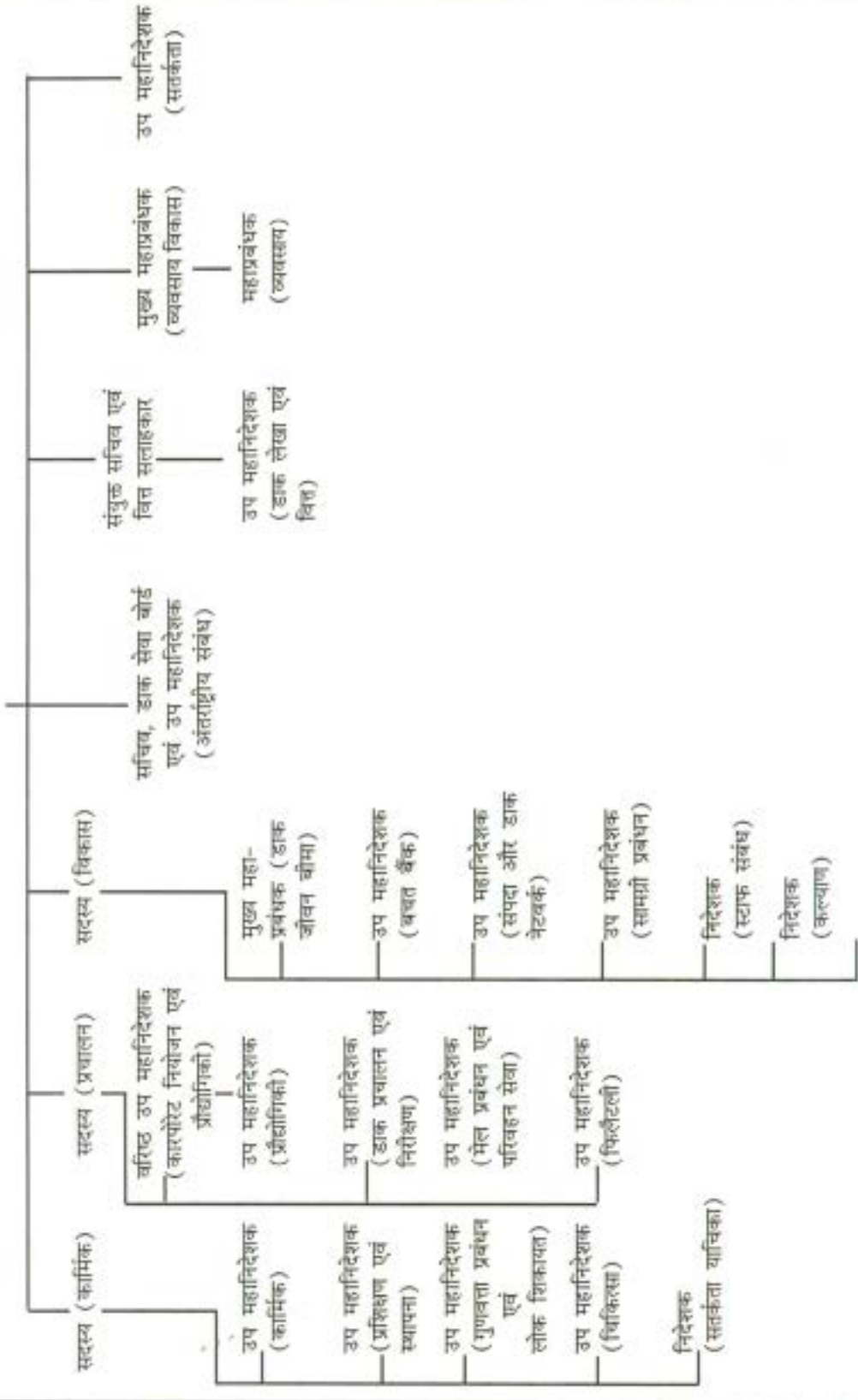
2.3 For providing postal services, the whole country has been divided into 22 Postal Circles. Each Circle is co-terminus with a State except that the North Eastern Circle comprises six North Eastern States; Maharashtra Circle includes the State of Goa; West Bengal Circle includes the State of Sikkim and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands; Kerala Circle includes the Union Territory of Lakshadweep and Punjab Circle includes the Union Territory of Chandigarh. Each of these Circles is headed by a Chief Postmaster General. Each Circle is divided into Regions comprising groups of field units, called Divisions (Postal/RMS Divisions). Each region is headed by a Postmaster General who is the Postal Manager of the area. In the Circles and Regions there are other functional supporting logistical units like Circle Stamp Depots, Postal Stores Depots and Mail Motor Service, etc.

2.4 Over and above these 22 Circles, there is another Postal Circle, called Base Circle, to cater to the postal communication needs of the armed forces. Base Circle is headed by the Additional Director General, Army Postal Service. Cent per cent of the officer cadre of Army Postal Services is on deputation from the civil post and 75 per cent of the other ranks of the Army Postal Service are also drawn from the Department of Posts and the remaining personnel are recruited by the Army.

2.5 Indian post offices are categorised as Head, Sub and Branch Post Office. Branch Post Offices are Extra-Departmental Post Offices (EDBOs) located in rural India. The Sub Post Offices are departmental offices located in both rural and urban areas. Head Post Offices are graded into five categories according to their workload and staff strength, the largest being the General Post Offices at Mumbai and Calcutta, followed by GPOs at Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Kanpur and Lucknow.

2.6 The organisational set up of the Department has been undergoing restructuring in recent times as a response to the challenges faced by the post in the communication market due to induction of technology. This restructuring is designed to tackle the transitional problems of change and is primarily on functional basis giving due importance to the coordinating role of the higher management. Steps have been taken to substitute the traditional pyramidal system with desk level system to support the decision makers. These reforms are being introduced to infuse the system with dynamism and strengths that are needed to create a responsive, sensitive, efficient and vibrant management system.

डाक विभाग का संगठनात्मक चार्ट
संचार मंत्री
संचार राज्य मंत्री
सचिव

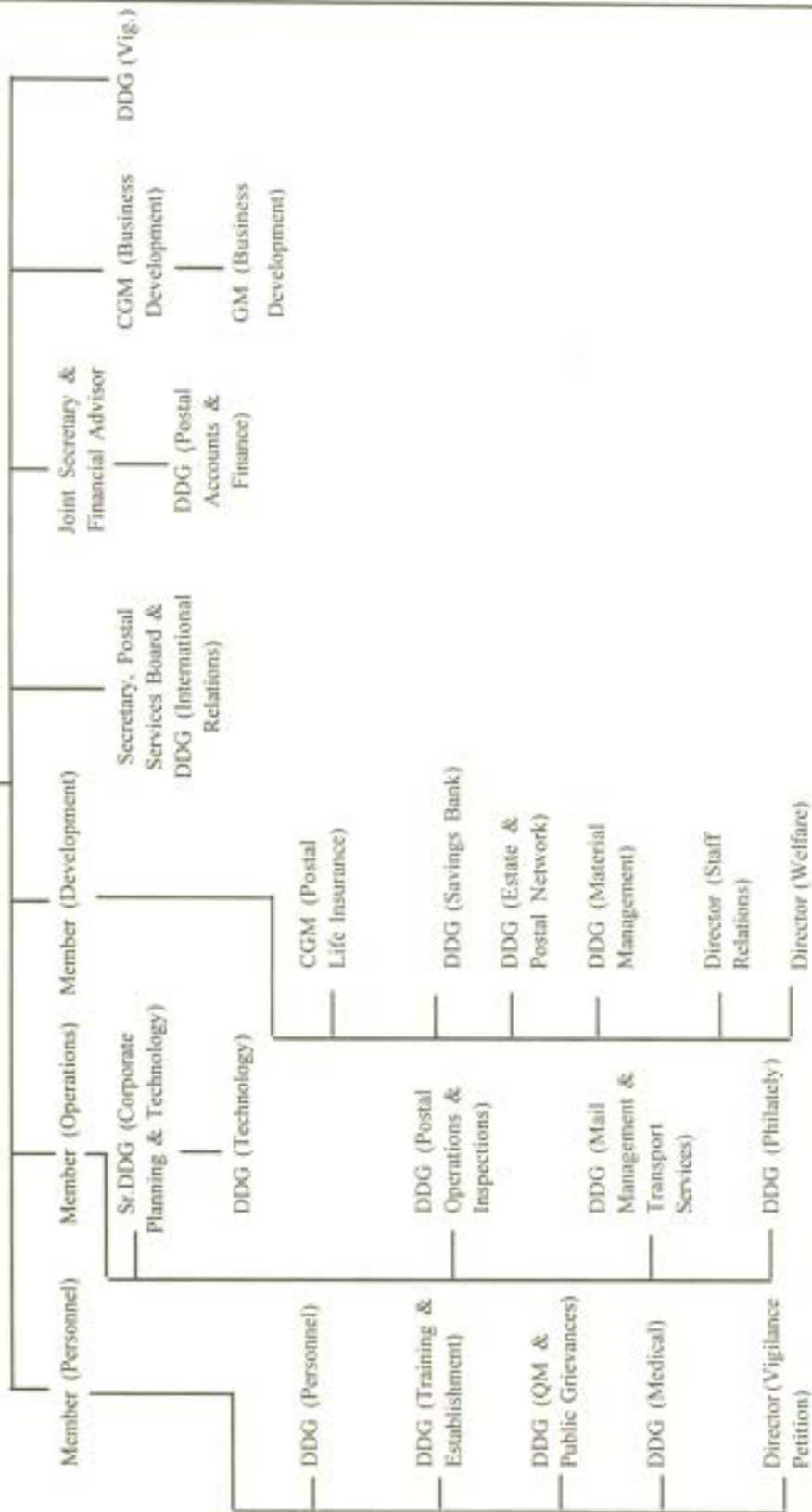


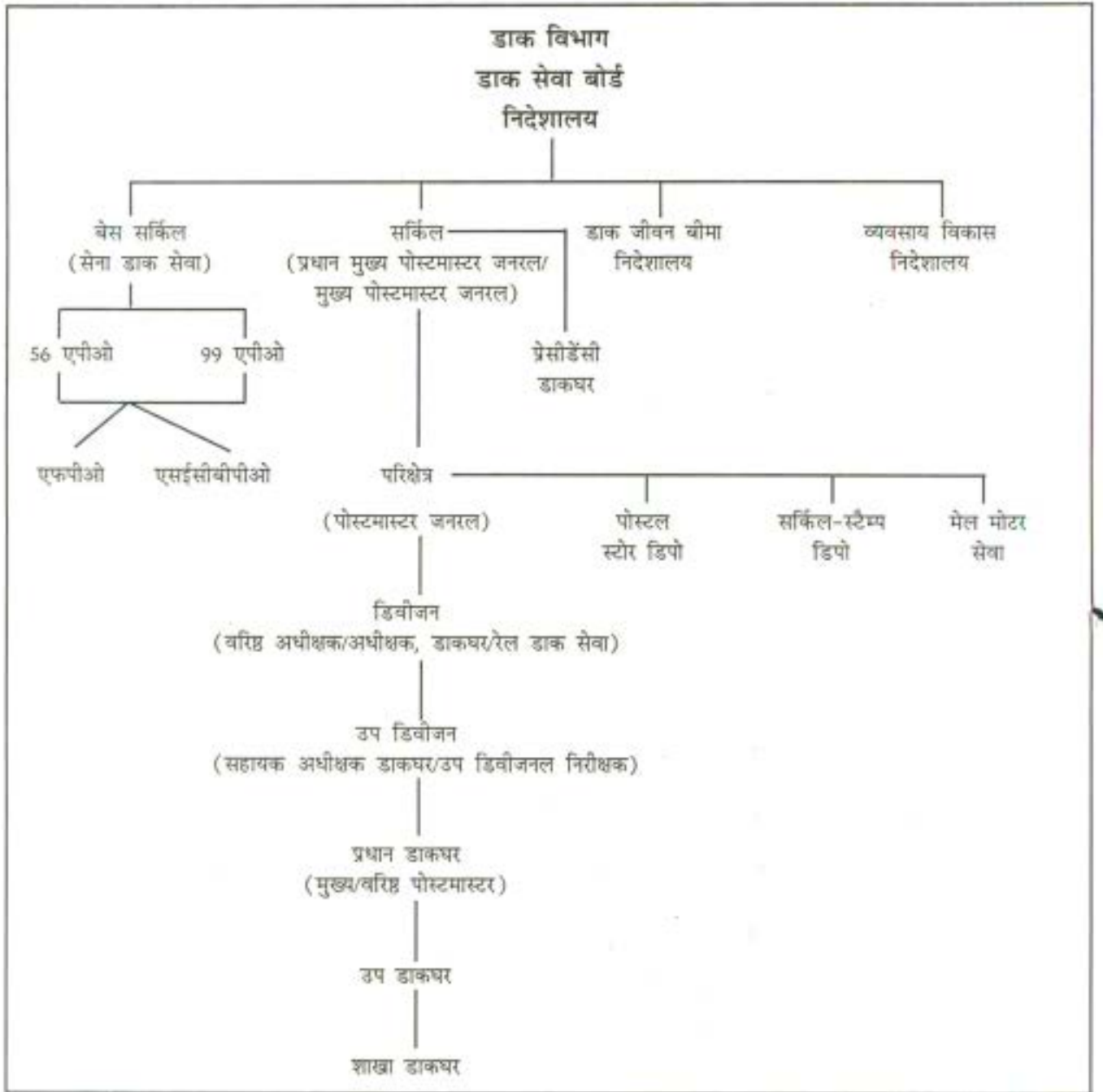


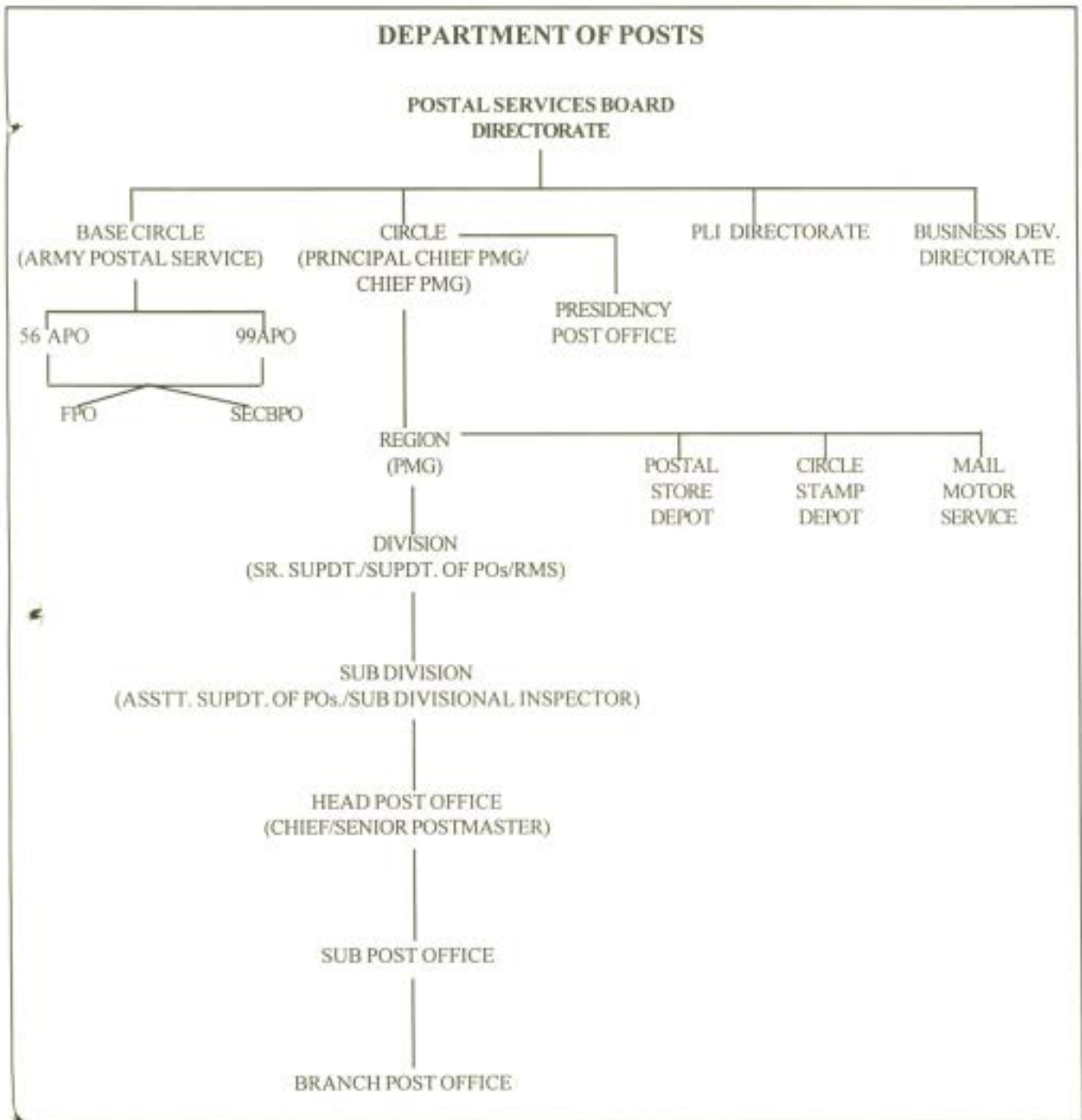
ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF POSTS

MINISTER FOR COMMUNICATIONS
MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS

SECRETARY







अध्याय-3

डाक प्रचालन

डाक नेटवर्क

3.1 भारत के डाकघरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 23,344 डाकघर थे जिनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों में और चुनिंदा गांवों में ही चल रहे थे। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार इस डाक नेटवर्क में अब 1,54,551 डाकघर हो गए हैं जिनमें से 1,38,149 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। एक डाकघर औसतन 21.26 वर्ग किलोमीटर तथा 5,462 की जनसंख्या को सेवा उपलब्ध करा रहा है।

3.2 डाक के माध्यम से लोगों को परस्पर जोड़ना सरकार की अत्यन्त उच्च प्राथमिकता वाली सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी है जिसे प्रदान करने के लिए विभाग पूर्णतया समर्पित है। देश में डाक नेटवर्क की सुविधा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्यतया अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है। तथापि, हाल के वर्षों में दूर-दराज के तथा ऐसे दूरवर्ती क्षेत्रों, जहां अभी भी डाकघर नहीं हैं, के लोगों को मूलभूत डाक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से "पंचायत संचार सेवा योजना" नामक एक स्कीम की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के तहत, कुछ मूलभूत डाक सुविधाएं प्रदान करने जैसे डाक टिकटों, डाक लेखन सामग्री की बिक्री, पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग और पंचायत संचार सेवा केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से डाक के वितरण के लिए पंचायत संचार सेवा केन्द्र एक नोडल केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय दोनों ने यह सिफारिश की है कि विभाग को अतिरिक्त विभागीय डाकघर की स्कीम के स्थान पर पंचायत संचार सेवा योजना की स्कीम चालू करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि नई प्रणाली से कम लागत पर और शक्तियों को केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरित करने की संवैधानिक स्कीम के अनुरूप डाक सेवाओं को और भी दूर-दूर तक मुलभ करना सुनिश्चित हो जाएगा।

3.3 "डाक नेटवर्क का विस्तार" योजना स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए हैं :-

(क) उन गांवों, अधिमानतः ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई.डी.बी.ओ.) खोलना, जहां फिलहाल कोई डाकघर नहीं है तथा जहां निर्धारित मानदंडों के आधार पर डाकघर खोलने का

औचित्य है बशर्ते कि लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध हों। पहाड़ी, जन-जातीय और दुर्गम क्षेत्रों में डाकघर खोलने पर विशेष बल दिया जाता है।

(ख) उन स्थानों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप-डाकघर करना जहां ऐसा करना औचित्यपूर्ण हो। इसके साथ-साथ निर्धारित मानदंडों के आधार पर शहरों, सेटेलाइट टाउनशिप आदि के नए विकसित क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा बशर्ते कि लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध हों।

3.4 1999-2000 अर्थात् नौवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष के दौरान देश भर में कुल 386 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 49 विभागीय उप डाकघर खोले गए। इसके अतिरिक्त 486 पंचायत संचार सेवा केन्द्र भी खोले गए थे। वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, 50 विभागीय उप डाकघर और 2000 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डाक सेवाएं

3.5 डाकघर में डाक प्रचालनों में अन्य सेवाओं के साथ-साथ निम्नलिखित मूल डाक सेवाओं का समूचा क्षेत्र शामिल है :-

- डाक टिकट तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री।
- पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग।
- बीमाकृत वस्तुओं की बुकिंग।
- मूल्यदेय वस्तुओं की बुकिंग।
- मनीआर्डर और पोस्टल आर्डरों के माध्यम से धन-प्रेषण तथा
- पार्सलों की बुकिंग।

3.6 परंपरागत रूप से ये सेवाएं मैनुअल कार्डटों पर प्रदान की जा रही थीं। तथापि ग्राहकों को प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब कार्डटर प्रचालनों को उत्तरोत्तर रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि एक ही खिड़की से अधिकाधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकें जिससे सेवाएं अधिक अनुकूल हों और उनमें गलती की संभावना भी कम हो। इस समय कम्प्यूटरीकृत कार्डटों पर प्रतिमाह सत्र लाख से भी अधिक लेन-देन किए जा रहे हैं। मनीआर्डर अब



Chapter 3

POSTAL OPERATIONS

Postal network

3.1 India has the largest number of post offices in the world. At the time of the independence there were 23,344 post offices in the country largely confined to the urban areas and selected villages. This network has now grown to 1,54,551 post offices as on 31.3.2000, including 1,38,149 post offices in rural areas. On an average, a post office serves an area of 21.26 sq. km. and a population of 5,462.

3.2 Postal connectivity is a high priority socio-economic responsibility of the Government, which the Department is fully committed to provide. Postal network in the country, specially in rural areas, has been mainly provided through a system of extra-departmental branch post offices. However, in recent years, in order to provide basic postal facilities to people in far flung and remote areas which are still without a post office, a scheme called "Panchayat Sanchar Sewa Yojana" has been introduced. Under this arrangement, Panchayat Sanchar Kendras serve as nodal point for retailing some basic postal facilities like sale of stamps, postal stationery, booking of registered articles and delivery of mails through a network of Panchayat Sanchar Sewa Kendras (PSSK). Both, Planning Commission and Ministry of Finance, have recommended that Department should consider replacing the Extra Departmental Post Office Scheme by Panchayat Sanchar Sewa Yojana, since the new approach would ensure greater access to postal services at lesser cost and in conformity with constitutional scheme of devolution of power from the Centre to the States.

3.3 The following activities have been undertaken under the Plan Scheme "Expansion of postal network":-

(a) Opening of Extra Departmental Branch Post Offices (EDBOs) in villages, preferably Gram Panchayat Headquarter villages, where no post office exists at present and where such a post office is justified on the basis of prescribed

norms, subject to availability of resources. Special emphasis is laid on opening post offices in hilly, tribal and inaccessible areas.

(b) Upgradation of EDBOs into Departmental Sub Post Offices (DSOs), wherever justified with particular emphasis on newly developed areas of the cities, satellite townships etc. on the basis of prescribed norms, subject to availability of resources.

3.4 During 1999-2000, the third year of the 9th Five Year Plan, 386 EDBOs and 49 DSOs were opened throughout the country. In addition, 486 Panchayat Sanchar Sewa Kendras were also opened. A target for opening 500 EDBOs, 50 DSOs and 2000 Panchayat Sanchar Kendras has been set for the Annual Plan 2000-2001.

Postal Services

3.5 Postal operations at the post office encompass the entire gamut of the basic postal services which inter alia include:

- (i) Sale of stamps and stationery,
- (ii) Booking of registered articles,
- (iii) Booking of insured articles,
- (iv) Booking of value payable articles,
- (v) Remittance of money through money orders and postal orders and
- (vi) Booking of Parcels

3.6 Traditionally, these services were being provided at manually operated counters. Considering, however, the vital need for providing the benefit of technology to the customers, the counter operations are now being progressively computerised to provide a greater range of service from a single window leading to services being more responsive and error free. At present, more than seventy lakh transactions are being carried out at the computerised counters every month. Money orders are now being transmitted via satellite communication system providing utmost speed in transmission, at no extra cost to the customers. Already 12% of the total money order service has

उपग्रह प्रेषण व्यवस्था से भेजे जा रहे हैं जिससे ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त कीमत के प्रेषण कान्ते जल्दी हो रहा है। कुल मनीआर्डर का 12% पहले ही उपग्रह व्यवस्था में डाल दिया गया तथा अगले वित्तीय वर्ष तक पूरी मनीआर्डर सेवा इसके अंतर्गत आने को उम्मीद है। वर्ष के दौरान मनीआर्डर परियात तेजी से बढ़ा है।

3.7 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान मनीआर्डर परियात तथा उनका संबंधित मूल्य नीचे तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका - 1			
मनीआर्डर परियात तथा प्रेषित मनीआर्डरों का मूल्य			
वर्ष	1998-99	1999-2000	वृद्धि/कमी
1. मनीआर्डर परियात (संख्या करोड़ में)	10.91	11.37	(+) 4.22 %
2. प्रेषित मनीआर्डरों का मूल्य (करोड़ रुपए में)	4829.86	5707.94	(+) 18.18 %

डाक प्रचालन

3.8 मेल प्रोसेसिंग, पारेषण तथा वितरण विभाग के प्रमुख कार्यकलाप हैं। देश में 5.81 लाख लेटर बाक्सों से पत्र एकत्रित किए जाते हैं। इन्हें 573 रेल डाक सेवा (आर.एम.एस.) कार्यालयों के नेटवर्क द्वारा प्रोसेस किया जाता है तथा रेलों,

एयरलाइनों, सड़क परिवहन द्वारा देशभर में प्रेषित किया जाता है।

डाक परिमाण

3.9 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान डाक परियात तालिका-2 के अनुसार रहा।

तालिका - 2			
डाक परियात (करोड़ में)			
वर्ष	1998-99	1999-2000	वृद्धि/कमी
1. पंजीकृत वस्तुएं	26.82	27.59	(+) 2.87 %
2. अपंजीकृत वस्तुएं	1549.83	1550.56	(+) 0.05 %
3. कुल (1+2)	1576.65	1578.15	(+) 0.09 %

डाक प्रबंधन

3.10 देशभर में अत्यधिक प्रभावी और अधिकतम कुशल डाक पारेषण नेटवर्क स्थापित करने की योजनाओं को व्यावहारिक रूप से लागू किया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभाग ने डाक परियात के विभिन्न भागों का पता लगाया है और प्रत्येक भाग के लिए परियात के निपटान का विशिष्ट तरीका निश्चित किया है। इस प्रकार महानगरों के बीच की डाक के लिए मेट्रो चैनल, राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों के बीच तथा इसके विपरीत के लिए राजधानी चैनल, स्थानीय डाक के लिए ग्रीन चैनल, धोक डाक के लिए बिजनेस चैनल और समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए पत्रिका चैनल जैसे विशिष्ट चैनल बनाए गए हैं।

3.11 दीपावली, क्रिसमस, रक्षाबंधन तथा नववर्ष जैसे फेस्टिवल सीजन के दौरान डाक की मात्रा में होने वाली आकस्मिक वृद्धि से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रमुख शहरों में लोगों को उनके पत्र सीधे गंतव्य थैलों में डालने के लिए आमंत्रित किया गया था।

डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण

3.12 विभाग ने डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण की एक नीति प्रारंभ की है। डाक कार्यालयों के आधुनिकीकरण का

been transferred to satellite system and by the next financial year the entire money order service is expected to be covered by this system. There has been rise in the money order traffic during the year.

3.7 Compared to the previous year, the Money Order traffic and the value of Money Order transmitted during 1999-2000 are as given in Table 1.

	1998-99	1999-2000	Increase/Decrease
1. Money Order traffic (Numbers in crores)	10.91	11.37	(+)4.22%
2. Value of MOs transmitted(Rs. in crores)	4829.86	5707.94	(+) 18.18%

MAIL OPERATIONS

3.8 Mail processing, transmission and delivery are the core activities of the Department. The letters are collected from 5.81 lakh letter boxes in the country. These are processed by a network of 573 Railway

Mail Service (RMS) Offices, and conveyed by trains, airlines, and road transport, all over the country.

Mail Volume

3.9 The mail traffic handled during 1999-2000, compared to previous year, is as given in Table 2.

YEAR	1998-99	1999-2000	Increase/Decrease
1. Registered Articles	26.82	27.59	(+) 2.87%
2. Unregistered Articles	1549.83	1550.56	(+) 0.05%
3. Total (1+2)	1576.65	1578.15	(+) 0.09%

Mail Management

3.10. Plans for achieving an efficient mail transmission network throughout the country have been put into effect. With this objective in view, the Department has identified different segments of mail traffic and has devised exclusive handling for each segment. Thus, there are specialised channels like Metro Channel for mail between metro cities, Rajdhani Channel for mail between the national capital and the state capitals and vice-versa, Green Channel for local mail, Business Channel for bulk mail and Patrika Channel for newspapers and periodicals.

3.11 Special arrangements to meet the sudden spurt

in traffic during festival season like Diwali, X-Mas, Raksha Bandhan and New Year were made. In major towns, sorting trays were provided for the members of the public to post their letters directly into the bags for destination to speed up delivery to the addressees.

Modernisation and Computerisation of Mail Operations

3.12 In order to expedite transmission, processing and delivery of mail, the Department has embarked on a policy of computerisation and modernisation of the mail transmission, processing and delivery in mail offices. The modernisation of mail offices aims at pro-

उद्देश्य डाक कार्यालयों में बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना और बेहतर कार्य के वातावरण का निर्माण करना है।

3.13 लेखादेय मदों जैसे पंजीकृत पत्रों, बीमाकृत मदों आदि की छंटवाई को इन मदों के त्वरित निपटान एवं सुरक्षा के उद्देश्य से और शिकायतों/पूछताछ के मामले में शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

3.14 ट्रांजिट मेल आफिस (टी.एम.ओ.), विशेष रूप से बड़े

शहरों में हवाई अड्डों पर, डाक के पारेषण का महत्वपूर्ण चरण होते हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान 6 अन्य टी.एम.ओ. का कम्प्यूटरीकरण किया गया जिससे कुल कम्प्यूटरीकृत टी.एम.ओ. 20 हो गए हैं। समग्र योजना यह है कि मेल प्रोसेसिंग के इन विभिन्न चरणों के बीच संबद्धता स्थापित की जा सके ताकि एक बार जिस वस्तु की प्रविष्टि कर दी जाए उसे दुबारा विभिन्न चरणों में प्रविष्टि करने की आवश्यकता न पड़े। इस संबंध में उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं :-

तालिका - 3						
आधुनिकीकृत और कम्प्यूटरीकृत किए गए कार्यालय						
कार्यकलाप	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	कुल
1. मेल आफिसों का आधुनिकीकरण	22	26	21	43	38	150
2. रजिस्ट्रेशन सार्टिंग का कम्प्यूटरीकरण	4	10	14	22	6	56
3. ट्रांजिट मेल आफिसों का कम्प्यूटरीकरण	-	2	6	6	6	20

रेलवे मेल सेवा नेटवर्क का विस्तार

3.15 डाक के प्रेषण और त्वरित वितरण से संबंधित व्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्नलिखित गाड़ियों में ट्रांजिट सेक्शन स्थापित किए गए हैं :-

- (क) गोवा एक्सप्रेस
- (ख) नेत्रवती एक्सप्रेस
- (ग) कमला गंगा इंटर सिटी फास्ट पैसेन्जर
- (घ) धनबाद से रांची तक मौर्य एक्सप्रेस में आरएमएस सेक्शन की बीट का विस्तार

3.16 वैशाली जिले और गोवा क्षेत्र के लिए डाक प्रेषण में तीव्रता लाने के प्रयोजन से क्रमशः हाजीपुर और मडगांव में नए मेल कार्यालय खोले गए हैं।

3.17 विभाग ने डाक के सुव्यवस्थित वहन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे के माध्यम से एयर ब्रेक सिस्टम वाली 28 नई आरएमएस मेल वैन प्राप्त कीं।

मेल मोटर सेवा (एम एम एस)

3.18 मेल मोटर सेवा संगठन विभाग के मेल मोटर वाहनों, निरीक्षण वाहनों और स्टाफ कारों के रखरखाव, प्रचालन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। मेल मोटर सेवा 94 स्टेशनों में चलती है। इनमें से 17 स्टेशनों पर बड़े मरम्मत कार्य और रख-रखाव कार्य करने के लिए पूर्ण विकसित वर्कशाप सुविधाएं उपलब्ध हैं।

3.19 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार विभागीय वाहनों की संख्या 1611 थी।

3.20 वर्ष 1999-2000 के दौरान एम.एम.एस. वाहनों ने डाक प्रेषित करने के लिए 2.36 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की जो गत वर्ष की तुलना में 12,000 किलोमीटर अधिक है। इस अवधि के दौरान एम.एम.एस. पर 38.75 करोड़ रुपये का कुल व्यय हुआ।

3.21 सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए घोषित उपायों को ध्यान में रखकर प्राप्त किए गए 6 नए वाहनों को इस क्षेत्र में लंबे मार्गों पर चलाने के लिए आपूर्ति की गई जहां परिवहन के विश्वसनीय और वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं थे।

viding better equipment and improved work environment in the Mail Offices.

3.13 Sorting of accountable articles like registered letters, insured articles, etc. has been computerised for speedy and safe handling of these articles and more expeditious response in case of complaints/enquiries.

3.14 The Transit Mail Offices (TMOs) especially

at the airports in big cities, are crucial stages in the transmission of mail. During 1999-2000, 6 TMOs have been computerised bringing the total of computerised TMOs to 20. The overall plan is to establish connectivity between different stages of mail processing so that data about an article keyed in once, need not be entered again at various stages.

The following have been the achievement in this regard so far.

Table 3
MAIL OFFICES MODERNISED AND COMPUTERISED

Activity	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	Total
1. Modernisation of Mail Offices	22	26	21	43	38	150
2. Computerisation of Registration Sorting	4	10	14	22	6	56
3. Computerisation of Transit Mail Offices	-	2	6	6	6	20

Expansion of Railway Mail Service Network

3.15 In order to improve arrangements relating to the transmission and delivery of mails, Transit Sections have been introduced in the following trains:

- a) Goa Express
- b) Netravati Express
- c) Kamala Ganga Intercity Fast Passenger
- d) Extension of beat of RMS Section in Maurya Express upto Ranchi from Dhanbad.

3.16 New Mail Offices have been opened at Hajipur and Madgaon to expedite the mail transmission for Vaishali district and Goa region respectively.

3.17 The Department got 28 new RMS Mail Vans with Air-brake system manufactured through the Indian Railways to ensure smooth conveyance of mails.

MAIL MOTOR SERVICE (MMS)

3.18 The Mail Motor Service Organization is responsible for maintenance, operations and administration of mail motor vehicles, inspection vehicles and staff cars of the Department. MMS operates at 94 stations. Full-fledged workshop facilities for undertaking major repairs and maintenance are available at 17 of these stations.

3.19 The strength of departmental vehicles was 1611 as on March 31, 2000.

3.20 The MMS vehicles covered 2.36 crores KMs for conveying mails during 1999-2000 which is 12,000 KMs more than the previous year. A total expenditure of Rs.38.75 crores was incurred on MMS during this period.

3.21 Keeping in view the initiatives announced by the Government for the North-Eastern Region, 6 new vehicles were procured and supplied in this region for running on long routes where reliable and alternate means of transport were not available.

एमएमएस वाहनों के श्रेष्ठतम उपयोग पर अध्ययन

3.22 मेल मोटर सेवाओं को युक्तियुक्त बनाने और उसका श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मुंबई और कोलकता में एक अध्ययन किया। अध्ययन के आधार पर की गई सिफारिशों को लागू कर दिया गया है जिससे डाक का तीव्र प्रेषण और वितरण सुनिश्चित हुआ है। एमएमएस सारणियों को युक्तिसंगत बनाने में मदद मिली है तथा इन सारणियों को चलाने से लागत में कमी आई है।

सामग्री प्रबंधन

3.23 निदेशालय के सामग्री प्रबंधन डिवाजन को देश भर में डाक नेटवर्क के कार्यकरण के लिए आवश्यक सामग्री, प्रपत्र और उपकरण उपलब्ध कराने, उनकी मानीटरिंग तथा आपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अनेक प्रकार के डाक बैले, लेटर बाक्स, वर्दी की मर्दे, कागज तथा अन्य आधारभूत उपकरण या तो सामग्री प्रबंधन डिवाजन द्वारा सीधे प्राप्त और मुहैया कराए जाते हैं अथवा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की एजेंसियों के माध्यम से इनकी आपूर्ति की जाती है। तथापि वर्ष के दौरान कई प्रापण कार्य सर्किलों को विकेंद्रित कर दिए गए हैं जैसे वर्दी, छाता, जूट और सूती ट्वाइन तथा पोस्ट-बाक्स कैबिनेट। इसका उद्देश्य निदेशालय में सामग्री प्रबंधन डिवाजनों को पूरी तरह से पालिसी निर्धारण डेस्क के तौर पर पुनर्गठित करना है। डाकघरों को यह आपूर्ति 46 पोस्टल स्टोर डिपो (पी.एस.डी.) तथा 5 रीजनल फार्म डिपो (आर.एफ.डी.) के माध्यम से की जाती है। ये डिपो उन डाक सर्किलों के अध्यक्षों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं जहां ये स्थित होते हैं। इन डिपो के अतिरिक्त भुवनेश्वर में एक डाक मुद्रण प्रेस है।

3.24 बेहतर इन-हाउस सुविधाएं प्रदान करने के लिए पी.एस.डी. / आर.एफ.डी. को मशीनरी और उपकरण की आपूर्ति की जाती है। विभाग द्वारा 46 पोस्टल स्टोर डिपो के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया है ताकि उनका प्रभावी सामान सूची (इन्वेंटरी) नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

फिलैटली

3.25 फिलैटली विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप बना रहा। विशेष डाक-टिकट जारी किए जाने के माध्यम से अनेक

महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया गया। 1.4.1999 से 31.3.2000 की अवधि के दौरान तिहत्तर (73) स्मारक / विशेष डाक टिकट जारी किए गए।

3.26 विभाग ने नई सहस्राब्दि के प्रथम सूर्योदय के अवसर पर कच्छल, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एक डाक टिकट जारी किया जहां सूर्य की प्रथम किरण ने स्पर्श किया।

3.27 वर्ष के दौरान विभाग ने कला और संस्कृति, वनस्पति और जीव-जन्तुओं, आदि पर भी सुंदर डाक-टिकट जारी किए। विभाग द्वारा डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया जिस पर विश्व प्रकृति निधि (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) का प्रतीक चिह्न चित्रित किया गया है जो कि विश्व प्रकृति निधि, संरक्षण का एक हिस्सा है। भारत को समृद्ध विरासत को उजागर करते हुए और विश्व प्रेम और सौहार्द के संदेश का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से "ताबो गोम्या" पर भी एक डाक टिकट सहस्राब्दि डाक टिकट के रूप में जारी किया गया।

3.28 वर्ष के दौरान डाक लेखन सामग्री जैसे पोस्टकार्डों, अंतर्देशीय पत्र कार्डों, लिफाफों, पंजीकृत लिफाफों और एरोग्राम, जिनपर विज्ञापन जनता को जागरूक करने वाले उद्धरण और संदेश आदि अंग्रेजी-हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे थे, का अभिनव प्रयोग किया जाता रहा।

3.29 देश भर में 54 फिलैटली ब्यूरो और 205 फिलैटली कार्टटों के माध्यम से फिलैटली की वस्तुओं का विक्रय किया गया।

3.30 वर्ष 1998 में विभाग द्वारा जारी सर्वाधिक लोकप्रिय डाक टिकटों का चयन करने के लिए विभाग द्वारा 8 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के स्कूली बच्चों के बीच एक डाक टिकट लोकप्रियता मतसंग्रह कराया गया था। देश भर से लगभग 22000 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। 1998 के तीन सर्वाधिक लोकप्रिय डाक टिकटों के लिए क्रमशः महात्मा गांधी, बाल दिवस और एयर इंडिया-अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की स्वर्ण जयंती पर जारी किए गए डाक टिकटों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्रदान किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय सर्वाधिक लोकप्रिय विषय के रूप में उभरा।

3.31 वर्ष के दौरान निम्नलिखित सर्किल / राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित की गईं :

Study on Optimisation of MMS Vehicles

3.22 A study was conducted to rationalise and optimise the mail motor services in Mumbai and Kolkata by the Indian Institute of Technology. The recommendations of the study have been implemented which has resulted in speedy transmission and delivery of mails and rationalization of MMS schedules and cost saving in running of these schedules.

MATERIAL MANAGEMENT

3.23 Material Management (MM) Division of the Directorate is entrusted with the responsibility of procuring monitoring and supplying material, forms and equipments required for the functioning of the postal network, throughout the country. A large variety of postal bags, letter boxes, uniform items, paper and other infrastructural equipment is either procured and supplied directly by Material Management Division or through the agencies of the Directorate General of Supply and Disposal. However, during the year many procurement function have been decentralised to the circles like procurement of uniform, umbrellas, jute and cotton twine and post box cabinets. The aim is to restructure Material Management Divisions in the Directorate into a purely policy making desk. The supply of stores to post offices is done through 46 Postal Store Depots (PSDs) and 5 Regional Form Depots (RFDs) These Depots work under the administrative control of Heads of Postal Circles in whose jurisdiction they are located. Apart from these Depots, there is a Postal Printing Press at Bhubaneswar.

3.24 For providing better in-house facilities, machinery and equipment is supplied to PSDs/RFDs computerisation of 46 Postal Store Depots has been undertaken by the Department so as to ensure effective inventory control.

PHILATELY

3.25 Philately continued to remain an important activity of the Department. Many significant events

were commemorated by issue of special stamps. During the period from 1.4.99 to 31.3.2000, Seventy three (73) commemorative/special stamps were issued.

3.26 A stamp to commemorate the new millennium was issued at Katchal, Andaman and Nicobar Islands where the first sun ray of the century touched the earth.

3.27 During the year, the Department also released beautiful stamps on art and culture, flora and fauna, heritages, etc. A set of stamps carrying the World Wide Fund for Nature (WWF) logo 'The World Wide Fund for Nature' was released by the Department. To celebrate India's rich heritage and to propagate the message of universal love and harmony, a stamp was issued on "Tabo Monastery" as the Millennium Issue.

3.28 The innovative use of postal stationery i.e. Post Cards, Inland Letter Cards, Envelopes, Registered Envelopes and Aerograms carrying advertisement, public awareness quotations, messages, etc. in English, Hindi as well as regional languages continued during the year.

3.29 Sale of philatelic items was carried out all over the country through 54 Philatelic Bureaux and 205 Philatelic Counters.

3.30 A stamp popularity poll was organized by the Department for selecting the most popular stamps issued by the Department in the year 1998 amongst school children between the age group of 8 to 12 years. About 22,000 entries were received from all over the country. For the three most popular stamps of 1998, 1st, 11nd and 111rd ranks were given for the stamps on Mahatma Gandhi, Children's Day and Air India - Golden Jubilee International Flight respectively. The theme of 'Science and Technology' emerged as most popular theme.

3.31 The following Circle/State level Exhibitions were held during the year:-

क्र.सं.	प्रदर्शनी का नाम	स्थान	अवधि
1.	केरापेक्स '99	कोट्टायम	26.11.1999 से 28.11.1999
2.	पनपेक्स '99	तुधियाना	24.12.1999 से 26.12.1999
3.	कनपेक्स '2000	बेंगलूर	07.01.2000 से 09.01.2000
4.	बाईपेक्स '2000	पटना	14.01.2000 से 17.01.2000
5.	मिल्लोपेक्स '2000	भुवनेश्वर	29.01.2000 से 02.02.2000
6.	क्षेत्रीय फिलैटली प्रदर्शनी (अपने किस्म की प्रथम)	गोरखपुर	12.02.2000 से 14.02.2000

3.32 श्री बी.एन. सोम तत्कालीन सदस्य (प्रचालन) ने क्रम संख्या 1, 5 और 6 पर सूचित प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया तथा अन्य प्रदर्शनियों में पुरस्कार दिया। वे बाईपैक्स 2000 में उपस्थित नहीं हो पाए। एक लंबे अंतराल के बाद देश में कई

स्थानों पर फिलैटली प्रदर्शनियां आम लोगों के बीच आयोजित की गईं जिसके कारण युवा वर्ग और आम जनता में जीवन्त रुचि की उन्नति में एक नया अध्याय शुरू हुआ।



S.No	Name of the Exhibition	Place	Duration
1.	KERAPEX'99	Kottayam	26.11.1999 to 28.11.1999
2.	PUNPEX'99	Ludhiana	24.12.1999 to 26.12.1999
3.	Karnapex'2000	Bangalore	07.01.2000 to 09.01.2000
4.	BIPEX'2000	Patna	14.01.2000 to 17.01.2000
5.	Millepex'2000	Bhubaneshwar	29.01.2000 to 02.02.2000
6.	Regional Philatelic Exhibition (First of its kind)	Gorakhpur	12.02.2000 to 14.02.2000

3.32 Shri B.N. Som, the then Member(O) inaugurated the exhibition listed at Sr.Nos.1,5 & 6 and gave away prizes at the other exhibitions. He could not attend BIPEX-2000. After a long interval, so

many philatelic exhibitions were organised around the country going to the grass root, heralding a new era in the promotion of this lovely hobby among the youth and the general public

अध्याय-4

व्यवसाय विकास कार्यकलाप

4.1 विभाग के मूल्यवर्धित प्रीमियम उत्पादों के डिजाइन तैयार करने, विकास करने और उनका विपणन करने के लिए व्यवसाय विकास निदेशालय की 1996 में स्थापना की गई। व्यवसाय विकास निदेशालय के उत्तरदायित्व इस प्रकार है :

- मौजूदा मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं का विस्तार तथा संवर्धन;
- नए मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं का अभिकल्पन एवं प्रवर्तन ;
- इनकी रिटेलिंग और नेटवर्किंग के लिए प्रक्रियाओं, विनियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करना;
- बाजार अध्ययन, बाजार परीक्षण तथा उत्पाद-परिष्कार;
- बाजार-नीतियों, गठजोड़ों और सहयोग का विकास;
- कार्मिक-प्रशिक्षण;
- मूल्यवर्धित उत्पादों तथा सेवाओं की मॉनीटरिंग तथा पुनरीक्षा;

4.2 व्यवसाय विकास निदेशालय निम्नलिखित उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन करता है :

- (क) स्पीड पोस्ट
- (ख) बिजनेस पोस्ट
- (ग) मीडिया पोस्ट
- (घ) उपग्रह डाक
- (ङ) एक्सप्रेस पार्सल डाक
- (च) रीटेल डाक

कारोबार में वृद्धि

4.3 व्यवसाय विकास दल द्वारा उठाए गए नए कदमों के परिणाम-स्वरूप 1999-2000 में राजस्व बढ़कर 222 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 1998-99 में यह 141.76 करोड़ रुपये था। प्रत्येक उत्पाद के संदर्भ में राजस्व में हुई बढ़ोतरी तालिका-4 में दर्शाई गई है।

तालिका - 4			
व्यवसाय विकास कार्यकलापों की उत्पादवार राजस्व वृद्धि			
उत्पाद	1998-99 में राजस्व (करोड़ में)	1999-2000 में राजस्व (करोड़ में)	% वृद्धि
स्पीड पोस्ट	91.36	126.17	38.10
बिजनेस पोस्ट	43.71	84.92	94.28
मीडिया पोस्ट	5.52	5.78	4.71
एक्सप्रेस पोस्ट	0.55	3.56	547.27
उपग्रह डाक	0.06	0.06	-
रीटेल पोस्ट	0.56	0.69	23.21
अन्य कारोबारी सेवाएं	-	1.26	-
कुल	141.76	222.44	56.91

स्पीड पोस्ट

4.4 त्वरित एवं समयबद्ध वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए, सात मेट्रो नगरों को जोड़ते हुए 1986 में स्पीड पोस्ट सेवाएं शुरू की गई थीं। आज स्पीड पोस्ट के नेटवर्क के अंतर्गत घरेलू नेटवर्क भारत में 108 प्रमुख शहरों से तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क 97 देशों

से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्पीड पोस्ट नेटवर्क में 700 से अधिक शहर तथा जिला मुख्यालय जुड़े हुए हैं जहां से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थानों के लिए स्पीड पोस्ट वस्तुएं बुक की जा सकती हैं।

4.5 स्पीड पोस्ट ग्राहकों को पूरे देश तथा समूची दुनिया में पत्रों,



Chapter 4

BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES

4.1 Business Development Directorate was set up in 1996 to design, develop and market value-added premium products of the Department. The responsibilities of the Business Development Directorate are enumerated as follows:

- Expansion and promotion of the existing value added products and services;
- Designing & launching of new value added products and services;
- Set up procedures, regulations and guidelines for their retailing and networking;
- Market study, market testing and product improvement;
- Market strategies, alliances and cooperation;
- Training for personnel;
- Monitoring and reviewing of growth of value added products and services;

4.2 The Business Development Directorate is presently marketing the following products and services:

- (a) Speed Post
- (b) Business Post
- (c) Media Post
- (d) Satellite Post
- (e) Express Parcel Post
- (f) Retail Post

Business Growth

4.3 As a result of new initiatives taken by the Business Development Group, the revenue increased to Rs. 222 crores in 1999-2000, as compared to Rs. 141.76 crores in 1998-99. The revenue growth in respect of each product is given in the Table-4.

Table 4
PRODUCT-WISE REVENUE GROWTH OF BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES

Product	Revenue in 1998-99 (In crores)	Revenue in 1999-2000 (In crores)	% of Increase
Speed Post	91.36	126.17	38.10
Business Post	43.71	84.92	94.28
Media Post	5.52	5.78	4.71
Express Post	0.55	3.56	547.27
Satellite Post	0.06	0.06	-
Retail Post	0.56	0.69	23.21
Other Business Services	-	1.26	-
Total	141.76	222.44	56.91

Speed Post

4.4 Speed Post service was introduced in 1986, linking seven metro cities, with a view to provide fast and time-bound delivery services. As on date, Speed Post has a network linking 108 major towns in India in the domestic network and 97 countries

in the international network. In addition, more than 700 towns and district headquarters are linked in the State speed post network, from where speed post articles can be booked for national and international destinations.

4.5 Speed Post offers the customers time-specific

दस्तावेजों तथा 35 कि.ग्रा. तक के पार्सलों की समयनिष्ठ एवं सुनिश्चित वितरण सेवा उपलब्ध कराता है। केन्द्रों को जोड़ने के लिए उपलब्ध तीव्रतम परिवहन के साधन को ध्यान में रखकर वितरण मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। इसे, व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ एक व्यावसायिक सेवा के तौर पर चलाया जाता है।

4.6 स्पीड पोस्ट ब्रांड के अंतर्गत स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट घरेलू सेवाएं, स्पीड पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, स्पीड पोस्ट मनीआर्डर तथा स्पीड पोस्ट उपहार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्पीड पोस्ट का राजस्व 1998-99 के 91.36 करोड़ रुपये से बढ़कर 1999-2000 में 126.17 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें बहुत हद तक वृद्धि हुई है। कारपोरेट ग्राहकों को अतिविशिष्ट ग्राहकों की हैसियत प्रदान की जाती है जो विभाग को उनके द्वारा दिए जाने वाले व्यवसाय पर आधारित होती है। स्पीड पोस्ट में ग्राहक सेवा तथा वितरण दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

बिजनेस पोस्ट

4.7 बिजनेस पोस्ट, कारोबार करने वाले ग्राहकों को उनकी सुविधा एवं जरूरत के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराकर संपूर्ण कारोबारी समाधान प्रस्तुत करता है। यह संग्रहण, सनिवेशन, पतालेखन, सीलिंग, फ्रिंकिंग आदि के रूप में, डाक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी पारंपरिक सेवाओं का मूल्यवर्धन करता है। ज्यादा से ज्यादा कारपोरेट ग्राहक बिजनेस पोस्ट सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि महानगरों तथा शहरों में व्यावसायिक डाक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

4.8 एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट में स्थल परिवहन के माध्यम से पार्सलों को एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जाती है। यह सेवा नए मूल्य परिवर्धन तथा ग्राहक फोकस के साथ मार्च, 1999 में पुनः शुरू की गई। इसमें 35 कि.ग्रा. भार तक के पार्सलों की बुकिंग एवं प्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये सेवाएं कारपोरेट ग्राहकों को संविदात्मक आधार पर, ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती हैं। एक्सप्रेस पोस्ट के कारोबार में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इससे 3.56 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।

मीडिया पोस्ट

4.9 मीडिया पोस्ट कारपोरेट ग्राहकों / सरकारी संगठनों और दूसरे बड़े निजी संस्थानों को डाक स्टेशनरी, डाक वाहनों, पत्र-पेटियों आदि पर उनके उत्पादों / सेवाओं को विज्ञापित करने का

अवसर प्रदान करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इससे 5.78 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।

रीटेल पोस्ट

4.10 समूचे देश में 1,50,000 से अधिक डाकघरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से भारतीय डाक, रीटेल पोस्ट के माध्यम से सरकारी एवं निजी संगठनों के लिए टेलीफोन-बिलों, विद्युत-बिलों को वसूलने का काम करता है।

व्यवसाय विकास दल की नई पहल

व्यावसायिक कार्य नीति

4.11 प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में स्पीड पोस्ट को चलाने के लिए उन स्थानों पर स्पीड पोस्ट केन्द्र संस्थापित किए गए हैं जहां स्पीड पोस्ट का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

- स्पीड पोस्ट प्रचालन
- स्पीड पोस्ट ग्राहक सेवा
- स्पीड पोस्ट विपणन

4.12 इसके अलावा व्यवसाय विकास दल को लेखाकरण प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1999 से एक स्वतंत्र लाभ केन्द्र बनाया गया है। यह व्यवसाय विकास दल को वसूल किए गए राजस्व तथा सेवाओं को चलाने में निहित लागत के बारे में जानने में सक्षम बनाएगा।

ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली उन्नयन परियोजना

4.13 स्पीड पोस्ट ने भारत के आठ शहरों - दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक प्रणाली संस्थापित की है। वर्तमान ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है। इसमें बुकिंग, पैला बनाने, पारेषण, वितरण एवं ग्राहक एकाउंट प्रबंधन माइयूल्स का समावेश किया जा रहा है। जब एक बार इसे कार्यान्वित कर दिया जाता है तो ग्राहक, ग्राहकोन्मुखी प्रोग्राम का इस्तेमाल करके, इंटरनेट के माध्यम से अपने-अपने पारेषणों का पता लगाने में सक्षम हो पाएंगे।

वितरण का मशीनीकरण

4.14 वाहनों के माध्यम से स्पीड पोस्ट वस्तुओं के वितरण ने वितरण में तेजी लाने तथा प्रचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार लाने में विभाग को सक्षम बनाया है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता,

and assured delivery service of letters, documents and parcels upto 35 kg, across the country and around the world. Delivery norms are fixed taking into account the fastest transport available to link the stations. It is managed as a business service with a commercial approach.

4.6 Under the brand Speed Post, Speed Post Domestic services, Speed Post International services, Speed Post Money Orders and Speed Post Gift services are offered. The revenue from Speed Post increased considerably from Rs.91.36 crores in 1998-99 to Rs.126.17 crores in 1999-2000. The corporate customers are given the status of Very Important Customers based on their business value to the Department. Customer service and delivery efficiency are the focus areas in Speed Post.

Business Post

4.7 Business Post offers total business solutions for the business users by providing tailor made services. It provides value addition to all traditional services offered by the Post in the form of collection, inserting, addressing, sealing, franking etc. More and more corporate customers have been using Business Post services, as the business mail continues to grow in the metro cities and towns.

Express Parcel Post

4.8 Express Parcel Post provides express delivery of parcels through ground transportation. The product was re-launched in March, 1999 with new value addition and customer focus. It provides booking and dispatch of parcels weighing upto 35 kg. The services are provided to corporate customers on contractual basis tailoring it to the specific needs of the customer. The business from Express Post has been growing. The revenue during the year 1999-2000 was to the tune of Rs.3.56 crores.

Media Post

4.9 Media Post provides opportunities to corporate customers/Govt. organizations and other large private institutions to have their products/services advertised on the postal stationary, postal vans, letter boxes etc.

The revenue during the year 1999-2000 was to the tune of Rs.5.78 crores.

Retail Post

4.10 Through its vast network of more than 1,50,000 post offices across the country, India Post offers to collect telephone bills, electricity bills, etc. for Govt. and private organizations through Retail Post.

New initiatives of Business Development Group

Business Strategy:

4.11 In order to manage Speed Post in competitive environment, Speed Post Centers have been established where to optimise:

- i) Speed Post operations
- ii) Speed Post customer services
- iii) Speed Post marketing.

4.12 Further, the Business Development Group has been made as an independent Profit centre for accounting purposes effecting from 1st April, 1999. This will enable the Business Development Group to know the revenue realized and the cost incurred for managing the services.

Track and Trace System upgradation project:

4.13 Speed Post has established electronic track system in eight cities in India - Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad and Pune. The existing TATS system is being upgraded, incorporating booking, bagging, transmission, delivery and customer accounts management modules. Once this is implemented, the customers will be able to track their consignments through internet, using a customer friendly program.

Mechanisation of delivery:

4.14 Delivery of Speed Post articles through vehicles has enabled the Department to speed up delivery and improve operational efficiency. Mopeds have been provided to postmen in many towns

चेन्नई तथा बेंगलूर सहित कई शहरों में डाकियों को मोपेड उपलब्ध कराए गए हैं।

स्पीड पोस्ट केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण

4.15 उत्पादकता में वृद्धि करने तथा कार्यकुशल ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी स्पीड पोस्ट केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल के एक भाग के तौर पर राष्ट्रीय नेटवर्क के अधिकांश स्पीड पोस्ट केन्द्रों में कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मोडेम तथा फैक्स मशीन उपलब्ध कराए गए हैं।

बिजनेस पोस्ट केन्द्रों का स्वचलीकरण

4.16 प्री-मेलिंग प्रक्रिया का स्वचलीकरण करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कलकत्ता स्थित बिजनेस पोस्ट केन्द्रों में पायलट परियोजना आधार पर डेस्क टाप मेलिंग तथा सन्निवेशन प्रणालियां मुहैया कराई गई हैं। ये मशीनें लिफाफे में पत्रों को डालेंगी तथा इन्हें तीव्रता से और बेहतर तरीके से सील करेंगी।

स्पीड पोस्ट का स्रोत से एकत्रीकरण

4.17 कार्यकुशल तथा प्रभावी संग्रहण प्रणाली प्रदान करने हेतु कई स्पीड पोस्ट केन्द्रों में स्रोत से संग्रहण शुरू किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कारपोरेट ग्राहकों तथा खुदरा ग्राहकों से स्पीड पोस्ट वस्तुओं का संग्रहण करने हेतु एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। ग्राहकों से परेषणों के संग्रहण के उपरांत एजेंट इन्हें बुकिंग के लिए स्पीड पोस्ट केन्द्र पर लाते हैं। इस

स्कीम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उनके द्वार पर सेवाएं प्रदान करना है।

सेवा की गुणवत्ता

4.18 सेवा की गुणवत्ता, विशेषकर स्पीड पोस्ट परेषणों की डिलीवरी के बारे में, की सभी स्तरों पर मॉनीटरिंग की जाती है। स्वतंत्र बाजार सर्वेक्षण कंपनियों द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों से यह बात सामने आई है कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता तथा चेन्नई में 97% स्पीड पोस्ट वस्तुएं समय पर वितरित की जाती हैं।

विपणन पर बल

4.19 स्पीड पोस्ट तथा अन्य प्रीमियम सेवाओं के संवर्धन के लिए एक विपणन संरचना तैयार की गई है। प्रमुख केन्द्रों में विपणन कार्यपालकों को नए ग्राहकों की खोज करने तथा मौजूदा ग्राहकों की कुशलतापूर्वक सेवा करने का दायित्व सौंपा गया है। स्पीड पोस्ट की तुलना में कुरियरों का निष्पादन, स्पीड पोस्ट के लिए बाजार में संभावनाएं तथा स्पीड पोस्ट के वितरण-निष्पादन पर समय-समय पर बाजार सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं।

बीमा सुविधा

4.20 भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति को ध्यान में रखकर विभाग ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से जेवरों तथा आभूषणों का निर्यात करने पर 1 लाख रुपये तक की बीमा सुविधा प्रदान की है।

including, Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai and Bangalore.

Computerisation of Speed Post centres:

4.15 For increasing productivity and for providing efficient customer service it has been decided to computerize all Speed Post Centres. As a part of this venture, most of the Speed Post Centres in the national network have been provided with computers, scanners, printers, modems and fax machines.

Automation of Business Post Centres:

4.16 Business Post Centers in Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta have been provided with Desk top mailing and inserting systems to automate pre-mailing process on a pilot project basis. These machines will insert the letters into the envelopes and seal them faster and better.

Outsourcing collection of Speed Post:

4.17 Outsourcing has been introduced in many Speed Post Centres to provide efficient and effective collection system. Under the scheme, agents are appointed to collect speed post articles from the corporate customers and retail customers. After collection of the consignments from the customers, agents bring them to Speed Post for booking. The

main objective of the scheme is to providing door-to-door services to the customers.

Quality of Service:

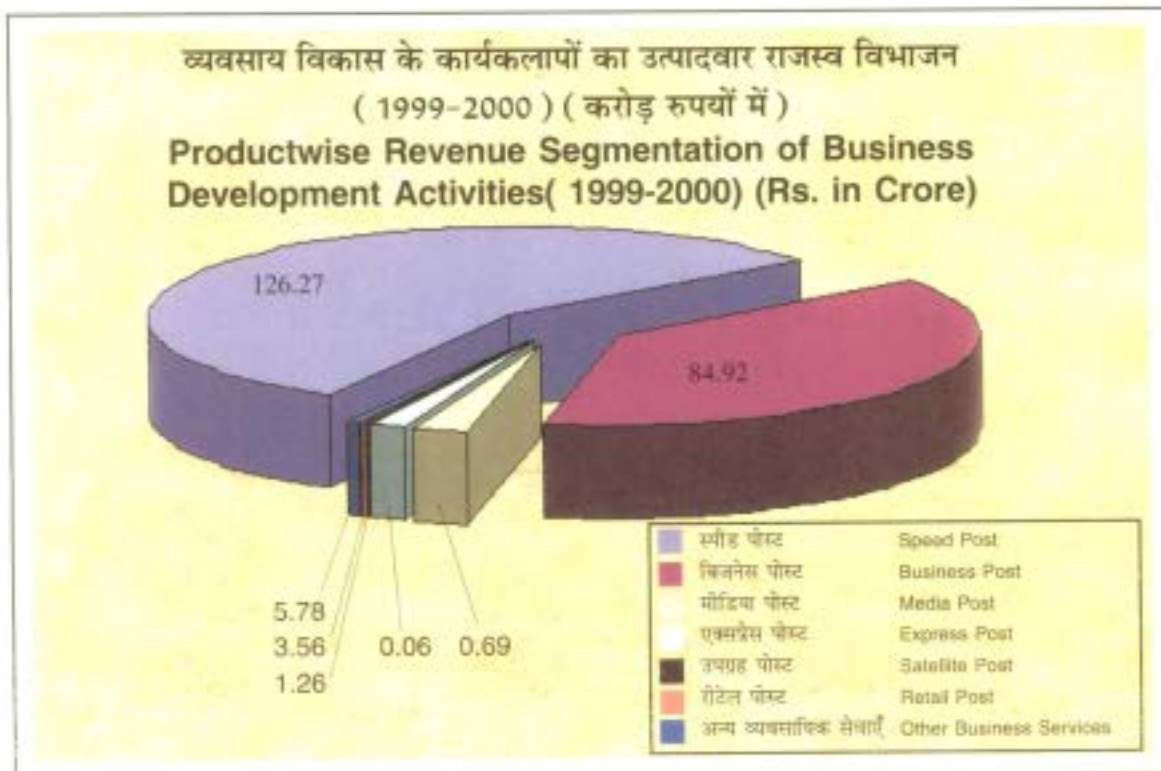
4.18 Quality of service, specially on delivery of speed post consignments, is monitored at all levels. Surveys conducted by independent market survey companies revealed that 97% Speed post articles were delivered on time in Mumbai, Delhi, Calcutta and Chennai.

Thrust on marketing:

4.19 A marketing infrastructure to promote Speed Post and other premium services has been developed. In major centres marketing executives have been entrusted with the task of seeking new customers and services the existing customers efficiently. Market surveys are conducted periodically on the performance of speed post vis-à-vis couriers, market opportunities for speed post and delivery performance of speed post.

Insurance facility:

4.20 In keeping with the Exim Policy of the Government of India, the Department has provided insurance facility upto Rs.1 lakh for export of gems and jewelry through Speed Post.



अध्याय-5

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

5.1 भारत का विश्व के डाक प्रशासनों के धातुसंघ में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 1874 में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सबसे पहले के सदस्यों में से एक है। 1948 में यू.पी.यू. अपने 189 सदस्य देशों को उनकी डाक सेवाएं सुधारने तथा विकसित करने में सहायता करने के लिए एक विशेष एजेंसी बन गई। यू.पी.यू. के चार अंग हैं - अर्थात् कांग्रेस, प्रशासन परिषद् (सी.ए.), डाक प्रचालन परिषद् (पी.ओ.सी.) तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो (आई.बी.)। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस सभी देशों के प्रतिनिधियों को मिलाकर बना है। इसकी बैठक प्रत्येक पांच वर्ष में डाक विधि निर्माण तथा विकास परियोजनाओं के लिए मार्ग-दर्शक नीति निर्धारित करने के लिए होती है। प्रशासन परिषद् तथा डाक प्रचालन परिषद् निर्वाचित निकाय हैं और इनमें क्रमशः 40 तथा 41 सदस्य होते हैं।

5.2 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 22वीं कांग्रेस दिनांक 23 अगस्त से 15 सितम्बर, 1999 तक बीजिंग, जनवादी गणराज्य चीन में आयोजित की गई। कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन संचार राज्य मंत्री श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा किया गया। सचिव (डाक) ने वित्त पर कांग्रेस समिति-2 की बैठक की अध्यक्षता की। प्रशासन परिषद् तथा डाक प्रचालन परिषद् के 22 वें कांग्रेस में भारत का पुनः चयन किया गया। यू.पी.यू. के भावी विकास पर बीजिंग कांग्रेस द्वारा स्थापित 24 सदस्यीय उच्चस्तरीय ग्रुप के लिए भारत को भी नामांकित किया गया। भारत को, प्रशासन परिषद् की तीन समितियों में से एक के लिए अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया।

5.3 डाक प्रचालन परिषद् के 22 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 1999 तक बर्न में आयोजित प्रथम सत्र में भारत ने भी भाग लिया। डाक प्रचालन परिषद् में भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत डाक प्रचालन परिषद् की तीन समितियों का भी सदस्य है, समिति-1 आर्थिक मामले तथा विनियमन, समिति-2 बाजार और समिति-3 प्रचालन तथा सेवा निधि पर तदर्थ गुणवत्ता समिति (क्यू.एस.एफ.) भारत, डाक प्रतिभूति कार्यदल (पी.एस.ए.जी.) सीमांत बकाया कार्यदल (टी.डी.ए.जी.), तकनीकी सहायता कार्यदल (टी.सी.ए.जी.) देयता परियोजना दल, पारगमन पद्धति परियोजना दल, ग्राहक संबंध परियोजना दल, विपणन विकास

परियोजना दल तथा विश्व फिलैटली विकास संघ (डब्ल्यू.ए.डी. पी.) का भी सदस्य है।

5.4 डाक प्रचालन परिषद् के सत्र में मुख्य रूप से पत्र डाक, पार्सल डाक तथा डाक भुगतान सेवा विनियमों तथा उसके निकायों की संरचना व कार्यों को अनुमोदित करने पर बल दिया गया। डाक प्रचालन परिषद् ने बाजार पर स्थापित समिति-2 को विभिन्न डाक बाजारों में होने वाले विकास संबंधी प्रबल प्रबंधन परिवर्तनों के मद्देनजर उन्हें सरल एवं कारगर बनाने के अनुदेश दिए। डाक प्रचालन परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि प्रचालन पर समिति-3 का उद्देश्य, डाक प्रचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उसे अनुकूल बनाने तथा पूरे यूनिवर्सल पोस्टल नेटवर्क के माध्यम से सभी प्रकार के ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित व भरोसेमंद डाक सेवा उपलब्ध कराना होना चाहिए। तदर्थ सेवा गुणवत्ता निधि समिति ने भारत को वित्त प्रबंधन दल के सह-अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। उन्होंने परियोजना प्रबंधन तथा संविधि पर भी दो और दलों का गठन किया है। वित्त प्रबंध दल को वित्तीय प्रबंधन नियम पुस्तिका तैयार करने का काम सौंपा गया। अन्य दो कार्यदलों को परियोजना प्रबंधन नियम पुस्तिका तथा संविधि तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

5.5 भारत ने एशिया प्रशान्त डाक यूनियन (ए.पी.पी.यू.) जो कि एशिया प्रशान्त क्षेत्र 28 देशों की यूनियन है, के मामलों में भी सार्थक भूमिका निभाई। एशिया प्रशान्त डाक प्रशिक्षण केन्द्र शासी बोर्ड की बैठक और एशिया प्रशान्त पोस्टल यूनियन की कार्यकारी परिषद् की बैठक 3 मई से 7 मई, 1999 तक इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में हुई थी। सम्मेलन में 22वें यू.पी.यू. कांग्रेस पर ए.पी.पी.यू. सदस्य देशों द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में बीजिंग कांग्रेस के दौरान प्रस्तावित सीमांत देय प्रणाली तथा मसौदा बीजिंग डाक नीति पर, एकमत निर्णय पर पहुंचने के लिए विस्तारपूर्वक विचार किया गया। व्यवसाय योजना, बजट जैसी विभिन्न डाक सेवाओं के विकास के विभिन्न आयामों संबंधी मामलों, क्षेत्र में विशेष कार्यकलापों, ए.पी.पी.यू. की कार्य योजना, एशियाई प्रशान्त डाक की कार्यकारी तथा क्षेत्रीय सहायता केन्द्र पर भी विचार किया गया।

5.6 अपने निकट के पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की



Chapter 5

INTERNATIONAL RELATIONS

5.1 India has an important place in the fraternity of the postal administrations of the world. India is one of the earliest members of the Universal Postal Union (UPU), established in 1874. In 1948, the UPU became a specialised agency of the United Nations for assisting its 189 member countries in improving and developing their postal services. The UPU has four organs, namely, Congress, Council of Administration (CA), Postal Operations Council (POC) and International Bureau (IB). The Universal Postal Congress, is composed of representatives of all member countries. It meets every five years to lay down policy guidelines for postal legislation and development strategies. The CA and POC are elected bodies and comprise of 40 and 41 Members respectively.

5.2 The 22nd Congress of the Universal Postal Union was held at Beijing, People's Republic of China from 23rd August to 15th September, 1999. A high level Indian delegation led by Shri Kabindra Purkayastha, the then Minister of State for Communications, represented India at the Congress. Secretary(Posts) chaired the meeting of Congress Committee 2 on Finance. At the 22nd Congress, India was re-elected to the Council of Administration and to the Postal Operations Council. India was also nominated to the 24 member High Level Group set up by the Beijing Congress on the future development of UPU. India was also elected as the Chairman of one of the three Committees of the Council of Administration.

5.3 India participated in the first session of the POC held in Berne from 22 November to 1 December 1999. India plays an active role in the POC. India is a member of the three Committees of the POC: Committee 1 on Economic Issues and Regulations, Committee 2 on Markets, Committee 3 on Operation and Ad-hoc Quality of Service Fund (QSF) Committee. India is also a member of Postal Security Action Group (PSAG), Terminal Dues Action Group (TDAG), Technical Co-Operation Action Group (TCAG), Liability Project Team, Transit Systems Project Team,

Customer Relations Project Team, Marketing Development Project Team and World Association for the Development of Philately (WADP).

5.4 The POC session focussed mainly on revising the Letter Post, Parcel Post and Postal Payment Services Regulations as well as approving the structure and functions of its bodies. POC instructed Committee 2 on Markets to facilitate dynamic management of changes in the Post in relation to developments taking place in different postal markets. The POC also decided that the mission of Committee 3 on Operations should be geared to seek excellence in postal operations and to take account of ever intensifying customer demand for secure, reliable postal services throughout the Universal Postal Network. Ad-hoc Quality of Service Fund Committee nominated India as Co-Chairman of Finance Management team. It also formed two more teams on Project Management and Statutes. The financial management team was entrusted with the task of preparing the Financial Management Manual. The other two task teams were entrusted with the task of preparing the Project Management Manual and Statutes.

5.5 India also plays a meaningful role in the affairs of the Asian Pacific Postal Union (APPU), a Union of 28 countries of the Asian and the Pacific region. The Governing Board meeting of the Asian Pacific postal Training Centre and the Executive Council meeting of the Asian Pacific Postal Union were held at Islamabad, Pakistan from 3rd May to 7th May, 1999. The meeting discussed various proposals initiated by APPU member countries for the 22nd UPU Congress. The meeting discussed in detail the newly proposed Terminal Dues System and the draft Beijing Postal Strategy to arrive at a unified stand during the Beijing Congress. The matter relating to various aspects of the development of postal services in the region like Business Plan, Budget, Special Activities in the region, APPU Action Plan, Working of Asia Pacific Post and Regional Support Centre were also discussed.

5.6 With a view to improve relations with its

दृष्टि से भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की संचार तकनीकी समिति (टी.सी.सी.) में भी सक्रिय रुचि दिखाई। सार्क जिसमें भारत सहित सात देश हैं, को दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के लिए गठित किया गया था। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 3-5 मई, 1999 तक आयोजित संचार पर 6वाँ सार्क तकनीकी समिति पर हुए सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया।

5.7 डाक पर भारत-फ्रांस संयुक्त समिति का पहला सम्मेलन 18 से 20 जनवरी, 2000 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में भारत व फ्रांस दोनों ओर से डाटा पोस्ट, फिलैटली सलाहकार संगठन का विकास तथा डाक छंटाई व एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट का विकास जैसे पारस्परिक रुचि के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

5.8 डाक व दूरसंचार पर इंडो-बेलारूस संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक मिंस्क, बेलारूस में 13 से 14 सितम्बर, 1999 तक आयोजित की गई थी। अन्य मुद्दों के साथ-साथ फिलैटली, प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग तथा डाक विनिमय को सरल बनाने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

5.9 भारत ने बीजिंग, चीन जनवादी गणराज्य (16-19 अगस्त, 1999) में आयोजित राष्ट्रमंडल डाक प्रशासन पर प्रौ-कांग्रेस सम्मेलन, टोक्यो, जापान (5 जनवरी - 7 जनवरी, 2000) में संयुक्त राष्ट्र डाक बचत विकास परियोजना की एशियाई क्षेत्र ग्रुप बैठक तथा संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क (3-8 फरवरी, 2000) की डाक बचत विकास परियोजना के पैनल प्रेजेन्टेशन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया।

5.10 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सहायता योजना के अन्तर्गत पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद द्वारा नवम्बर 1999 में दो हफ्ते के लिए "कार्यकारी विकास कार्यक्रम" पर एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत ने बंगलादेश, मालावी, इरेट्रिया, नेपाल, यमन तथा भूटान के सबसे कम विकसित देशों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कोर्स के लिए छह छात्रवृत्तियां प्रदान कीं।

5.11 विभाग के तीन अधिकारियों ने यू.पी.यू. के सलाहकार मिशन में भाग लिया। उन्होंने केन्या, सोलोमान तथा किरिबाटी में बतौर यू.पी.यू. सलाहकार के भाग लिया। इस अवधि के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय डाक विनिमय, फिलैटली तथा

मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास के क्षेत्र में हमारे सलाहकार मिशन चलाने के लिए यू.पी.यू. सलाहकारों को भी आमंत्रित किया।

5.12 वर्ष के दौरान, न्यूजीलैण्ड एशिया प्रशान्त डाक मुख्यालय सिंगापुर तथा स्लोवीनिया के उच्चस्तरीय पदाधिकारियों ने भारत का दौरा किया तथा डाक सेवाओं से संबंधित द्विपक्षीय लाभ के विषयों पर विचार-विमर्श किया।

अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं

5.13 विभाग विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं उपलब्ध कराता है। इनमें त्वरित मेल सेवा (ई.एम.एस.), एयरमेल सेवा, सरफेस एयरलिफ्टेड सेवा (एस.ए.एल.) और सरफेस मेल सेवा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, धन के प्रेषण की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर सेवा, ब्रिटिश पोस्टल आर्डर और आईरिश पोस्टल आर्डर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। विभाग इंटरनेशनल बिजनेस रिप्लाय सर्विस और इंटरनेशनल रिप्लाय कूपन सर्विस भी मुहैया कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय त्वरित मेल सेवा (ई.एम.एस.)

5.14 वर्ष 1986 के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय ई.एम.एस. सेवा शुरू की गई। इंडिया पोस्ट के पास अब 97 देशों के साथ ई.एम.एस. सेवा है। जबकि प्रलेखित सेवा सभी 97 देशों को उपलब्ध है, वाणिज्यिक सेवा केवल 73 देशों को ही उपलब्ध है। पिछले कुछ वर्षों में ई.एम.एस. परियात में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 के दौरान विकास दर 12.1% थी। इस सेवा का गुणवत्ता स्तर बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर समय-समय पर गुणवत्ता परीक्षण का आयोजन किया गया है।

5.15 अन्तर्राष्ट्रीय ई.एम.एस. मर्चें के ट्रेक तथा ट्रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली (आई.पी.एस.) परियोजना का मुम्बई तथा दिल्ली में कार्यान्वयन किया गया। चेन्नई तथा कलकत्ता में भी इस परियोजना का कार्यान्वयन संबंधी प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के पोस्ट नेट नामक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से कार्य करती है।

5.16 अंतर्राष्ट्रीय ई.एम.एस. का परियात तालिका 5 में दिया गया है।

immediate neighbours, India also takes active interest in the Technical Committee on Communications (TCC) of the South Asian Association for the Regional Cooperation (SAARC). The SAARC, which comprises seven countries including India, was set up for regional cooperation in the South Asian Region. India participated in the 6th SAARC Technical Committee on Communication meeting held in Islamabad, Pakistan from 3-5 May, 1999.

5.7 The 1st meeting of Indo-French Joint Committee on Posts was held in New Delhi from 18th to 20th January, 2000. During the meeting presentations were made by the Indian and the French sides on Data Post, Philately, development of consultancy organisation and other subjects of mutual interest like mail processing and development of express parcel post.

5.8 The 1st meeting of the Indo-Belarus Joint working Group on Posts and Telecom was held at Minsk, Belarus from 13-14 September, 1999. Issues relating to Philately, co-operation on technology and streamlining of mail exchanges were discussed among other things.

5.9 India also participated in other international meetings like Pre-Congress Conference of Commonwealth Postal Administrations in Beijing, People's Republic of China, (16-19 August, 1999), Asia Region Group meeting of the United Nations Postal Savings for development project in Tokyo, Japan (5 January - 7 January, 2000) and Panel Presentation of the Postal Savings for Development Project of the United Nations, New York (3rd - 8th Feb., 2000).

5.10 A Course on "Executive Development Programme" was organised at the Postal Staff College of India, Ghaziabad, for two weeks in November, 1999 under the scheme of assistance in kind to the Universal Postal Union (UPU). India granted six fellowships for the training course to participants from least developed countries, Bangladesh, Malawi, Eritrea, Nepal, Yemen and Bhutan.

5.11 Three officers from the Department, took part in the Consultancy Missions of UPU. They participated as UPU consultants in Kenya, Solomon Island and

Kiribati. During the period, India also invited UPU consultants to carry out consultancy missions in the fields of international mail exchange, development of philately and value-added products.

5.12 During the year, high level dignitaries from New Zealand, Asia Pacific Post headquarters at Singapore and Slovenia visited India and matters of bilateral interest relating to Postal Services were discussed.

INTERNATIONAL POSTAL SERVICES

5.13 The Department provides a variety of International Postal Services. These include Expedited Mail Service (EMS), Airmail Service, Surface Air Lifted Service (SAL) and Surface Mail Service. In addition, remittance of money is provided through International Money Order Service, British Postal Orders and the Irish Postal Orders. The Department also provides the International Business Reply Service and the International Reply Coupons Service.

International EMS

5.14 International EMS Service was introduced in India in 1986. India Post now has EMS Service with 97 countries. While document service is available to all 97 countries, merchandise service is available to 73 countries. There has been a consistent growth in the traffic of EMS during the past few years. The growth rate during 1999-2000 was 12.1%. To improve the efficiency level of this service number of quality tests have been undertaken with other countries from time to time.

5.15 International Postal System (IPS) project for the track and trace of International EMS items has been implemented in Mumbai and Delhi. The preliminary work for the implementation of this project at Chennai and Calcutta is also under way. The international postal system operates through Universal Postal Union's Virtual Private Network (VNP) called Post*NET.

5.16 The traffic of international EMS is given in Table 5.

तालिका - 5
अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट-ई.एम.एस. परियात

वर्ष	1998	1999	वृद्धि / कमी
आवक मर्दे	317163	396393	(+) 24.98 %
जावक मर्दे	391983	439425	(+) 12.10 %

पत्र-डाक

5.17 वर्ष 1999-2000 के दौरान जावक पत्र-डाक परियात में

4.36% की वृद्धि हुई है, जबकि उसी अवधि के दौरान आवक परियात में 7.35% वृद्धि दर्ज हुई है। पत्र-डाक परियात तालिका 6 में दिया गया है।

तालिका - 6
एल.सी. / ए.ओ. डाक-लाख कि. ग्रा. में

वर्ष	1998-99	1999-2000	वृद्धि / कमी
आवक मर्दे	39.06	41.93	(+) 7.35 %
जावक मर्दे	30.06	31.37	(+) 4.36 %

सरफेस एयर लिफ्टेड (एस.ए.एल.) सेवा

5.18 स्थल डाक का ऐसी वस्तुएं जिनका कम चरियता देकर हवाई मार्ग से पारेपण किया जाता है, सरफेस एयर लिफ्टेड (एस.ए.एल.) वस्तुएं कहलाती हैं। वर्तमान में एस.ए.एल. पार्सल सेवा 23 गंतव्यों के लिए उपलब्ध है।

पार्सल

5.19 वर्ष 1999-2000 के दौरान जावक पार्सलों के विदेशी परियात में 2.93% की वृद्धि हुई है। कथित अवधि के दौरान आवक पार्सलों के विदेशी परियात में 44.10% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है।

तालिका - 7
विदेश पार्सल परियात

वर्ष	1998-99	1999-2000	वृद्धि / कमी
आवक मर्दे	159987	230544	(+) 44.10 %
जावक मर्दे	80047	82394	(+) 2.93 %

अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर सेवा

5.20 आवक अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर सेवा 27 देशों के साथ उपलब्ध है जहां से भारत को मनीआर्डर भेजे जा सकते हैं। नेपाल तथा भूटान के साथ दोनों तरफ मनीआर्डर सेवा उपलब्ध है जहां से भारत को मनीआर्डर भेजे व प्राप्त किए जा सकते हैं।

5.21 वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 48, 363 विदेशी मनीआर्डरों से भारत को 2036.76 लाख रु. की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 1999-2000 में विदेशी मनीआर्डर मूल्यों की राशि में 3.93% की वृद्धि हुई है।

Table 5
INTERNATIONAL SPEED POST – EMS TRAFFIC

Year	1998	1999	Increase/Decrease
Inward Articles	317163	396393	(+) 24.98%
Outward Articles	391983	439425	(+) 12.10%

Letter Mail

5.17 Traffic of outward letter mail traffic has shown an increase of 4.36% during the year 1999-2000,

while the inward traffic during the same period showed a rise of 7.35%. Letter Mail traffic is given in Table 6.

Table 6
LC/AO MAILS – In Lakhs Kg.

Year	1998-99	1999-00	Increase/Decrease
Inward Articles	39.06	41.93	(+) 7.35%
Outward Articles	30.06	31.37	(+) 4.36%

Surface Air Lifted (SAL) Service

5.18 Surface items conveyed through air with reduced priority are known as Surface Air Lifted (SAL) items. Presently, SAL parcel service is available for 23 destinations..

Parcel

5.19 Foreign traffic of outward parcels has registered a growth of 2.93% during the year 1999-2000. Foreign traffic of inward parcels registered an impressive increase of 44.10% in the said period.

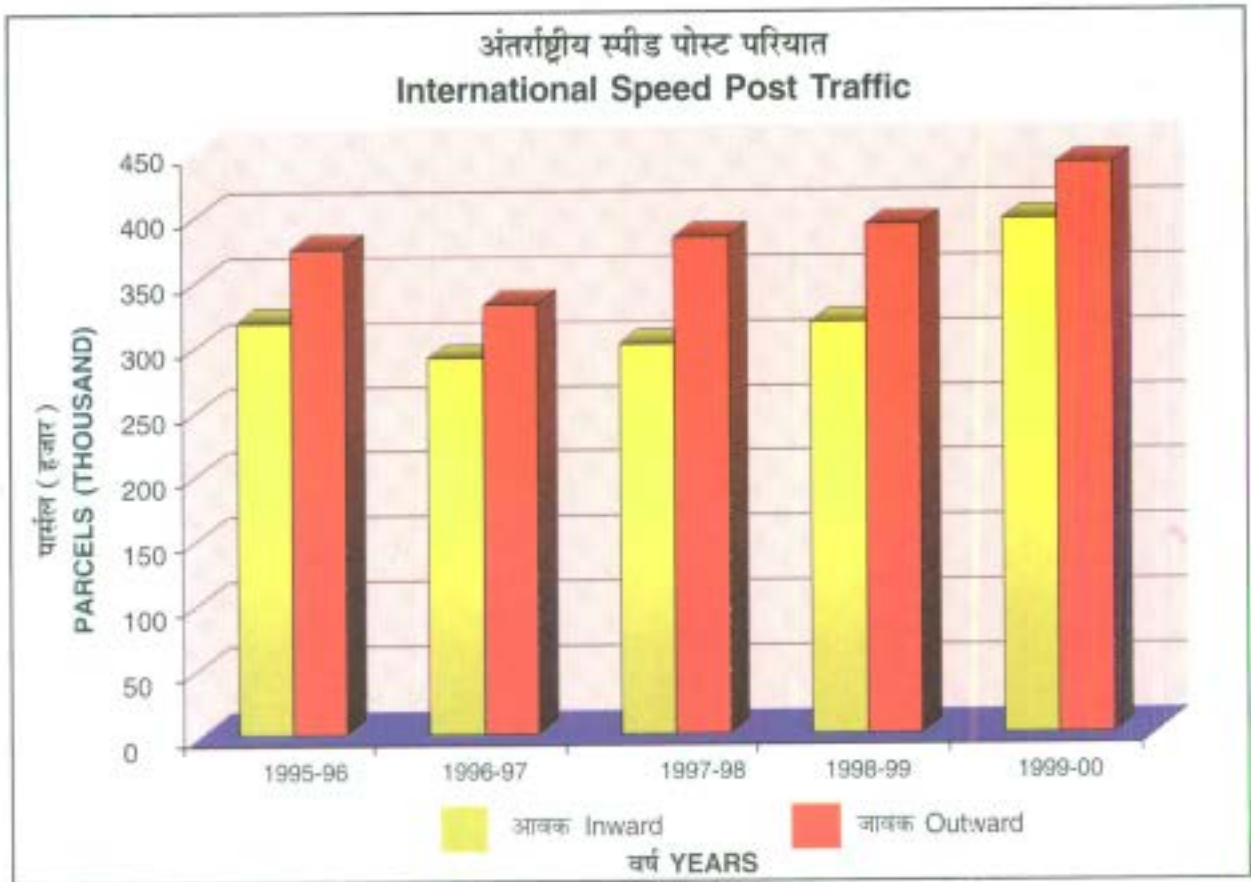
Table 7
FOREIGN PARCEL TRAFFIC

Year	1998-99	1999-00	Increase/Decrease
Inward Articles	159987	230544	(+) 44.10%
Outward Articles	80047	82394	(+) 2.93%

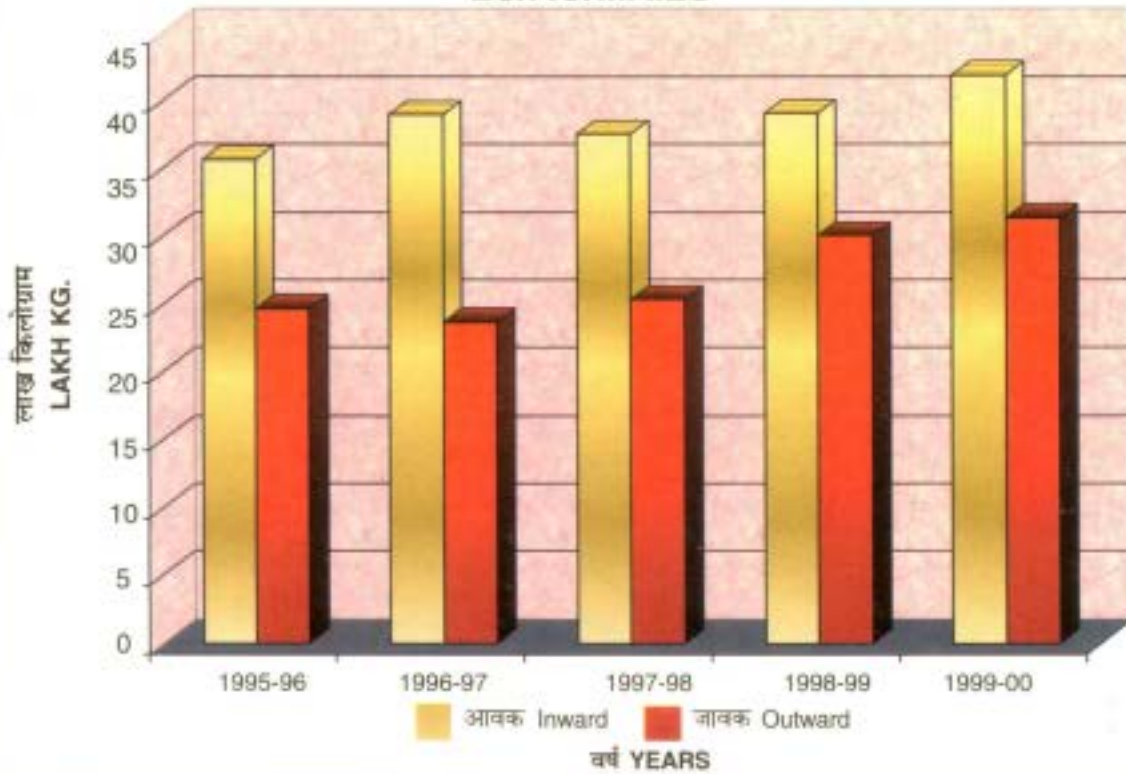
International Money Order Service

5.20 Inward International Money Order Service is available with 27 countries whereby Money Orders can be remitted to India. A two-way Money Order service is available with Nepal and Bhutan, whereby Money Orders can be remitted from and to India.

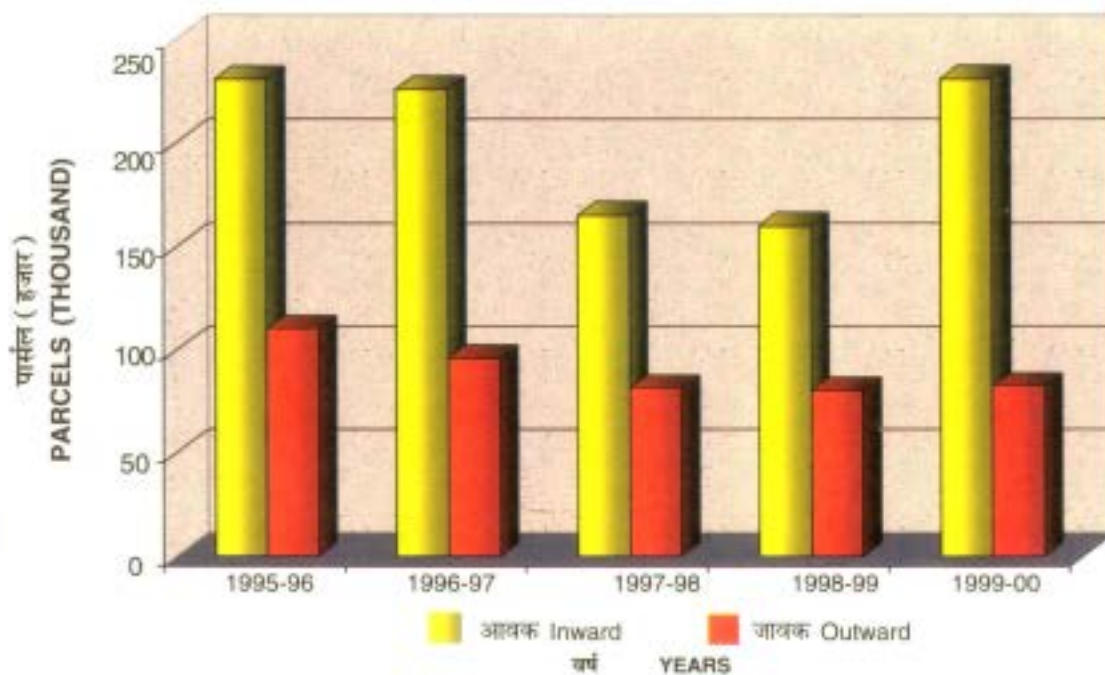
5.21 During the year 1999-2000, a total of 48,363 foreign money orders brought in Rs.2036.76 lakhs in foreign exchange to India. The value of Foreign money orders value has increased by 3.93% in 1999-2000, as compared to last year.



एल सी / ए ओ डाक
LC/AO/MAILS



विदेश पार्सल परियात
FOREIGN PARCEL TRAFFIC



तालिका - 8
विदेश मनीआर्डर

क्र. सं.	1998	1999	वृद्धि / कमी
1. मनीआर्डर परियात	50397	48363	(-) 4.04 %
2. संप्रेषित मनीआर्डरों का मूल्य (लाख रु. में)	1959.68	2036.76	(+) 3.93 %

पत्र-लेखन प्रतियोगिता

5.22 युवाओं की लेखन कला को विकसित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को मजबूत करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यू.पी.यू. तथा सार्क द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्र-लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

5.23 29वीं यू.पी.यू. पत्र-लेखन प्रतियोगिता 9 फरवरी, 2000 को आयोजित की गई थी। 2300 से भी अधिक बच्चों से प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं।

5.24 31.8.99 को 16वीं सार्क पत्र-लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कुल 1079 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, उनका मूल्यांकन किया गया तथा मेजबान देश बंगलादेश को उत्कृष्ट राष्ट्रीय प्रविष्टि प्रदान की गई। सार्क देशों में भारतीय प्रविष्टि को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

विदेशों से प्राप्त निवल प्राप्तियां

5.25 विभाग को अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालन पर टर्मिनल राशि, पारगमन प्रभार इत्यादि के कारण 28.35 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।



Table 8
FOREIGN MONEY ORDERS

S.No	1998	1999	Increase/decrease
1. Money Order Traffic	50397	48363	(-) 4.04%
2. Value of MOs transmitted (Rs in lakhs)	1959.68	2036.76	(+) 3.93%

Letter Writing Competition

5.22 Letter writing competitions are conducted by the UPU and the SAARC every year for young people with the objectives of developing their faculty in composition and to contribute to the strengthening of international friendship.

5.23 The 29th UPU letter writing competition was held on 9th January, 2000. Entries from more than 2300 children were received.

5.24 The 16th SAARC letter writing competition was held on 31.8.1999. 1079 entries were received, evaluated and the best national entry forwarded to Bangladesh, the host country. India's entry secured the 1st position among SAARC countries.

Net Receipts from foreign countries

5.25 The Department received Rs.28.35 crores in foreign exchange on account of Terminal dues, transit charges etc. on international mail operations.

अध्याय-6

प्रौद्योगिकी

परिचय

6.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, संचार के नए साधनों की शुरुआत और प्रौद्योगिकी विकास ने डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने के प्रयास, उसके फ्रंट आफिसों और डाक संरचना के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

6.2 विभाग अब डाक-प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए पहले किए गए उपायों का समेकीकरण और एकीकरण करने की ओर अग्रसर है और मौजूदा तथा नये व्यवसाय के लिए विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों को अपने कार्यों में प्रयुक्त कर रहा है। इस वातावरण में मूल्यवर्धित सेवाओं की ओर से अत्यंत निर्णायक भूमिका अदा करने की उम्मीद है।

6.3 विभाग ने वर्ष 1994-95 के दौरान चुने हुए डाकघरों के आधुनिकीकरण का कार्य चरणबद्ध रूप से किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डाकघरों में प्रचालनात्मक उपकरणों के उन्नयन तथा उपभोक्ताओं के लिए अनुकूल परिवेश तथा कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करने पर बल दिया गया। तब से इस परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 135 डाकघरों को आधुनिकीकृत किया गया।

6.4 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभाग की मौजूदा सेवाओं के साथ-साथ नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए उपयुक्त एवं नई प्रौद्योगिकियों की पहचान के लिए तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ अंतर्संबंध बनाने के लिए सहायता एवं सुझाव के बतौर विभाग में गठित प्रौद्योगिकी पर स्थाई समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), दूरसंचार विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं जिनकी वर्ष के दौरान कई बैठकें हुईं। समिति ने नित नई आ रही प्रौद्योगिकियों को प्रभावपूर्ण ढंग से समाविष्ट करने, विद्यमान प्रौद्योगिकी में कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के मूल्यवान सुझाव दिए।

6.5 नीची पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय डाक, अपने योजनाबद्ध बजट के 61 प्रतिशत का व्यय सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं उन्नयन करने, ग्राहकों की बढ़ती हुई आवश्यकता

को पूरा करने तथा नए मूल्यवर्धित उत्पाद विकसित करने एवं उपलब्ध कराने के मद्देनजर प्रौद्योगिकी के समावेश पर करेगा।

काउंटर प्रचालन-फ्रंट आफिस

6.6 हाल ही में कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में बहुत तीव्रता से परिवर्तन होते आ रहे हैं। भारतीय डाक ने उभरती हुई प्रौद्योगिकी तथा बेहतर ग्राहक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावपूर्ण फ्रंट आफिस प्रचालन व कर्मचारियों की बेहतर संतुष्टि एवं उचित लागत नियंत्रण के बीच तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, कुल 1250 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गईं। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान जिन कार्यालयों में ये मशीनें लगी हैं उनकी संख्या बढ़कर 1560 हो गई। इन मशीनों पर प्रतिमाह किए जाने वाले लेन-देन की संख्या 1 करोड़ है। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय ने टिप्पणी की कि एम.पी.सी.एम. उत्कृष्टतम जनसेवाओं का अनुपम उदाहरण है।

साफ्टवेयर

6.7 प्रचालन तथा अनुप्रयोग साफ्टवेयर का मानकीकरण करने, अंतर-प्रचालन, संबंध और सिंगल पाइंट डाटा एन्ट्री लक्ष्य प्राप्त करने की विभाग की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी डाकघरों के कार्यों (बचत बैंक के अलावा) हेतु एक व्यापक पैकेज, "मेघदूत 98" लगभग 1500 कार्यालयों में संस्थापित किया गया। डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर द्वारा पूर्णतया घरेलू रूप से विकसित किया गया मेघदूत 98 सही मायने में एक बहुमुखी साफ्टवेयर है। इससे किसी डाकघर में फ्रंट आफिस के साथ बैंक आफिस प्रचालन पूर्णतया एकीकृत होगा।

6.8 संचय पोस्ट एक नया व्यापक बचत बैंक साफ्टवेयर है जो 303 डाकघरों में संस्थापित किया गया है और अन्य 100 साइटों पर संस्थापित किया जा रहा है। यह साफ्टवेयर एस.बी. आर.डी., टी.डी. राष्ट्रीय बचत पत्रों, आई.वी.पी., के.वी.पी. आदि सभी प्रकार के लेन-देन को संचालित कर लेता है। ये सभी सेवाएं सिंगल विंडो पर प्रदान की जा सकती हैं।

उपग्रह मनीआर्डर सेवा

6.9 अपनी आधुनिकीकरण की कार्यनीति के एक भाग के रूप में, डाक विभाग ने देशभर में जनसाधारण की सहायता करने



Chapter 6

TECHNOLOGY

Introduction

6.1 The liberalisation of the Indian economy, introduction of new means of communication and developments in technology have underlined the need for modernising postal services with the help of information technology. India Post's efforts to modernise have been focussed on modernisation of front office areas and postal infrastructure.

6.2 The Department is now moving towards consolidation and integration of the steps taken in the past for computerisation and modernisation of the postal system and harnessing emerging technologies to the existing as well as new businesses. In this environment the value added services are expected to play an increasingly crucial role.

6.3 The Department took up modernisation of selected Post Offices in a phased manner from the year 1994-95 which inter-alia aimed at upgrading operational equipment in post offices and providing a friendly ambience for the users and better working environment for the workers. This on-going programme is being successfully implemented since then. 135 Post Offices were modernised during the year 1999-2000.

6.4 The Standing Committee on Technology constituted in the Department, comprising representatives from the Indian Institutes of Technology (IITs), the National Informatics Centre (NIC), the Department of Telecommunications and the Department of Electronics, to aid and advise the Department in identifying appropriate and new technologies for the existing services, the new products and services, value additions and interfacing with other Government Departments, in the field of Information Technology met several times during the year. The Committee provided valuable suggestions for effective induction of emerging technologies and improving performance of existing ones.

6.5 During the 9th Five Year Plan, India Post will be spending about 61% of its planned budget on

induction of technology with a view to improving and upgrading the quality of service, meeting the emerging need of the customers, and developing as well as providing new value added services and products.

COUNTER OPERATIONS – FRONT OFFICE

6.6 Technology in the field of computers has been changing very rapidly in recent times. India Post has recognised the need to keep pace with emerging technologies and processes for effective office operations for better customer care, greater employee satisfaction and reasonable cost control. A total of 1250 Multipurpose Counter Machines (MPCMs), were installed during the year 1999-2000. The total number of offices having such machines went up to 1560 during the year under review. The number of transactions being conducted on these machines were one crore per month. The Ministry of Personnel and Public Grievances has observed that MPCMs are an outstanding example of excellence in public services.

Software

6.7 In keeping with the Department's policy to standardise operating and application software, achieve inter-operability, connectivity and single-point data entry, *Meghdoot 98*, a comprehensive package for all post office functions (except Saving Bank) was deployed in about 1500 offices. A truly versatile software, *Meghdoot 98* has been developed entirely in-house by the Postal Training Centre, Mysore. It integrates front office with back office operations in a post office.

6.8 *Sanchay Post*, the new comprehensive savings bank software has been installed in 303 Post Offices and is in the process of being installed in another 100 sites. This software handles all types of transactions pertaining to SB, RD, TD, National Savings Certificates, IVPs, KVPs, etc.. All these services can be provided at a single window.

SATELLITE MONEY ORDER SERVICE

6.9 As a part of its modernizing strategy, the

के लिए एक नवीन उपग्रह आधारित सुलभ पहुंच वाली तत्काल मनीआर्डर सेवा सफलतापूर्वक शुरू की है। मनीआर्डरों को शीघ्रता से भुगतान करने की सुविधा देने के लिए डाक प्रणाली में वेरो स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी.एस.ए.टी.) के रूप में नवीनतम प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई है। देश में कुल 139 वी.एस.ए.टी. स्टेशनों की स्थापना की गई है जिन्हें टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से अन्य 876 स्थानों से जोड़ा गया है जिसके जरिये मनीआर्डरों को तुरंत संप्रेषित किया जाता है जिससे 7 से 10 दिनों तक औसतन संप्रेषण समय कम हुआ है, अतः मनीआर्डरों का भुगतान पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी हो जाता है। इन आंकड़ों में 1999-2000 के दौरान उच्च गति के 62 वी.एस.ए.टी. और 266 ई.एस.एम.ओ. के संस्थापन शामिल हैं। वी.एस.ए.टी. पर हो रहे लेन-देनों की संख्या उसकी शुरुआत में कुछ हजार से बढ़कर 10.5 लाख प्रतिमाह हो गई है।

हाइब्रिड मेल सेवा तथा कारपोरेट मनीआर्डर सेवा

6.10 वी.एस.ए.टी. के संस्थापन से विभाग दो मूल्यवर्धित उत्पाद हाइब्रिड मेल सर्विस (एच.एम.एस.) और कारपोरेट मनीआर्डर सर्विस की व्यवस्था कर सका है। एच.एम.एस. मूलपाठ तथा डेटा को इलेक्ट्रॉनिकी से एक वी.एस.ए.टी. केन्द्र के दूसरे वी.एस.ए.टी. केन्द्र में प्रेषण करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है जिससे हार्ड कॉपी को एक डाक मद की तरह पोस्टमैन द्वारा वितरित किया जा सके। कारपोरेट मनीआर्डर सर्विस ने कारपोरेट ग्राहकों को 100 लाख रुपए तक के मनीआर्डर भेजने में सक्षम कर दिया है।

स्वचालित एकीकृत मेल प्रोसेसिंग प्रणाली (ए.आई.एम.पी.एस.)

6.11 विभाग मुंबई और चेन्नई में स्वचालित मेल प्रोसेसिंग

प्रणाली स्थापित की है। प्रणालियां व्यस्ततम समय में भी बृहत मात्रा में डाक निपटाती रहती हैं जिससे इन महानगरों से देश के अन्य स्थानों तथा विदेश में, डाक प्रेषण की गति में तीव्रता आई है। इससे, इन शहरों में आने वाली डाक के वितरण समर्थ में भी कमी आई है। प्रत्येक केन्द्र में औसतन 5 लाख पत्र प्रतिदिन प्रोसेस किए जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन (ई.एफ.एम.)

6.12 विभाग द्वारा निर्णय लिया गया था कि डाकघरों में संस्थापित तथा ग्राहक द्वारा डाक के उपयोग के लिए प्राप्त की जाने वाली फ्रैंकिंग मशीनें केवल इलेक्ट्रॉनिक होंगी। बहुमुखी होने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीनों में अतिरिक्त सुरक्षा का गुण है जो उन्हें गड़बड़ी रहित बनाता है तथा राजस्व के क्षरण को रोकता है। इन मशीनों को टेलीफोन लाइनों पर कम्प्यूटर के जरिए दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 111 इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीनें संस्थापित की गई हैं।

वेब उपस्थिति

6.13 सूचना, संचार तथा विपणन के लिए इंटरनेट की "वर्ल्ड वाइड वेब" का अविर्भाव एक ऐसे माध्यम के रूप में हुआ है जो किफायती और विश्व स्तर पर पहुंच वाला है। इसके अतिरिक्त चाणित्य विकास निदेशालय एवं विभिन्न सर्किलों/क्षेत्रों ने भी अपने वेबसाइट स्थापित किए हैं जो विभाग की मुख्य वेबसाइट से हाइपरलिंकड हैं।

चाणित्य विकास निदेशालय	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू स्पीड पोस्ट.ओर्ग
पुणे	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू पुणे पोस्ट.ओर्ग
गोवा	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू गोवा पोस्ट.ओर्ग
असम	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू असम पोस्ट.कॉम
उड़ीसा	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू उड़ीसा पोस्ट.कॉम
कोलकाता	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू कोलकाता पोस्ट.कॉम
केरल	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू केरल पोस्ट.ओर्ग
मध्य प्रदेश	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एमपी पोस्ट.ओर्ग
उत्तर प्रदेश	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू यूपी पोस्ट.ओर्ग
पीटीसी मद्रै	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू पोस्टल सेन्टर ओर्ग

Department of Posts has successfully introduced an innovative satellite based easily accessible instant money order service for helping the common man throughout the country. Modern technology in the form of Very Small Aperture Terminals (VSATs) has been introduced in the postal system for facilitating quicker payment of money orders. A total of 139 VSAT stations have been set up in the country which are in turn connected to another 876 locations through the telephone network through which money orders are getting transmitted instantly cutting down the transmission time on an average by 7 to 10 days thus facilitating much quicker payment of money orders than earlier. The figures includes installation of 62 high speed VSATs and 266 ESMOs during 1999-2000. The number of transactions being handled on the VSATs has gone up from a few thousands at inception to over 10.5 lakhs per month.

HYBRID MAIL SERVICE AND CORPORATE MONEY ORDER SERVICE

6.10 Installation of VSATs has also enabled the Department to provide two value added products called Hybrid Mail Service (HMS) and Corporate Money Order Service. The former provides the facility to transmit text and data electronically from one VSAT centre to another to effect delivery of the hard copy through the Postman as a postal article. Corporate Money Order service enables the corporate clients to send Money Orders up to the value of Rs.100 lakhs.

AUTOMATIC INTEGRATED MAIL PROCESSING SYSTEM (AIMPS)

6.11 The Department has set up automatic mail

processing systems in Mumbai and Chennai. These systems keep in processing large volumes of mail during peak hours thus expediting mail movement from these major metropolises to other places in India and abroad. They also help in reducing the time to deliver incoming mails for these cities. Each of these centres, on an average, processes about five lakh letters every day.

ELECTRONIC FRANKING MACHINES (EFMs)

6.12 A decision was taken by the Department that Franking Machines installed in post offices as well as those to be procured by the customers would only be of the electronic variety. Besides being versatile, the Electronic Franking Machines have additional security features which make them tamper proof thus preventing leakage of revenue. These machines are also amenable to remote access through computers over telephone lines. A total of 111 Electronic Franking Machines were installed during the year 1999-2000.

WEB PRESENCE

6.13 The Internet's Worldwide Web is emerging as an affordable and globally accessible tool for information, communication and marketing. The Department has set up its own web site as *India-post.org*. w.e.f. 26th January, 2000. In addition the Business Development Directorate and various Circles/Regions have also set up the following websites which are hyperlinked to the Department's main website :

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTORATE	-	www.speedpost.org
PUNE	-	www.punepost.org
GOA	-	www.goapost.org
♦ ASSAM	-	www.assampost.com
ORISSA	-	www.orissapost.com
KOLKATA	-	www.kolkatapost.com
KERALA	-	www.keralapost.org
MADHYA PRADESH	-	www.mppost.org
UTTAR PRADESH	-	www.uppost.org
PTC MADURAI	-	www.postalcentre.org

पीटीसी मैसूर	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू पीटीसी इन्फो.ओर्ग
पोस्टल स्टाफ कालेज गाजियाबाद	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू पीएससीआई.कॉम
औरंगाबाद	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू औरंगाबाद.कॉम
महाराष्ट्र	-	डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू महाराष्ट्र पोस्ट.ओर्ग

विभाग की वेबसाइट उस सूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाएगी जिसका लक्ष्य विश्व स्तर पर डाक सेवा के संभावित प्रयोक्ता हैं और यह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन सहित (यूपीयू) अन्य डाक प्रशासनों के साथ संबंध बनाएगी तथा निर्यात योग्य उत्पादों, सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के लिए एक विपणन उपकरण के रूप में विकसित होगी।

6.14 डाक निदेशालय का इंटरनेट चर्च 1998-99 के दौरान शुरू हुआ था। इस प्रणाली में 125 नोड्स को कवर करने के लिए इंटरनेट पहुंच, डाक पेटियां, आई.सी.क्यू. चैट और एफ.टी.पी.

की व्यवस्था है। इंटरनेट को एक 64 के.बी.पी.एस. लीज्ड लाइन के माध्यम से एकीकृत किया गया है।

6.15 लोकल एरिया नेटवर्क (एल.ए.एन.) में एक इंटरनेट वेबसाइट भी स्थापित किया गया है, अंततः जिसका उद्देश्य एक कागज रहित कार्यालय बनाने की ओर अग्रसर होना है। डाक निदेशालय के लोकल एरिया नेटवर्क का पूर्वोत्तर और असम सर्किल से अंतर्संबंध बना हुआ है। असम सर्किल में गुवाहाटी में एक 64 के.बी.पी.एस. लीज्ड लाइन की व्यवस्था की गई है। शिलांग में डायल-अप तंत्र है क्योंकि उस स्टेशन पर किसी लीज्ड सर्किट की व्यवस्था नहीं है।



PTC MYSORE
STAFF COLLEGE GHAZIABAD
AURANGABAD
MAHARASHTRA

- www.ptcinfo.org
- www.psci.com
- www.aurangabad.com
- www.maharashtrapost.org

The Department's website will facilitate flow of information globally directed at potential users of postal services, connectivity to other postal administrations, including the Universal Postal Union (UPU), and develop into a marketing tool for 'exportable' products, services and technologies.

6.14 The internet of the Postal Directorate was commissioned during the year 1998-99. The system provides internet access, mail boxes, ICQ, Chat and FTP to over 125 nodes. Internet has been integrated through a 64 Kbps leased line.

6.15 An internet web site has also been set up in the Local Area Network (LAN) that has the objective, in the long run, of moving towards a paperless office. The Postal Directorate's LAN has connectivity to the North Eastern and Assam Circles. Assam Circle has been provided a 64Kbps leased line at Guwahati. Shillong has a dial up mechanism, as there is no provision of leased circuit at that station.

अध्याय-7 वित्तीय सेवाएं

बचत बैंक

7.1 डाक विभाग 1,54,000 से अधिक डाकघरों के अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अल्प बचत योजनाओं को प्रचालित करता है। जिसमें से 1,38,149 डाकघर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

7.2 डाकघर बचत बैंक की ओर से वर्तमान में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

- बचत खाता योजना

- आवर्ती जमा योजना
- सावधि जमा योजना : 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष
- मासिक आय योजना
- लोक भविष्य निधि योजना
- किसान विकास पत्र योजना
- राष्ट्रीय बचत पत्र
- राष्ट्रीय बचत योजना (1992)

7.3 नीचे तालिका 9 में बचत योजनाओं द्वारा किए कार्य-व्यापार की रूपरेखा दी गई है :-

तालिका - 9		
बचत योजनाएं : कार्य व्यापार रूपरेखा (31.3.2000 की स्थिति के अनुसार)		
बचत योजना का नाम	खातों की संख्या	कुल राशि (करोड़ रुपयों में)
बचत खाता (एसबी)	5,90,66,453	7978.30
आवर्ती जमा खाता	4,37,50,913	14265.63
सावधि जमा खाता	21,46,875	5340.68
मासिक आय योजना खाता	69,86,156	29974.63
राष्ट्रीय बचत योजना 1992	6,11,218	845.42
लोक भविष्य निधि खाता	12,06,224	4623.05

डाक जीवन बीमा

7.4 सन् 1884 में प्रारंभ की गई डाक जीवन बीमा योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पुरानी कल्याण योजनाओं में से एक है। प्रारंभ में यह योजना केवल डाक कर्मचारियों तक ही सीमित थी। आज यह योजना न केवल केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्मिकों को बल्कि सशस्त्र सेना कार्मिकों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत सरकार के अनेकों स्वायत्त

तथा वित्त संस्थानों और केन्द्र व राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवा प्रदान कर रही है। एक अभिनव परिवर्तन के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लाभ के लिए वर्ष 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना शुरू की गई है।

7.5 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि की स्थिति और वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राप्त कारोबार की स्थिति नीचे तालिका 10 में दी गई है :-



Chapter 7

FINANCIAL SERVICES

Savings Bank

7.1 The Department of Posts operates the Small Savings Schemes of Govt. of India, Ministry of Finance through its countrywide network of more than 1,54,000 Post Offices. Out of them, as many as 1,38,149 Post Offices are located in the rural areas of the country.

7.2 The following schemes are at present offered by the Post Office Savings Bank (POSB):

- Savings Account Scheme

- Recurring Deposit Scheme
- Time Deposit Scheme: 1 Year, 2 Years, 3 Years & 5 Years
- Monthly Income Scheme
- Public Provident Fund Scheme
- Kisan Vikas Patra Scheme
- National Savings Certificate
- National Savings Schemes, 1992.

7.3 The business profile of the Saving Schemes is given in Table 9 below:

Table 9
SAVING SCHEMES : BUSINESS PROFILE (as on 31.3.2000)

Name of Saving Scheme	No. of Accounts	Total Amount (Rs.in Crores)
Saving Account (SB)	5,90,66,453	7978.30
R.D. Accounts	4,37,50,913	14265.63
T.D. Accounts	21,46,875	5340.68
MIS Accounts	69,86,156	29974.63
NSS 1992	6,11,218	845.42
PPF	12,06,224	4623.05

Postal Life Insurance

7.4 Postal Life Insurance (PLI), introduced in 1884, is one of the oldest welfare schemes for the Government employees. The scheme was initially meant only for the postal employees. Today it caters not only to employees of the Central and the State Governments, but also to Armed Forces personnel, employees of the local bodies, government aided educational institutions, universities, nationalised banks, many au-

tonomous and financial institutions of the Government of India and Central and State Public Undertakings. In a major innovation, Rural Postal Life Insurance Scheme was introduced in 1995 for the benefit of rural populace.

7.5 The status of PLI/RPLI Fund as on 31.3.2000 and the business procured during the year 1999-2000 are as given in Table 10:

तालिका - 10

डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा द्वारा किया गया कार्य-निष्पादन : 1999-2000

योजना का नाम	प्राप्त पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (करोड़ रु० में)	पॉलिसियों की कुल सं०	बीमित सकल राशि (करोड़ रु० में)
डाक जीवन बीमा	1,64,621	1398.17	24,51,587	9231.97
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	1,57,823	585.83	6,66,138	2250.69

7.6 डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा निम्नलिखित प्रकार की पॉलिसियों की सुविधा प्रदान करते हैं :

- आजीवन बीमा (सुरक्षा)
- परिवर्तनीय आजीवन बीमा (सुविधा)
- बंदोबस्ती बीमा (संतोष)
- 15 वर्ष तथा 20 वर्ष का प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (सुमंगल)

7.7 डाक जीवन बीमा के अंतर्गत एक नई स्कीम "युगल

सुरक्षा" 1.8.1997 से शुरू की गई है जिसमें एक प्रीमियम का भुगतान करने पर बीमित व्यक्ति और उसके पति / पत्नी को बीमा कवर का लाभ प्रदान कर दिया जाता है। इन स्कीम के अंतर्गत 21 से 45 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति द्वारा अधिकतम 5 लाख रु. की बीमित राशि पॉलिसी ली जा सकती है। पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर अथवा बीमादार की मृत्यु होने पर, इनमें जो पहले पड़े, बीमादार अथवा उसकी पत्नी / उसके पति अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को बीमित राशि तथा प्रोद्भूत बोनस का भुगतान कर दिया जाता है।

TABLE 10
PERFORMANCE OF PLI/RPLI : 1999-2000

Name of Plant	No. of policies Procured	Sum Assured (Rs. in Crores)	Aggregate No. of Policies	Aggregate Sum Assured (Rs. in Crores)
PLI	1,64,621	1398.17	24,51,587	9231.97
RPLI	1,57,823	585.83	6,66,138	2250.69

7.6 PLI and Rural PLI offer the following types of policies:-

- Whole Life Assurance (Suraksha)
- Convertible whole Life Assurance (Suvidha)
- Endowment Assurance (Santosh)
- Anticipated Endowment Assurance for 15 and 20 years (Sumangal)

7.7 Under PLI, a new scheme called "Yugal

Suraksha" has been introduced with effect from 1.8.1997 which provides insurance cover to the insurant and his/her spouse on payment of a single premium. Under this scheme, policy can be taken for a maximum sum assured of Rs.5 lakhs by those who are between 21 and 45 years of age. The sum assured alongwith accrued bonus is payable to insurant or his spouse/legal heir at the end of the term or death of insurant whichever is earlier.

कुछ विशेष डाक टिकट



SOME THEMATIC STAMPS



अध्याय-8

वित्तीय प्रबंधन

परिचय

8.1 डाक विभाग जनता को डाकघरों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता है। पूर्ण डाक सुविधाओं के अतिरिक्त डाकघर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों / विभागों को और से कई अन्य सेवाएं तथा एजेन्सी कार्य भी करते हैं।

1999-2000 के दौरान विभाग का कुल वित्त निष्पादन काफी अच्छा रहा। लगातार चौथे वर्ष में विभाग 4778.40 करोड़ रुपए के कार्यकारी व्यय को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 4835.53 करोड़ रुपए की संशोधित प्राक्कलन बजट सीमा के भीतर रखने में कामयाब हो सका। यह कड़े बजटीय नियंत्रण और सूक्ष्म मानीटरिंग द्वारा संभव हुआ। वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग का घाटा 1595.82 करोड़ रुपए था जो लगभग 1740.53 करोड़ रुपए के संशोधित प्राक्कलन आंकड़ों की तुलना में पिछले वर्ष के 1590.97 करोड़ रुपए के घाटे के स्तर पर तथा 144.71 करोड़ रुपए से कम था जैसा कि तालिका 11 में दर्शाया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में कार्यकारी व्यय में 427 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि के

बावजूद राजस्व प्राप्ति और वसूलियों में महत्वपूर्ण वृद्धियों के कारण हुआ।

8.2 वर्ष 1999-2000 का निवल कार्यकारी व्यय पिछले वर्ष के 3313.54 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 3615.94 करोड़ रुपए था (अर्थात् इसमें लगभग 9.13% की वृद्धि हुई)। यह वृद्धि मुख्यतः महंगाई भत्ते / महंगाई राहत के भुगतान तथा पेंशन संशोधन के कारण पेंशन प्रभागों के बकाया भुगतान के कारण से थी।

8.3 विभाग पहली बार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए राजस्व एवं वसूली के लक्ष्यों का विस्तार क्रमशः 70 करोड़ रुपए और 17 करोड़ रुपए तक करने में सफल रहा। यह मुख्यतः सूक्ष्म मानीटरिंग, व्यय नियंत्रण तथा प्रीमियम उत्पाद खंड के अच्छे निष्पादन से संभव हो सका जिसके कारण प्राप्तियों में वृद्धि हुई। बकाया उच्चतम शेष में भी काफी कमी आई जो 1997-98 में 760.17 करोड़ रुपए से घटकर 1999-2000 में 148.00 करोड़ रुपए हो गया। कुल वित्त निष्पादन नीचे तालिका 11 में दर्शाया गया है।

Chapter 8 FINANCIAL MANAGEMENT

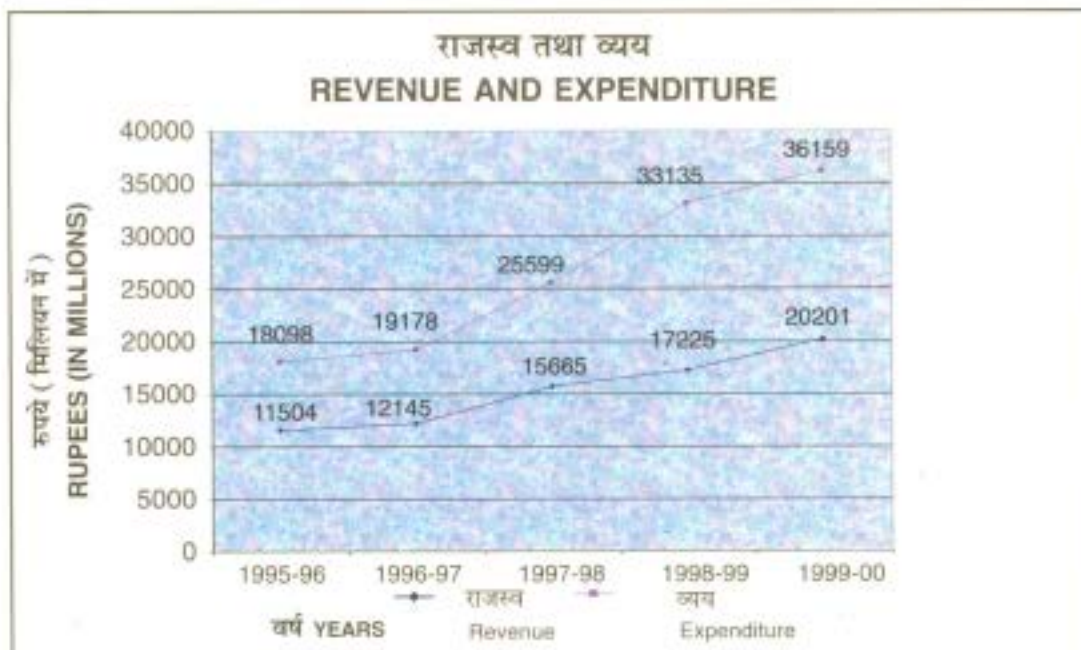
► Introduction :

8.1 The Department of Posts provides various services to the public through a nation wide network of post offices. Besides extending purely postal facilities, post offices perform various financial services and agency functions on behalf of the other Ministries/ Departments of the Government of India. The overall finance performance of the Department during 1999-2000 was very good. For the fourth consecutive year the Department has been able to keep the working expenses of Rs.4778.40 crores well within the Revised Estimates budget ceiling of Rs.4835.53 crores, approved by the Ministry of Finance. This was possible through strict budgetary control and close monitoring. During the financial year 1999-2000 the deficit of the Department was Rs.1595.82 crores which was almost at the level of the previous year deficit of Rs.1590.97 crores and less by Rs.144.71 crores as compared to the Revised Estimates figure of Rs.1740.53 crores as shown in Table 11. This was due to appreciable increase in revenue receipts and recoveries, despite substantial increase of Rs.427

crores in working expenses as compared to the previous year.

8.2 The net working expenses of the year 1999-2000 were Rs.3615.94 crores against the previous year's expenditure of Rs.3313.54 crores (i.e. an increase of about 9.13%). This increase was mainly due to the payment of Dearness Allowance/Dearness Relief and payment of arrears of pensionary charges due to revision of pension.

8.3 The Department for the first time succeeded in exceeding the revenue and recovery targets fixed by the Ministry of Finance by Rs.70 crores and Rs.17 crores respectively. This has been possible mainly due to close monitoring, expenditure control and good performance in the premium product segment resulting in enhanced receipts. There was also significant reduction in the outstanding suspense balance which was reduced from Rs.760.17 crores in 1997-98 to Rs.148.00 crores in 1999-2000. The overall financial performance is as shown in Table 11 below:-



तालिका - 11

समग्र वित्तीय निष्पादन (वर्ष 1999-2000 के लिए)

(करोड़ रु० में)

व्यय	वास्तविक आंकड़े 1998-99	संशोधित अनुमान 1999-2000	वास्तविक आंकड़े 1999-2000	1999-2000 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ प्रतिशत कमी (-)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/प्रतिशत कमी (-)
व्यय					
सामान्य प्रशासन	262.54	275.47	284.16	3.15 %	8.23 %
प्रचालन	3020.69	3397.06	3380.17	(-) 0.50 %	11.90 %
एजेंसी सेवाएं	167.28	182.79	178.01	(-) 2.62 %	6.41 %
* अन्य	900.78	980.21	936.06	(-) 4.50 %	3.92 %
कुल व्यय	4351.29	4835.53	4778.40	(-) 1.18 %	9.82 %
घटाएं : वसूलियां	1037.75	1145.00	1162.46	1.52 %	12.02 %
निवल व्यय	3313.54	3690.53	3615.94	(-) 2.02 %	9.13 %
राजस्व					
डाक टिकटों की बिक्री	946.89	1124.19	1071.13	(-) 4.72 %	13.12 %
नकदी के रूप में प्राप्त डाक शुल्क	483.86	558.30	651.87	16.76 %	34.72 %
मनीआर्डर और भारतीय पोस्टल आर्डर आदि पर कमीशन	219.40	225.00	253.55	12.69 %	15.57 %
** अन्य प्राप्तियां	72.42	42.51	43.57	2.49 %	(-) 39.84 %
कुल	1722.57	1950.00	2020.12	3.60 %	17.27 %
घाटा (निवल व्यय राजस्व)	1590.97	1740.53	1595.82	(-) 8.31 %	0.30 %

* इसमें मजदूरी, कार्यालय व्यय, समयोपरि भत्ता, किराया एवं कर, प्रोफेशनल सेवाएं, अनुरक्षण, स्टाफ को सुविधाएं, पेंशन संबंधी प्रभार, आपूर्ति और सामग्री, यांत्रिक उपस्कर, अन्य प्रशासनिक व्यय आदि शामिल हैं।

** इसमें डाक विभाग द्वारा बिक्री किए गए पासपोर्ट आवेदन फार्म, पासपोर्ट शुल्क टिकट एवं केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के सेवा प्रभार तथा अन्य डाक प्रशासनों आदि से हुई आय शामिल है।

8.4 विभाग की आय "वसूलियां" और "राजस्व" के रूप में होती है। उपर्युक्त तालिका 12 में उल्लिखित वसूलियों की मद विभाग द्वारा अर्जित कमीशन की यह रकम दर्शाती है जो विभाग द्वारा अन्य विभागों तथा संगठनों की ओर से किए गए एजेंसी/वित्तीय सेवाओं से अर्जित की गई है और 'राजस्व' में

डाक मर्दों की बिक्री, मनीआर्डरों तथा भारतीय पोस्टल आर्डरों पर कमीशन तथा अन्य प्रीमियम सेवाओं से हुई प्राप्तियों के जरिये हुई आय है। विभाग की आय खर्च किए गए कार्यकारी व्ययों की तुलना में कम है। इसके परिणामस्वरूप घाटे में और वित्त मंत्रालय से मिलने वाली तदनुसारी वित्तीय सहायता में क्रमशः

Table 11
Overall Financial Performance
(for the year 1999-2000)

(Rs. in crores)					
Particulars	Actuals 1998-99	RE 1999-00	Actuals 1999-00	%age inc(+)/ (-) over RE 1999-2000	%age inc(+)/ (-)over previous year
Expenditure					
General Administration	262.54	275.47	284.16	3.15%	8.23%
Operation	3020.69	3397.06	3380.17	(-)0.50%	11.90%
Agency Services	167.28	182.79	178.01	(-)2.62%	6.41%
* Others	900.78	980.21	936.06	(-)4.50%	3.92%
Gross Expenditure	4351.29	4835.53	4778.40	(-)1.18%	9.82%
Less: Recoveries	1037.75	1145.00	1162.46	1.52%	12.02%
Net Expenditure	3313.54	3690.53	3615.94	(-)2.02%	9.13%
Revenue					
* Sale of Stamps	946.89	1124.19	1071.13	(-)4.72%	13.12%
Postage realised in Cash	483.86	558.30	651.87	16.76%	34.72%
Commission on Money orders & Indian Postal Orders etc.	219.40	225.00	253.55	12.69%	15.57%
* * Other Receipts	72.42	42.51	43.57	2.49%	(-)39.84%
Total	1722.57	1950.00	2020.12	3.60%	17.27%
Deficit (Net Exp. - Revenue)	1590.97	1740.53	1595.82	(-)8.31%	0.30%

* This includes Wages, Office Expenses, Overtime Allowances, Rent and Taxes, Professional Services, Maintenance, Amenities to Staff, Pensionary Charges, Supplies and Material, Machinery equipments, Other Administrative Expenses, etc.

* * This includes services charges retained by the Department of Posts for sale of Passport Application Forms, Passport Fee Stamps and Central Recruitment Fee Stamps receipts from other Postal Administration etc.

8.4 The earnings of the Department are in the form of 'Recoveries' and 'Revenue'. The item 'Recoveries' mentioned in Table 12 represents the amount of commission earned by the Department for Agency/

Financial Services rendered on behalf of other Departments and organisations and the 'Revenue' is on account of sale of postal articles, commission on money orders and Indian Postal Orders and receipts

वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष घाटे में होने वाली वृद्धि की प्रकृति को कार्यकारी व्ययों को नियंत्रित करके और साथ ही विभाग की आय में वृद्धि करके रोका जा सकता है। तथापि कार्यकारी व्ययों की अत्यधिक कटौती कर पाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि लगभग 88 प्रतिशत कार्यकारी व्यय वेतन, पेंशन आदि से संबंधित होते हैं जो कि अनिवार्य देयताएं हैं। तथापि, कम्प्यूटरीकरण के मद्देनजर कर्मचारियों की उचित रूप से पुनः तैनाती,

चयनात्मक आधार पर डाक वस्तुओं की शुल्क दरों में पर्याप्त रूप से वृद्धि करके "राजस्व प्राप्ति" वित्तीय सेवाओं के कारण पारिश्रमिक में संशोधन और संगठित विपणन तथा नए-नए उत्पादों के विपणन के लिए नीतिगत तालमेल बिठाकर डाटा पोस्ट, मीडिया पोस्ट, मास मेलिंग, कारपोरेट मनीआर्डर आदि जैसी प्रीमियम सेवाओं पर लाभार्जन को प्रोत्साहित करके सुधार लाया जा सकता है।

तालिका - 12					
1999-2000 में एजेंसी वित्तीय सेवाओं पर कार्यकारी व्यय की वसूली (करोड़ रु० में)					
क्रम सं.	लेखा शीर्ष	1998-99		1999-2000	
		संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक आंकड़े
1.	बचत बैंक और बचत पत्र	1180.40	969.87	1055.00	1055.00
2.	सैनिक पेंशन	0.35	0.42	0.45	0.51
3.	कोयला खनिकों तथा ईपीएफ/परिवार पेंशन तथा विविध सेवाओं का भुगतान	2.00	2.56	2.80	3.42
4.	रेलवे पेंशन का भुगतान	6.00	4.09	4.75	4.59
5.	डाक जीवन बीमा	45.00	40.19	43.00	79.60
6.	सीमा शुल्क वसूली	0.90	0.95	1.10	0.91
7.	महिला समृद्धि योजना	1.50	0.00	18.00	17.30
8.	संयुक्त डाक-तारधरों का टेलीग्राफ हिस्सा	20.00	16.38	18.15	-3.13
9.*	अन्य	3.85	3.29	1.75	4.26
	कुल	1260.00	1037.75	1145.00	1162.46

* इसमें दिल्ली प्रशासन के गैर-डाक टिकटों की बिक्री पर कमीशन, सेना डाक सेवा, लेखे और अन्य सरकारी विभागों से वसूलियां और पूंजी के नामे डाला जाने वाला स्थापना का भाग आदि शामिल है।

8.5 वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान "कार्यकारी व्ययों" और "पूंजीगत परिव्यय" के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्ष के दौरान पूर्णतः और समुचित रूप से उपयोग कर लिया गया था। 71.28 करोड़ रुपए की सरप्लस निधि को समय पर वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित कर दिया गया था। पूंजी तथा राजस्व

खंड के अंतर्गत 4846.33 करोड़ रुपए के कुल बजट में से समग्र बचत केवल 2.14 करोड़ रुपए थी जो लगभग नगण्य थी जैसा तालिका 13 में दर्शाया गया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्रभावो बजट नियंत्रण और मासिक आधार पर व्यय की स्थिति पर निगरानी रखने के कारण संभव हो सकी।

from other premium services etc. The earnings of the Department are on the lower side in comparison to the working expenses incurred. This has resulted in gradual increase in deficit and corresponding budgetary support from the Ministry of Finance. The trend of increasing deficit every year can be arrested by controlling working expenses and also by increasing the earnings of the Department. Substantial reduction in working expenses is not practicable as nearly 88% working expenses relating to salary, pension etc. are in the form of committed liabilities. However, im-

provement can be brought about by judicious redeployment of manpower in the wake of computerisation, through 'Revenue receipts' by adequately increasing tariff rates of postal articles on a selective basis, revision of remuneration on account of financial services and encouraging profit earning on premium services, like Data Post, Media Post, Mass Mailing, Corporate Money Orders, etc. through concerted marketing and forging strategic alliances for marketing innovative products.

Table 12
Recovery of Working Expenses on account of Agency/Financial Services in 1999-2000 (Rs. in crore)

Sl. No.	Head of Account	1998-99		1999-2000	
		RE	Actuals	RE	Actuals
1.	Saving Bank & Saving Certificate	1180.40	969.87	1055.00	1055.00
2.	Military Pension	0.35	0.42	0.45	0.51
3.	Payment of Coal Miners and EPF/ Family Pension & Misc. Services	2.00	2.56	2.80	3.42
4.	Payment of Railway Pension	6.00	4.09	4.75	4.59
5.	Postal Life Insurance	45.00	40.19	43.00	79.60
6.	Custom Duty realisation	0.90	0.95	1.10	0.91
7.	Mahila Samridhi Yojana	1.50	0.00	18.00	17.30
8.	Telegraph Share of combined offices	20.00	16.38	18.15	(-) 3.13
9*	Others	3.85	3.29	1.75	4.26
	Total	1260.00	1037.75	1145.00	1162.46

* This includes Commission on sale of Non-Postal stamps of Delhi Administration, Recoveries from Army Postal Services, Accounts and other Government Departments and share of Establishment debitible to capital, etc.

8.5 The funds made available by the Ministry of Finance for 'Working Expenses' and 'Capital Outlay' during the year were fully and appropriately utilised during the year. The surplus funds to the tune of Rs.71.28 crores were surrendered in time to the Ministry of Finance. Under Capital & Revenue

Section, the overall saving out of the total budget of Rs.4846.33 crores was only Rs.2.14 crores which was very nominal as shown in Table 13. This appreciable achievement was possible by effective budgetary control and by monitoring progress of expenditure on month to month basis.

तालिका - 13

1999-2000 के दौरान अभ्यर्पित निधियां तथा बचत

(करोड़ रु० में)

व्यय की प्रकृति	अनुपूरक अनुदान सहित बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	अधिक (+) बचत (-)	अभ्यर्पित राशि	बचत
3201 कार्यकारी व्यय	4835.53	4778.40	(-) 57.13	56.5	(-) 0.63
5201 पूंजीगत परिव्यय	84.22	67.93	(-) 16.29	14.78	(-) 1.51
कुल	4919.75	4846.33	(-) 73.42	71.28	(-) 2.14

पूंजीगत परिव्यय

8.6 वर्ष 1999-2000 में नियत परिसंपत्तियों पर 68.09 करोड़ रुपए का व्यय हुआ जबकि पिछले वर्ष इस पर 56.46 करोड़ रुपए व्यय हुआ था। यह अत्यधिक व्यय आरएमएस वैनों के मशीनीकरण, आधुनिकीकरण, निर्माण और इसके ढांचे में परिवर्तन जैसे कार्यकलापों के कारण हुआ। वर्ष के अंत में नियत परिसंपत्तियों पर पूंजीगत मूल्य बढ़कर 952.51 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष के अंत तक निवल प्रणामी नियत परिसंपत्ति मूल्य 791.65 करोड़ रुपए हो गया।

सेवाओं की लागत

8.7 सामाजिक आर्थिक अवसंरचना के अत्यावश्यक घटक के रूप में देश के विभिन्न भागों और इसके लोगों के बीच अपेक्षित संपर्क स्थापित करने में डाक सेवाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संभावित सामाजिक उत्तरदायित्व और ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सेवाओं को आधुनिकीकृत करने हेतु राजस्व अर्जित करने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि व्यावसायिक/वाणिज्यिक

क्षेत्रों द्वारा प्रमुख रूप से प्रयुक्त सेवाओं को काफी अधिक आर्थिक सहायता न दी जाए, विभिन्न सेवाओं के डाक शुल्क में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

8.8 तालिका 14 से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश डाक सेवाएं घाटे में चल रही हैं। छह सेवाओं यथा पंजीकरण, मनीआर्डर, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पंजीकृत समाचार पत्रों का घाटा विभाग के वर्ष 1999-2000 (प्रायोजना) के कुल घाटे का लगभग 74.74% बनता है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए अनुमोदित वित्तीय पैकेज, महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनात्मक खर्चों में वृद्धि के कारण विभिन्न डाक सेवाओं की लागत में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1999-2000 (प्रायोजना) के कुल प्रायोजित घाटे में से डाक नेटवर्क पर दी गई आर्थिक सहायता लगभग 33% है। अपेक्षाकृत अधिक यथार्थपरक स्थिति दर्शाने के लिए ग्रामीण नेटवर्क पर यह आर्थिक सहायता जो एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, उचित रूप से डाक घाटे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।

Table 13
Funds Surrendered and Savings during 1999-2000

(Rs. in crore)

Nature of Expenditure	Budget Est. including Suppl. Grant	Actual Expenditure	Excess (+)/ Saving (-)	Amount Surrendered	Savings
3201 Working Expenses	4835.53	4778.4	(-) 57.13	56.5	(-) 0.63
5201 Capital Expenditure	84.22	67.93	(-) 16.29	14.78	(-) 1.51
Total	4919.75	4846.33	(-) 73.42	71.28	(-) 2.14

Capital Outlay

8.6 The expenditure on fixed assets in the year 1999-2000 was Rs. 68.09 crores as against Rs.56.46 crores in the previous year. The excess expenditure is attributable to activities like mechanisation and modernisation and fabrication and remodelling of RMS vans. The value of Capital on fixed assets rose to Rs.952.51 crores at the end of the year. The net progressive fixed asset value upto the end of the year was Rs.791.65 crores.

Cost of Services

8.7 The postal services as an essential element of the socio-economic infrastructure have a significant and important role in providing the required connectivity among various parts of the country and its people. Keeping in view this eventual social obligation and the need for generating revenues to modernise the services for meeting the needs of customers and the need to ensure that services predominantly

utilised by business/commercial sectors do not enjoy too high a level of subsidy, the postal tariff of various services are revised from time to time.

8.8 It may be seen from the table 14 that most of the postal services are in deficit. The deficit of six services namely, Registration, Money Order, Postcard, Inland Letter Card and Registered Newspapers constitutes about 74.74% of the total deficit of the Department for the year 1999-2000 (projection). The cost of various postal services has escalated significantly due to the implementation of the recommendations of the Vth Pay Commission, financial package approved for Extra-departmental agents, grant of additional installment of dearness allowance and increase in other operational expenses. Out of the total projected deficit for the year 1999-2000(projection), the subsidy on the postal network is approximately thirty three per cent. In order to give a more realistic picture, this subsidy on rural network which is a social responsibility, should appropriately not form a part of the postal deficit.

तालिका - 14
सेवाओं की लागत (रुपयों में)

सेवाएं	1998-99 (वास्तविक)		1999-2000 (प्रायोजना)	
	औसत लागत	औसत राजस्व	औसत लागत	औसत राजस्व
1. पोस्टकार्ड	4.76	0.25	4.53	0.25
2. मुद्रित पोस्टकार्ड	4.77	1.50	4.53	1.92
3. प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	4.81	2.58	4.63	3.83
4. पत्र कार्ड (अंतर्देशीय पत्र)	4.75	1.29	4.49	1.92
5. पत्र	5.54	4.97	5.20	5.35
पंजीकृत समाचार पत्र (6 एवं 7)				
6. एकल	6.65	0.26	5.88	0.26
7. बंडल	10.95	0.51	11.39	0.66
बुक पोस्ट (8, 9 एवं 10)				
8. बुक पैटर्न एवं सैम्पल पैकेट	6.70	3.60	7.05	8.92
9. मुद्रित पुस्तकें	11.13	2.42	12.63	2.43
10. अन्य पत्रिकाएं	10.63	1.95	12.59	7.01
11. पावती	4.45	1.58	4.11	2.00
12. पार्सल	46.31	34.46	44.92	45.05
13. पंजीकरण	26.24	11.17	26.91	13.67
14. स्पीड पोस्ट	35.65	46.62	28.56	55.13
15. मूल्यदेय डाक	20.76	2.75	22.31	4.53
16. बीमा	35.62	75.32	38.44	78.82
17. मनीआर्डर	40.18	18.65	36.23	18.27
18. तार मनीआर्डर	51.49	20.65	42.69	20.27
19. भारतीय पोस्टल आर्डर	17.46	1.02	15.46	2.06
20. विदेश डाक	10.45	13.49	10.23	16.41
* 21. बचत बैंक	19.53	15.22	20.78	16.74
22. महिला समृद्धि योजना (प्रति खाला)	13.78	22.49	14.68	22.49
* 23. बचत पत्र एवं किसान विकास पत्र	35.87	20.61	38.22	22.67
* 24. इंदिरा विकास पत्र	10.05	5.47	8.24	6.02

* ये सेवाएं लाभ-हानि रहित आधार पर प्रदान की जाती हैं। विभेद संबंधी मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ पत्राचार चल रहा है।

Table 14
Cost of Services (in Rs.)

Services	1998-99 (Actual)		1999-2000 (Projection)	
	Average Cost	Average Revenue	Average Cost	Average Revenue
1. Post Card	4.76	0.25	4.53	0.25
2. Printed Post Card	4.77	1.50	4.53	1.92
3. Competition Post Card	4.81	2.58	4.63	3.83
4. Letter Card(Inland Letter)	4.75	1.29	4.49	1.92
5. Letter	5.54	4.97	5.20	5.35
Registered Newspapers (6 & 7)				
6. Single	6.65	0.26	5.88	0.26
7. Bundle	10.95	0.51	11.39	0.66
Book Post (8, 9 & 10)				
8. Book Pattern & Sample Packet	6.70	3.60	7.05	8.92
9. Printed Books	11.13	2.42	12.63	2.43
10. Other Periodicals	10.63	1.95	12.59	7.01
11. Acknowledgement	4.45	1.58	4.11	2.00
12. Parcel	46.31	34.46	44.92	45.05
13. Registration	26.24	11.17	26.91	13.67
14. Speed Post	35.65	46.62	28.56	55.13
15. Value Payable Post	20.76	2.75	22.31	4.53
16. Insurance	35.62	75.32	38.44	78.82
17. Money Order	40.18	18.65	36.23	18.27
18. Telegraphic Money Order	51.49	20.65	42.69	20.27
19. Indian Postal Order	17.46	1.02	15.46	2.06
20. Foreign Mail	10.45	13.49	10.23	16.41
*21. Savings bank	19.53	15.22	20.78	16.74
22. Mahila Smridhi Yojana per A/c	13.78	22.49	14.68	22.49
*23. Savings Certificates & Kisan Vikas Patra	35.87	20.61	38.22	22.67
*24. Indira Vikas Patra	10.05	5.47	8.24	6.02

* These services are being rendered on a no profit no loss basis. The matter regarding the differential is under correspondence with Ministry of Finance.

मानव संसाधन विकास

9.1 किसी भी संगठन की शक्ति उससे जुड़े व्यक्तियों में निहित होती है। इस 2,90,000 कर्मचारियों की जनशक्ति वाले विभाग के पास सुविकसित आधारभूत प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध है। यह विभाग मानव संसाधन विकास पर निरंतर सर्वाधिक ध्यान देता रहा है जिसे डाक प्रचालनों में प्रौद्योगिकी के समावेश की दृष्टि से हाल के वर्षों में और अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। इसने प्रबंध एवं प्रचालन के तथा अन्य कर्मचारियों की दक्षता के निरंतर उन्नयन और उनका व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने के प्रयोजन से ऑन-द-जॉब और संस्थागत, दोनों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है।

प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचा

9.2 विभाग के प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं :

- (1) पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद; और
- (2) दरभंगा, मदुरै, मैसूर, सहारनपुर और बडोदरा स्थित क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र।

पोस्टल स्टाफ कालेज

9.3 गाजियाबाद स्थित पोस्टल स्टाफ कालेज विभाग के प्रबंधकीय संवर्गों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शीर्ष प्रशिक्षण संस्था है। इस कालेज का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक सेवा और डाक सेवा समूह "ख" के अधिकारियों में वृत्तिक ज्ञान, दक्षता और आचार-व्यवहार का विकास करना है ताकि वे डाक प्रणाली को अधिक कार्यकुशल और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बना सकें। इस दृष्टि से सेवा में भर्ती के समय और सेवाकाल के दौरान उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। डाक सेवाओं के प्रबंध क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा पोस्टल डाटा बैंक और डाक्युमेंटेशन केन्द्रों की स्थापना करना भी कालेज का उद्देश्य है।

9.4 यह कालेज यूनिवर्सल पोस्टल यूनिजन (यू.पी.यू.) एशियन पैसिफिक पोस्टल कालेज, बैंकाक (ए.पी.पी.टी.सी.) के परामर्श पर तथा दक्षेस देशों के मध्य हुए करार के अंतर्गत उन देशों के डाक प्रशासनों से संबंधित अधिकारियों के लाभ के लिए डाक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशाला का आयोजन भी करता है।

9.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कालेज ने 5 प्रवेश (इंडक्शन) तथा 17 सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 505

अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 290 अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

9.6 1.11.1999 से 12.11.1999 तक एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें भारत की ओर से 7 अधिकारियों सहित भूटान, इथोपिया, इरेट्रिया, मलेशिया, नेपाल तथा यमन प्रत्येक के डाक प्रशासन से एक अधिकारी ने भाग लिया।

9.7 विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय डाक सेवा अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है :-

(1) जापान	: 2
(2) स्वीडन	: 1
(3) थाईलैंड (एशिया प्रशांत पोस्टल कालेज)	: 8

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र

9.8 क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य हैं :

- निरीक्षकीय संवर्गों, पर्यवेक्षकों और डाक एवं छंटाई सहायकों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना;
- पर्यवेक्षकों, डाक एवं छंटाई सहायकों, निरीक्षकों, सहायक अधीक्षक डाकघर, पोस्टमास्टर्स आदि को सेवाकालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना; तथा
- विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर तथा साफ्टवेयर प्रणालियों को समझने, उनका प्रचालन करने के लिए अपेक्षित दक्षता और उनकी जानकारी प्रदान करना।

9.9 1999-2000 के दौरान, पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कुल 11,462 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यस्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाएं

9.10 कार्यस्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर कुशलता में वृद्धि करना एक वृहत् कार्यकलाप है। विभाग के पास अब 10,000 से अधिक कर्मचारियों को वार्षिक रूप से इनहाउस प्रशिक्षण देने की मूलभूत व्यवस्था है। पोस्टल स्टाफ कालेज और डाक प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त 16 शहरों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें से छः की स्थापना 1999-2000 के दौरान चंडीगढ़, औरंगाबाद, कालीकट, त्रिवेन्द्रम और कोलकाता में की गई हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 8002 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।



Chapter 9

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

9.1 The strength of an organisation is the strength of its people. The Department with a manpower of 2,90,000 regular employees has a well developed training infrastructure. It has always been giving priority attention to human resource development, which in recent years received added stimulus in view of induction of technology in postal operations. It has worked out extensive training programmes, both on the job as well as institutional, for the managers and operatives and other functionaries for continually upgrading skills and professional competence.

TRAINING INFRASTRUCTURE

9.2 The training infrastructure of the Department consists of the following training institutes:

- (1) Postal Staff College of India, Ghaziabad; and
- (2) Regional Postal Training Centres at Darbhanga, Madurai, Mysore, Saharanpur and Vadodara.

Postal Staff College

9.3 The Postal Staff College of India at Ghaziabad is the apex training institution catering to the training needs of the managerial cadres of the Department. The primary objective of the college is to impart induction as well as in-service training to the officers of the Indian Postal Service and Postal Service Group 'B' with a view to inculcating professional knowledge, skills and attitude to enable them to make the postal system effective and responsive to customers' needs. The College also undertakes research in the spheres of management of postal services. The mandate of the College is also to build up a postal data bank and documentation centre.

9.4 The College also organises workshops on different aspects of the Postal Services at the behest of the Universal Postal Union (UPU), Asian Pacific Postal College, Bangkok (APPC) and under the agreement amongst SAARC countries for the benefit of officers belonging to the postal administrations of these countries.

9.5 During the period under review, the College conducted 5 induction and 17 in-service training programmes, in which 505 officers participated. Besides, 290 officers were imparted training in computers during the period.

9.6 An International Executive Development

Programme was organised from 1.11.1999 to 12.11.1999 with participation of one officer each from the postal administrations of Bhutan, Ethiopia, Eritrea, Malaysia, Nepal and Yemen along with seven officers from India.

9.7 The number of Indian Postal Service officers trained abroad is as under:

(1) Japan	:	2
(2) Sweden	:	1
(3) Thailand (Asian Pacific Postal College)	:	8

Regional Postal Training Centres

9.8 The main objectives of the Regional Postal Training Centres are:

- To impart induction training to the inspectorial cadres, Supervisors and Postal and Sorting Assistants;
- To impart in-service and refresher training to Supervisors, Postal and Sorting Assistants, Inspectors, ASPOs, Postmasters, etc.; and
- To impart the skill and knowledge required to understand and operate computer hardware and software systems relevant to the needs of the Department.

9.9 A total number of 11,462 officials were imparted training during 1999-2000 by the five Regional Training Centres.

Workplace Computer Training Facilities

9.10 Upgradation of skills by imparting training on computer at the workplace is a major activity. The Department has now the infrastructure to train in-house more than 10,000 officials annually. Apart from the Postal Staff College and the Postal Training Centers, Computer Training Laboratories have been setup in 16 cities. Six of these have been setup during 1999-2000 at Chandigarh, Aurangabad, Calicut, Trivandrum and Kolkatta. A total of 8002 officials were imparted training on computers during the year 1999-2000.

अध्याय-10

सतर्कता कार्यकलाप

10.1 यद्यपि विभाग में निष्कलंकता, सत्यनिष्ठता और कार्यकुशलता बनाए रखने का मुख्य उत्तरदायित्व सचिव, डाक विभाग में निहित है, किंतु उपमहानिदेशक (सतर्कता) विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता संबंधी सभी मामलों में सचिव के विशेष सहायक के तौर पर कार्य करते हैं और वे डाक विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

10.2 मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता मामलों को देखने के अलावा संवेदनशील स्थानों का नियमित और अचानक निरीक्षण करने, ऐसे कार्यविधियों की समीक्षा करने और दोष रहित बनाने में, जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की आशंका मालूम पड़ती हो और विभाग और इसके फील्ड कार्यालयों में भ्रष्टाचार और दूसरे प्रकार के अनाचारों की रोकथाम, इनका पता लगाने और दंड देने के लिए भी जवाबदेह हैं।

10.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसार सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :-

- (क) विभागीय जांच पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना।
- (ख) भ्रष्टाचारियों को कारगर सजा देना।
- (ग) शिकायत की अनिवार्य रूप से पावती देकर उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

10.4 निवारक सतर्कता कार्यक्रम पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता रहा। क्षेत्र के अधिकारियों से लगातार यह अनुरोध किया गया कि वे इस प्रयोजन से विशेष रूप से तैयार की गई प्रश्नावली का नियमित रूप से प्रयोग कर अचानक निरीक्षण करें।

10.5 विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार किए

गए भ्रष्टाचार निरोधी उपायों की कार्ययोजना तैयार करता है तथा उसे कार्यान्वित करता है। इस संबंध में उक्त विभाग को एक तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती है।

10.6 प्रधानमंत्री कार्यालय के भ्रष्टाचार निरोधी सेल से प्राप्त 70 शिकायतों (31.3.2000) से 38 शिकायतों का निपटान कर दिया गया।

10.7 उप महानिदेशक (सतर्कता) के अधीन कार्यरत केन्द्रीय सतर्कता दल देशभर के डाकघर और रेल डाक सेवा कार्यालयों में आकस्मिक सतर्कता जांच करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान देश भर में 17.84 लाख रुपए के राजस्व की चोरी का पता चला और उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

10.8 01.4.1999 से 31.3.2000 तक की अवधि के सतर्कता कार्यकलाप का सांख्यिकीय सार

1. दंडित अधिकारियों की संख्या			
	(क) बड़ा दंड	अधिकारी	- 06
		अन्य कर्मचारी	- 243
	(ख) लघु दंड	अधिकारी	- 04
		अन्य कर्मचारी	- 08
2. जांच की गई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई रिपोर्टों (सीबीआई मामलों को छोड़कर) की संख्या			- 41
3. परामर्श के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई सीबीआई रिपोर्टों की संख्या			- 02
4. किए गए आकस्मिक निरीक्षणों की संख्या			- 11285

Chapter 10

VIGILANCE ACTIVITIES

10.1 The primary responsibility for the maintenance of purity, integrity and efficiency in the Department vests in the Secretary, Department of Posts, while the Deputy Director General(Vigilance) is the Chief Vigilance Officer (CVO) of the Department. The CVO acts as the Special Assistant to the Secretary in all matters pertaining to Vigilance and provides a link between the Department of Posts and the Central Vigilance Commission (CVC).

10.2 Besides dealing with Vigilance cases, the CVO is also responsible for arranging regular and surprise inspections of sensitive spots, review and streamlining of procedures which appear to afford scope for corruption or misconduct and for initiating other measures for prevention, detection and punishment of corruption and other malpractices in the Department and its field offices.

10.3 Several measures have been initiated for improving vigilance administration as per the initiatives taken by the CVC. Some of these important initiatives are as follows:

- (a) Fixing of time limits in departmental inquiries.
- (b) Effective punishment of the corrupt.
- (c) Bringing in accountability by compulsorily giving receipt of complaint.

10.4 Preventive Vigilance Programme continued to receive greater attention. Officers in the field were constantly impressed upon to conduct surprise checks regularly using questionnaire specially devised for the purpose.

10.5 The Department also pursues and implements action plan on anti-corruption measures drawn up by the Department of Personnel & Training. A quarterly report in this regard is sent to that Department.

10.6 Out of 70 complaints received (up to 31.3.2000) from anti-corruption cell of PMO 38 were disposed off.

10.7 The Central Vigilance Squad working under DDG(Vigilance) undertakes surprise vigilance checks in Post Offices and RMS Offices across the country. During the year 1999-2000 leakage of revenue amounting to Rs.17.84 lakhs was detected across the country and remedial action taken

10.8 STATISTICAL SUMMARY OF VIGILANCE ACTIVITIES FOR THE PERIOD 01.4.1999 TO 31.03.2000

1. Number of officers punished with			
(a) Major penalty	Officers	-	06
	Other Staff	-	243
(b) Minor penalty	Officers	-	04
	Other Staff	-	08
2. Number of reports examined and sent to CVC (other than CBI cases)			
- 41			
3. Number of CBI reports referred to CVC for advice			
- 02			
4. Number of surprise inspections carried out			
- 11285			

अध्याय-11

अन्य कार्यकलाप

स्टाफ संबंध

11.1 संगठनात्मक दक्षता तथा कर्मचारी के ऊँचे मनोबल हेतु विवादमुक्त औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए कर्मचारी संबंध को सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। संबोधाधीन वर्ष के दौरान विभाग का यह प्रयास रहा है कि कर्मचारियों को यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ सद्भावपूर्ण और सार्थक संबंध बनाए रखे जाएं।

11.2 इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सिविल सेवा (सर्विस एसोसिएशन को मान्यता) नियमावली और अतिरिक्त विभागीय एजेंट (एसोसिएशन को मान्यता) नियमावली के अंतर्गत यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के लिए पुनर्सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

11.3 एफ.एन.पी.ओ., एन.एफ.पी.ई. और बी.पी.ई.एफ. के प्रति-निधियों के साथ बैठकें/साक्षात्कार आयोजित किए गए थे।

11.4 अखिल भारतीय डाक स्टेनोग्राफर एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की गई।

कर्मचारी कल्याण-डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड के कार्यकलाप

11.5 डाक सेवा स्टाफ कल्याण बोर्ड का उद्देश्य विभाग के कर्मचारियों के कल्याण, खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देना, उनका विकास और उन्हें संगठित करना है। बोर्ड को इस प्रयोजनार्थ भारत की संचित निधि से अनुदान प्राप्त होता है। स्टाफ की ओर से स्वैच्छिक अंशदान तथा खेल एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों के जरिये भी अधीनस्थ संघटकों द्वारा धन प्राप्त किया जाता है।

11.6 कल्याण बोर्ड की निधि का प्रयोग खेल-कूद, मनोविनोद जैसे कार्यकलापों में, बीमारी, मृत्यु और प्राकृतिक विपदाओं के मामले में वित्तीय सहायता में, आमोद-यात्राओं के लिए सब्सिडी देने में, विकलांग कर्मचारियों तथा उनके बच्चों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, शिशु सदनो आदि को अनुदान देने में किया जाता है। 1999-2000 के दौरान, इस प्रयोजनार्थ सरकार से 2.47 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी और 3.43 करोड़ रुपए खर्च हुए।

11.7 वर्ष के दौरान, विभागीय अधिकारियों सहित अतिरिक्त

विभागीय एजेंटों और अनियत मजदूरों के संबंध में मृत अधिकारी के शोक संतप्त परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि संशोधित करके बढ़ा दी गई। उड़ीसा के चक्रवात के मामले में प्रभावित कर्मचारियों को एकवारगी वित्तीय सहायता के रूप में दी गई राशि को विभागीय कर्मचारियों के मामले में बढ़ाकर 3,000 रुपए और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के मामले में बढ़ाकर 1500/- रुपए कर दिया गया।

11.8 विभाग में काम कर रही महिला कर्मचारियों की उत्पाड़न संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए डाक निदेशालय और सभी सर्किलों में शिकायत समितियाँ बनाई गईं ताकि इस संबंध में एक पूर्ण तंत्र उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

अवकाश गृह

11.9 कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभार्थ 22 अवकाश गृह पहले से ही चल रहे हैं। वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश में इटानगर में एक नया अवकाश गृह खोला गया।

खेल-कूद

11.10 1999-2000 के दौरान एथलेटिक्स एवं साइक्लिंग, बास्केट-बाल, बैडमिंटन, श्रेष्ठ शारीरिक सौष्ठव, शतरंज एवं कैरम, क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, कबड्डी, पावरलिफ्टिंग, टेबल टेनिस, बॉलीबाल, भारोत्तोलन और कुश्ती में अखिल भारतीय डाक सेवा टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक बैठक भी आयोजित की गई।

इन हाउस पत्रिका—डाक पत्रिका

11.11 प्रत्येक तीसरे माह प्रकाशित होने वाली विभाग की डाक पत्रिका (एक संस्थागत पत्रिका) द्विभाषी है। इस पत्रिका से कर्मचारियों को विभाग की पालिसियों, समस्याओं एवं विकास संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। इस पत्रिका में विभाग के कर्मचारियों के लेख/कहानियाँ/कविता आदि छपने के कारण यह विभाग में मौजूद प्रतिभा के प्रदर्शन का एक सशक्त मंच है।

11.12 डाक विभाग का यह प्रयास रहा है कि इस पत्रिका को सूचना एवं आंतरिक विपणन दोनों का उपकरण बनाया जा सके। इसके मनोरंजन बनाने के लिए, विभिन्न विषयों पर लेख शामिल किए जाते हैं। प्रतिवेदित वर्ष की इस पत्रिका में सहस्राब्दि 2000 और इंडिपेक्स एशियाना 2000 के विशेष कवर के साथ



Chapter 11

OTHER ACTIVITIES

Staff Relations

11.1 Staff relations is reckoned as the most important means of maintaining conflict-free industrial relations for organisational efficiency as also for high degree of employee morale. During the year under review, the Department endeavoured to maintain harmonious and meaningful relations with the Staff Unions/Associations of its employees.

11.2 During the period, the process of re-verification under the Central Civil Services (Recognition of Service Association), Rules and Extra Departmental Agents (Recognition of Association), Rules was initiated for recognition of the unions.

11.3 Meetings/interviews were held with the representatives of FNPO, NFPE and BPEF.

11.4 All India Postal Stenographers' Association was granted recognition.

Staff Welfare – Activities of Postal Services Staff Welfare Board

11.5 The objective of the Postal Services Staff Welfare Board is to promote, develop and organise welfare, sports and cultural activities for the employees of the Department. The Board receives grants-in-aid for this purpose from the Consolidated Fund of India. Voluntary contributions from the staff and collection through sports and cultural activities are also received by the subordinate formations.

11.6 The funds of the Welfare Board are utilised for activities like sports, recreation activities, financial assistance in cases of illness, death and natural calamities, educational scholarships, subsidy for excursion trips, grants to help handicapped staff and their children, vocational training centres, creches etc. During 1999-2000, an amount of Rs. 2.47 crores was received from the Government for this purpose and Rs.3.43 crores spent.

11.7 During the year, the quantum of financial assistance to the bereaved families of the deceased

officials was revised upwards both for Departmental Officials as well as EDAs and casual labourers. In case of super cyclone in Orissa financial assistance for the affected employees was increased to Rs.3000/- in case of Departmental officials and Rs.1500/- in case of EDAs as a one time measure.

11.8 Complaints Committees have been constituted in the Postal Directorate as well in all circles with a view to make available a complete mechanism for redressal of gender grievances for women employees working in the Department.

Holiday Homes

11.9 During the year, a new Holiday Home was opened at Itanagar in Arunachal Pradesh. 22 Holiday Homes already existing for the benefit of employees and their families.

Sports

11.10 During 1999-2000, All India Postal Services Sports Tournaments in Athletics and Cycling, Basketball, Badminton, Best Physique, Chess and Carrom, Cricket, Football, Hockey, Kabaddi, Powerlifting, Table Tennis, Volleyball, Weightlifting and Wrestling were organised. An All India Cultural meet was also organized.

In House Magazine – Dak Patrika

11.11 Dak Patrika is a quarterly magazine (in-house journal) of the Department, published bilingually. This magazine keeps the employees informed of the policies, problems and developments in the Department. This is also an effective platform for displaying the talents existing within the Department by publishing their articles/stories/poems. etc.

11.12 It has been the endeavour to make this magazine both informative as well as a tool for internal marketing. To make it engrossing, articles on variegated subjects are included. The magazine for the reporting year contains special covers of millennium 2000 and Indonex Asiana 2000 including special articles on

टाइटेनिक डाक, भारत में फिलैटली आंदोलन और अवध (लखनऊ) डाक सर्किल पर विशेष संदर्भ देते हुए 1873-74 के प्रारंभिक भारतीय डाक-टिकटों की अखिल भारतीय शृंखला के विरूपण अंग्रेजी में और राजभाषा हिन्दी पर विशेष लेख थे।

चिकित्सा सुविधाएं

11.13 विभाग अपने कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को बहुत महत्व देता है। डाक विभाग 48 नगरों/शहरों में 56 डाक एवं तार औषधालय एवं 7 प्राथमिक उपचार केन्द्र चलाता है। दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को भी इन औषधालयों से सुविधा प्रदान की जाती है। 1999-2000 के दौरान दवाइयों की कीमत सहित इन औषधालयों को चलाने में हुआ व्यय 26.86 करोड़ रुपए था। अन्य स्थानों पर जहाँ डाक एवं तार औषधालय नहीं है, वहाँ डाक विभाग के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों या प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंटों की सेवाओं का उपयोग करते हैं।

अनुकम्पा नियुक्तियां

11.14 सेवा में रहते हुए विभागीय कर्मचारियों और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की मृत्यु होने पर और सेवारत कर्मचारियों की अशक्तता के कुछ मामलों में विभाग पात्र मामलों में संबंधित कर्मचारियों के परिवार के किसी एक सदस्य को सामान्य भर्ती नियमों में छूट देकर उचित श्रेणी में नौकरी प्रदान करता है।

सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व

11.15 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार विभाग के विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति के 54828, अनुसूचित जनजाति के 19138, 2724 भूतपूर्व सैनिक, 87 विकलांग भूतपूर्व सैनिक तथा 33166 महिलाएं कार्यरत हैं। (देखें तालिका सं 17 एवं 18)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के संबंध में भारत सरकार के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जाता है।

स्थापना

11.16 वर्ष 1999-2000 के दौरान, जलाहली उपडाकघर का प्रधान डाकघर में उन्नयन कर दिया गया।

11.17 24 अधिकारियों को भारतीय डाक सेवा समूह "क" के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया और 8 एस.ए. जी. स्तर के अधिकारियों को भारतीय डाक सेवा समूह "क" के उच्च प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया।

11.18 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 1998 के परिणामों के आधार पर 12 उम्मीदवारों को भारतीय डाक सेवा (समूह "क") के कनिष्ठ समयमान में नियुक्त किया गया।

11.19 सी.एम.एस.ई. 1998 के आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त होने पर 8 डाक्टरों को विभिन्न डाक-तार औषधालयों में तैनात किया गया।

11.20 वर्ष के दौरान 39 अधिकारियों को डाक-सेवा समूह "ख" संवर्ग में पदोन्नत किया गया।

राजभाषा

11.21 केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार विभाग कार्यालय पत्र-व्यवहार में हिन्दी के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया।

11.22 हिन्दी का राजभाषा के बतौर अधिकतम प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सर्किल में एक वर्ष में कम से कम एक बार "राजभाषा सम्मेलन" आयोजित करने की योजना शुरू की गई। वर्ष 1999-2000 के दौरान उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सर्किलों में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए। सर्किलों के सामने आ रही विभिन्न कठिनाइयों को सुलझाने के लिए भी कदम उठाए गए।

11.23 राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, राजभाषा नीति तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए विभाग के विभिन्न कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया है और दस अधीनस्थ कार्यालयों का इस वर्ष निरीक्षण किया गया।

11.24 विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए एक "अखिल भारतीय डाक विभाग राजभाषा शील्ड योजना" शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, तीन सर्किलों को, जो "क", "ख", "ग" क्षेत्रों में स्थित हैं, हिन्दी में अधिकतम काम करने के लिए तीन चल शील्ड तथा 5000/- रुपए प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा, "क" तथा "ग" क्षेत्र में स्थित सर्किलों को क्रमशः 4000/- रु. तथा 3000/- रु. के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वर्ष 1998-99 में मध्य प्रदेश,

Titanic Mail, Philately movement in India, the All India series of Early Indian Cancellation of 1873-74 with special reference to Oudh (Lucknow) Postal Circle in English and special articles on Rajbhasha Hindi.

Medical facilities

11.13 The Department attaches great importance to the provision of medical facilities for its employees and their family members. The Department of Posts runs 56 P&T Dispensaries and 7 First-aid Centres in 48 cities/towns. The employees of the Department of Telecommunications are also served by these dispensaries. The expenditure incurred on the running of the dispensaries, including the cost of medicines, during 1999-2000 was Rs.26.86 crores. In other places where P & T dispensaries are not available, the employees avail the services of CGHS dispensaries or Authorised Medical Attendants.

Compassionate Appointments

11.14 In the event of the death of departmental officials and extra-departmental agents while in service, and in certain cases of invalidation of officials in service, the Department provides appointment in the appropriate category to a family member of the official concerned, in relaxation of normal recruitment rules in really deserving cases.

Representation of SCs & STs Service

11.15 As on 31.3.2000, there are 54,828 SC, 19,138 ST, 2,724 Ex-servicemen, 87 Disabled Ex-servicemen and 33,166 Women employees in various grades in the Department (see Table No. 17 & 18). The Government of India orders in respect of SC/ST etc. are being implemented scrupulously.

Establishment

11.16 Upgradation of Jalahalli Sub Post Office into Head Post Office was done during the year 1999-2000.

11.17 24 officers have been promoted to Junior Administrative Grade of IPS Group 'A' and 8 officers of SAG level to Higher Administrative Grade of the Indian Postal Service (IPS) Group 'A'.

11.18 On the basis of the results of Civil Services Examination, 1998 conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), 12 candidates were appointed to the Junior Time Scale (JTS) of the Indian Postal Service (Group "A") .

11.19 Eight Doctors have been posted in different P&T Dispensaries on appointment to the post of Medical Officers in Central Health Services on the basis of CMSE - 1998 .

11.20 39 officers have been promoted to Postal Service Group 'B' cadre during the year.

Official Language

11.21 In keeping with the policy of the Central Government, the Department has been making sustained efforts to ensure the optimum use of Hindi in official correspondence. To ensure the implementation of Official Language Act, 1963 and Rules made thereunder, an Official Language Implementation Committee was constituted at the headquarters and also in all the subordinate offices.

11.22 With a view to ensure the maximum progressive use of Hindi as Official Language, a scheme of organising "RAJBHASHA SAMMELAN" in every Circle, at least once a year, was introduced. Rajbhasha Sammelans were organised in Orissa, Gujarat, Karnataka, West Bengal and Delhi Circles during the year 1999-2000. Steps were also taken to solve the various difficulties faced by the Circles.

11.23 With a view to reviewing the implementation of the Official Language Act and rules made thereunder, the Official Language Policy and Annual Programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, inspections of various offices of the Department have been carried out from time to time and ten subordinate offices were inspected during the year.

11.24 The Department has introduced an "AKHIL BHARTIYA DAK VIBHAG RAJBHASHA SHIELD YOJANA" for its subordinate offices. Under this scheme, three running shields and a cash prize of

गुजरात तथा कर्नाटक सर्किल को "क", "ख", "ग" क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत अधिकतम कार्य करने के लिए क्रमशः प्रथम पुरस्कार दिया गया। क्षेत्र "क" और "ग" में क्रमशः उत्तर प्रदेश सर्किल और केरल सर्किल को द्वितीय पुरस्कार दिया गया और क्षेत्र "क" और "ग" में क्रमशः दिल्ली सर्किल और पश्चिम बंगाल सर्किल को तृतीय पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार सचिव (डाक) द्वारा 4.5.2000 को डाक भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिए गए।

11.25 विभाग द्वारा सर्किल कार्यालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों को हिन्दी पुस्तकों की खरीद हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित राशि प्रदान की जाती है।

11.26 हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत मुख्यालयों और सर्किलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के संबंध में अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

11.27 डाक निदेशालय में 11.10.99 से 10.11.99 तक "हिन्दी माह" आयोजित किया गया। सचिव (डाक) द्वारा 14 सितम्बर, 1999 को डाक भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में "हिन्दी दिवस" का उद्घाटन किया गया। अधिकारियों ने "हिन्दी माह" में उत्साह से भाग लिया। इस अवधि में हिन्दी में अधिकतम काम करने के लिए हिन्दी एवं अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के 22 अधिकारियों / कर्मचारियों को सचिव (डाक) द्वारा 4.5.2000 को डाक भवन में आयोजित एक समारोह में नकद पुरस्कार दिया गया।

11.28 निदेशालय में 20.10.99 से 22.10.99 तक सहायकों के लिए हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। 22 सहायकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

11.29 डाक विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 14.9.99 से 14.9.2000 तक राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। इस पूरी अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग के प्रचार को

बढ़ावा देने के अपने विशिष्ट कार्य के लिए डाक विभाग ने इस वर्ष भी "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड" जीती।

निरीक्षण

11.30 निदेशालय के निरीक्षण संगठन ने 1999-2000 के दौरान 2 सर्किल कार्यालयों और 3 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया।

जन शिकायत

11.31 1999-2000 के दौरान विभाग को 8,14,260 जन शिकायतों के मामले प्राप्त हुए और विभाग ने पिछले वर्ष के अनिर्णित मामलों को मिलाकर 8,20,763 मामलों का निपटारा कर दिया। पूरे वर्ष में शिकायतों को शरीयता आधार पर निपटाने के उपाय किए गए। वर्ष 1999-2000 में प्रत्येक सर्किल में त्रैमासिक डाक अदालतों का आयोजन किया गया जिनमें 1143 शिकायतें प्राप्त हुईं। पिछले वर्ष की अनिर्णित शिकायतों को मिलाकर 1130 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। मनीआर्डर, पंजीकरण और बचत बैंक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निपटारे पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए।

11.32 ग्राहक सेवा केन्द्रों के कम्प्यूटीकरण का कार्यक्रम जारी रहा और वर्ष 1999-2000 के दौरान 55 और केन्द्रों को कवर किया गया। अतः 31.3.2000 तक संपूर्ण भारत में 182 ग्राहक सुविधा केन्द्रों को कम्प्यूटीकृत किया जा चुका है।

11.33 तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा जून, 1999 तक डाक निदेशालय, दिल्ली में प्रत्येक बृहस्पतिवार लोक सुनवाई आयोजित की जाती रही। अब स्थानीय प्रेस के माध्यम से व्यापक प्रचार करके ये साप्ताहिक लोक सुनवाई संबंधित सर्किल मुख्यालय में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा आयोजित की जाती हैं।

डाक भवन

11.34 1999-2000 के दौरान 133 स्टाफ क्वार्टरों, 2 प्रशासनिक कार्यालयों और 35 डाकघर भवनों का निर्माण किया गया।*

Rs.5,000/- are awarded every year to each of the three circles located in regions "A", "B" and "C" for doing the maximum work in Hindi in the respective region. Besides, second and third prizes of Rs.4000- and 3000/- respectively are also awarded to the Circles located in regions "A" and "C". For the year 1998-99, Madhya Pradesh, Gujarat and Karnataka Circles, in region "A", "B" and "C" respectively were awarded first prizes under this scheme for doing maximum official work in Hindi. Uttar Pradesh Circle and Kerala Circle in region "A" and "C" respectively were awarded second prizes while Delhi Circle and West Bengal Circle in Region "A" and "C" respectively were awarded third prizes. These prizes were distributed by the Secretary(Posts) in a function held at Dak Bhawan, New Delhi on 4.5.2000.

11.25 The Department provides funds in every financial year to its Circle Offices and their subordinate offices, for purchase of Hindi books.

11.26 Instructions have been issued regarding provision of training to officers and staff at the Headquarters and the Circles under various schemes initiated under Hindi Teaching Scheme.

11.27 "HINDI MONTH" was organized in the Postal Directorate from 11.10.99 to 10.11.99. 'HINDI DIWAS' was inaugurated by Secretary(Posts) in a function held at Dak Bhawan, New Delhi on 14th September, 1999. Officers also took part in HINDI MONTH with enthusiasm. Twenty Two officers/employees belonging to both Hindi and non-Hindi areas were awarded cash prizes for doing their maximum work in Hindi during this period by Secretary(Posts) in function held at Dak Bhawan, New Delhi on 4.5.2000.

11.28 A Hindi Workshop for Assistants was organized in the Directorate w.e.f. 20.10.99 to 22.10.99. 22 Assistants took part in this Workshop.

11.29 The Golden Jubilee Year of Rajbhasha was observed by the Department of Posts and its sub-

ordinate offices from 14.9.99 to 14.9.2000. During the entire period various competitions were organized. The Department of Posts won "INDIRA GANDHI RAJBHASHA SHIELD" this year also for its outstanding work for the promotion of use of Hindi in official work.

Inspection

11.30 The Inspection Organisation of the Directorate carried out inspection of 2 Circle Offices and 3 Regional Offices during 1999-2000.

Public Grievances

11.31 During 1999-2000, the Department received 8,14,260 cases of public grievances and settled 8,20,763 cases including pending cases of the previous year. Measures to resolve grievances on priority continued throughout the year. Dak Adalats were held quarterly during the year 1999-2000 in each circle where 1143 grievances were received. A total of 1130 grievances were settled including some of the pending complaints of the previous year. Special drives were also organised for focussed attention to early settlement of complaints relating to money order, registration and SB services.

11.32 The programme of Computerization for Customer Care Centers continued and 55 more Centers were covered during the year 1999-2000. Thus till 31.3.2000, 182 Customer Care Centers have been computerized all over India.

11.33 Weekly public hearings were held every Thursday at the Postal Directorate in Delhi by the then Minister of Communications till June, 1999. Such weekly hearings are now being held at respective Circle Headquarters by the CPMsG after giving due publicity through the local press.

Postal Buildings

11.34 During 1999-2000, 133 Staff Quarters, 2 Administrative Office buildings and 35 Post Office buildings were constructed.

अध्याय-12

पूर्वोत्तर में विकासात्मक कार्यकलाप

12.1 सरकार के नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलाप के लिए विशेष पहल की है।

12.2 पहले संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल एक डाक सर्किल द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। तथापि, बाद में क्षेत्र के महत्व पर विचार करते हुए तथा विकासात्मक कार्यकलाप पर ध्यान केन्द्रित करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पूर्ववर्ती सर्किल को दो स्वतंत्र डाक सर्किलों में विभाजित कर दिया गया। इसमें एक असम सर्किल है जो असम राज्य के साथ कोटमिनस है तथा दूसरा पूर्वोत्तर डाक सर्किल है जिसमें छः राज्य-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। प्रत्येक सर्किल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

12.3 असम डाक सर्किल में 3911 डाकघर हैं जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। प्रत्येक डाकघर औसतन 5731 की जनसंख्या को तथा 20.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। पूर्वोत्तर डाक सर्किल का मुख्यालय शिलांग में है और इसके अधिकार क्षेत्र में कुल 2913 डाकघर हैं। प्रत्येक डाकघर औसतन क्रमशः 60.54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और 3121 की जनसंख्या को सेवा उपलब्ध कराता है क्योंकि यह क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ी है तथा जनसंख्या दूर-दूर फैली है इसलिए प्रति कि.मी. सेवित-जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से ज्यादा है।

योजनागत कार्यकलाप

12.4 पूर्व योजनाओं में शुरू किए गए विकासात्मक कार्यक्रमों को नवीनी योजना में और आगे बढ़ाया गया। 1997-98 में, 72.27 करोड़ रुपए के कुल योजना व्यय में से इस क्षेत्र में 5.88 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। 1998-99 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों पर योजना व्यय 8.27 करोड़ रुपया हुआ जो कुल योजना व्यय (73.69 करोड़ रुपए) का 11.22 प्रतिशत था। वर्ष 1999-2000 के दौरान 88.28 करोड़ रुपए के कुल योजना व्यय की तुलना में 6.12 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। वर्ष 2000-2001 के दौरान, वार्षिक योजना के अंतर्गत 12 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न योजना कार्य-कलापों के लिए उद्दिष्ट किए गए हैं। विभाग द्वारा 1999-2000

के दौरान इस क्षेत्र में किए गए मुख्य विकासात्मक कार्य-कलापों का राज्यवार-ब्यौरा निम्नानुसार है :

असम

12.5 राज्य में 24 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा सात विभागीय उपडाकघर खोलकर डाक सुविधाओं का और विस्तार किया गया। 1999-2000 के दौरान दो डाकघरों तथा एक मेल कार्यालय का आधुनिकीकरण भी किया गया। कम्प्यूटरीकरण की सुविधा बढ़ाते हुए, 53 बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनें, 01 वी-सेट स्टेशन, 9 ई.एस.एम.ओ. संस्थापित किए गए। एक ट्रांजिट मेल कार्यालय तथा एक प्रधान रिकार्ड कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण भी किया गया। सात स्पीड पोस्ट केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। जन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए तीन ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। 55 कर्मचारियों को एस.बी. / एस.सी. पुनश्चर्चा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 383 को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एम.एम.एस. गुवाहाटी के लिए पहले खरीदी गई दो टन वाहनों की चैसिस पर "बॉडी बिल्डिंग" का कार्य किया गया। सिलिगुड़ी में एस.पी.एम. क्वार्टर तथा डाकघर भवन, यू.एस. रोड, गुवाहाटी में तथा दक्षिण जुलाननगर में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया। स्टाफ क्वार्टर समस्या में सुधार करने के लिए पोस्टल स्टोर्स डिपो के स्टाफ के लिए सिलचर में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

अरुणाचल प्रदेश

12.6 राज्य में सात अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा एक विभागीय उपडाकघर खोला गया। दो डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया तथा एक ग्राहक सेवा केन्द्र का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। 66 कर्मचारियों को कम्प्यूटर संचालन का प्रशिक्षण दिया गया तथा 21 कर्मचारियों को एस.बी./एस.बी.सी.ओ. पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। रोईंग उपडाकघर में निर्माण कार्य प्रगति पर है। एम.एम.एस. एटा नगर के लिए पहले खरीदे गए एक टाटा 407 चैसिस वाहन पर बॉडी बिल्डिंग का कार्य किया गया। इस अवधि के दौरान बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनें संस्थापित की गईं। मेल के निर्बाध पारेषण के लिए एक मेल मोटर सर्विस (एम.एम.एस.) वैन तथा दो मोपेड (वितरण के लिए) उपलब्ध कराए गए।

Chapter 12

DEVELOPMENTAL ACTIVITIES IN THE NORTH EAST

12.1 In accordance with the policy guidelines of the Government, the Department has taken special initiatives for developmental activities in the North Eastern region.

12.2 The whole of North Eastern region was earlier served by only one postal circle. However, considering the strategic importance of the region and with a view to ensuring focussed attention to the developmental activities, the erstwhile Circle was bifurcated into two independent postal circles – namely the Assam Circle coterminous with the State of Assam and the North Eastern Postal Circle covering the six states of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. Each Circle is under the administrative control of a Chief Postmaster General.

12.3 Assam Postal Circle, which is headquartered at Guwahati has a network of 3911 post offices. On an average, each post office serves a population of 5731 persons and an area of 20.05 Sq.Kms. North Eastern Postal Circle with headquarters at Shillong has within its jurisdiction a total of 2913 post offices. On an average, each post office serves an area and population of 60.54 Sq.Kms. and 3121 persons respectively. Population served per kilometer is more than all India average on account of the fact that this circle is a predominately hilly area and sparsely populated.

Plan Activities

12.4 The developmental programmes initiated in earlier plans were extended further in the Ninth Plan. In 1997-98, with the total plan expenditure of Rs.72.27 crores the expenditure in the region was Rs.5.88 crores. During 1998-99, the Plan expenditure towards developmental activities in the North Eastern region was Rs.8.27 crores, which was 11.22% of the total plan expenditure (Rs.73.69 crores). During the 1999-2000, the expenditure of Rs.6.12 crores was incurred as against the total plan expenditure of Rs.88.28 crores. During 2000-2001, under the Annual Plan Rs.12 crores has been earmarked

for the various plan activities in the North Eastern Region. The details of major developmental activities undertaken by the Department in the region during 1999-2000, statewise, are as follows:

Assam

12.5 Postal facilities were further extended in the state by opening 24 Extra Departmental Branch Offices (EDBOs) and seven Departmental Sub Post Offices. Two Post Offices and one Mail Office were also modernised during 1999-2000. Extending the facility of computerisation, 53 Multi Purpose Counter Machines (MPCMs), 1 VSAT station, 9 ESMOs were installed. One Transit Mail office and one Head Record Office were also computerised. Seven Speed Post Centers have been computerized. Three Customer Care Centers are being set up for attending to public grievances. 55 officials have been imparted SB/SC refresher training course and 383 were imparted computer training. Body building on two chasis of 2 tonne vehicles purchased earlier was carried out for MMS Guwahati. Post Office building and SPMs quarter at Siliguri and staff quarters at U.S. Road Guwahati and South Julannagar were constructed. To ameliorate the housing problem staff quarter were constructed at Silchar for staff of PSD.

Arunachal Pradesh

12.6 Seven Extra Departmental Branch Offices (EDBOs) and one Departmental Sub Office (DSO) were opened in the state. Two Post Office were modernised and one Customer Care Centre was computerized. 66 officials were imparted training for computer operation and 21 officials were imparted SB/SBCO refresher course. Construction work of Roing S.O. is under progress. Body building on one TATA 407 chasis vehicle purchased earlier was carried out for MMS Itanagar. Multi Purpose Counter Machines (MPCMs) were installed during the period. In order to facilitate smooth transmission of mail, one Mail Motor Service (MMS) van and two mopeds (for delivery) were provided.

मणिपुर

12.7 मणिपुर राज्य में दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा एक विभागीय उपडाकघर खोले गए। इसके अतिरिक्त, एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया तथा जनशिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक ग्राहक सुविधा केन्द्र का कम्प्यूटरीकरण भी किया गया। इसके अलावा 67 कर्मचारियों को कम्प्यूटर का तथा 14 को एस.बी. / एस.बी.सी.ओ. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक वी-सेट स्टेशन तथा 12 ई.एस.एम.ओ. स्टेशन भी संस्थापित किए गए। दो स्पीड पोस्ट संकेन्द्रण केन्द्रों का आधुनिकीकरण भी किया गया है। एम.एम.एफ. इम्फाल के लिए काउल चैसिस पर बॉडी बिल्डिंग का कार्य किया गया और इम्फाल प्रधान डाकघर, मोर्च उपडाकघर तथा चन्देल उपडाकघर में 3 डाकघर भवनों तथा इम्फाल में पैलेस कम्पाउंड में कर्मचारी आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है।

मेघालय

12.8 मेघालय राज्य में चार अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और एक विभागीय उपडाकघर खोले गए। एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया। एक वी-सेट स्टेशन और एक ई.एस.एम.ओ. स्टेशन की संस्थापना की गई। दो स्पीड पोस्ट संकेन्द्रण केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। कम्प्यूटर के क्षेत्र में 91 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 30 कर्मचारियों को एस.बी. / एस.बी.सी.ओ. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। नांगस्टाइन डाकघर के लिए एक भवन का निर्माण किया जा रहा है तथा लालचन्द बस्ती में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है।

मिजोरम

12.9 राज्य में तीन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए। आइजोल में एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया तथा एक ग्राहक सेवा केन्द्र स्थापित किया गया। एक स्पीड पोस्ट संकेन्द्रण केन्द्र का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, 67 कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया है तथा 11 कर्मचारियों ने एस.बी./एस.बी.सी.ओ. के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साइतुआल तथा मिलखातियाल उपडाकघर में डाकघरों

के लिए दो भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा वेंगलुई में स्टाफ क्वार्टर का भी निर्माण किया जा रहा है। आइजोल में एक एम.एम.एस. वाहन की खरीद के अतिरिक्त एम.एम.एस. के लिए दो टन क्षमता के पहले खरीदे गए चैसिस सहित दो चैसिस वाहनों पर बॉडी निर्माण का कार्य किया गया।

नागालैंड

12.10 दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों तथा एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 68 कर्मचारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया गया है तथा 18 कर्मचारियों को एस.बी. / एस.बी.सी.ओ. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया है। दो स्पीड पोस्ट संकेन्द्रण केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। जुनहेबोनो उपडाकघर में डाकघर भवनों का निर्माण तथा दीमापुर में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण चल रहा है। कोहिमा में एक नए एम.एम.एस. वाहन की खरीद के अतिरिक्त एम.एम.एस. के लिए दो टन क्षमता वाले दो वाहनों के लिए चैसिस पर बॉडी बिल्डिंग का कार्य किया गया।

त्रिपुरा

12.11 एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 2 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया। एक केन्द्र में "रजिस्ट्रेशन सार्टिंग" को कम्प्यूटरीकृत किया गया। दो स्पीड पोस्ट संकेन्द्रण केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। इसके अलावा कम्प्यूटर के क्षेत्र में 63 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 20 कर्मचारियों को एस.बी. / एस.बी.सी.ओ. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया। धर्मनगर प्रधान डाकघर, मनुषाट उपडाकघर तथा पानीसागर उपडाकघर के लिए तीन भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

सिक्किम

12.12 सिक्किम जो पश्चिम बंगाल सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है, विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रयोजन हेतु नामोद्दिष्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र का ही एक भाग है। वहां दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए। 11 कर्मचारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया गया। रंगोली बाजार तथा मान्गोन में डाकघर भवन तथा एस.पी.एम. क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

Manipur

12.7 Two Extra Departmental Branch Post Offices and one Departmental Sub Post Office were opened in the state of Manipur. Besides, one Post Office was modernised and one Customer Care Centre was also computerized for attending to public complaints. Besides, training was imparted to 67 officials in computer and 14 SB/SBCO refresher courses. One VSAT station and 12 ESMOs stations were also installed. Two Speed Post concentration centers were computerized. Body building on one chasis purchased earlier was carried out for MMS Imphal, 3 post office buildings at Imphal H.O., Morch SO and Chandel S.O. and Staff Quarters at Palace compound in Imphal are under completion.

Meghalaya

12.8 Four Extra Departmental Branch Offices (EDBOs) and one Department Sub Office (DSO) were opened in the State of Meghalaya. One Post Office was modernised. One VSAT station and one ESMO station were installed. Two Speed Post Concentration Centers were computerized. Training was imparted to 91 officials in the area of computers, 30 officials were imparted training for SB/SBCO refresher course. One building is being constructed for Nongstoin Post Office and Staff Quarters at Lalchand Basti are being constructed.

Mizoram

12.9 Three Extra Departmental Branch offices (EDBOs) were opened in the state. One Post Office was modernised and one Customer Care Centre was set up at Aizwal. One Speed Post Concentration Centre has been computerised, 67 officials were imparted computer training and 11 officials had undergone SB/SBCO refresher training. Two buildings are being constructed for post offices at Saitual and

Bhilkhatial S.O. and also Staff Quarters at Venglui. Body building on two chasis vehicles with 2 tonne capacity purchased earlier was carried out for the MMS at Aizwal in addition to purchase of one MMS vehicle.

Nagaland

12.10 Two Extra Departmental Branch offices (EDBOs) and one Post Office were modernised. Further training has been imparted to 68 officials in computers and 18 officials in SB/SBCO refresher courses. Two Speed Post Concentration Centers were computerized. Post Office buildings at Zunheboto S.O. and the Staff Quarters at Dimapur are under construction. Body building on chasis for two vehicles with 2 tonne capacity was undertaken for the MMS at Kohima in addition to one new MMS vehicle being procured.

Tripura

12.11 One Extra Departmental Branch Offices (EDBOs) and two Post Office were modernized. Registration sorting was computerized at one centre. Two Speed Post Concentration Centers were computerized. Besides training has been imparted to 63 officials in the field of computers and 20 officials in SB/SBCO refresher courses. Three buildings are being constructed for Dharmanagar H.O., Manughat S.O. and Panisagar S.O..

Sikkim

12.12 Sikkim, which falls under the administrative control of West Bengal Circle, also comprises a part of the identified North Eastern region for the purpose of developmental activities. Two Extra Departmental Branch offices (EDBOs) were opened. 11 officials were imparted training in computers. Post Office building and SPMs quarters were constructed at Rangolibazar and Mangon.



“बधाई डाक” के शुभारंभ के अवसर पर श्री राम विलास पासवान माननीय संचार मंत्री तथा श्री बी. एन. सोम, सचिव (डाक) और श्रीमती अपरणा मोहिले, सदस्य (विकास)।

Shri Ram Vilas Paswan, Hon'ble Minister for Communications and Shri B.N. Som, Secretary (Posts) and Smt. Aparna Mohile, Member(D) at the Launching of "Greeting Post."

भोपाल में सातवीं अखिल भारतीय अकबर रफ़ीक़ मेमोरियल हाकी प्रतियोगिता में कप प्रदान करते हुए श्री दिग्विजय सिंह, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश।



Shri Digvijay Singh, Chief Minister, Madhya Pradesh distributing Cup in the 7th All India Akbar Rafiq Memorial Hockey Tournament at Bhopal.

महाराष्ट्र डाक सर्किल की वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर श्री बी. एन. सोम, सचिव (डाक) के साथ श्री डी. एस. भालचन्द्र, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र।

Shri B.N. Som, Secretary (Posts) alongwith Shri D.S. Bhalchandra, CPMG, Maharashtra at the inauguration of the Maharashtra Postal Circle website.



भाग - II
PART-II

कार्यकलाप
ACTIVITIES

(अप्रैल-दिसम्बर 2000)
(April - December 2000)

भाग - II

कार्यकलाप (अप्रैल-दिसम्बर 2000)

डाक नेटवर्क का विस्तार

1.1 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई.डी.बी.ओ.) और 50 उपडाकघर (डी.एस.ओ.) खोलने के लक्ष्य की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2000 की अवधि के दौरान 44 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 9 विभागीय उपडाकघर खोले गए हैं।

डाक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

1.2 उपर्युक्त विषय के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

1. डाक कार्यकलापों का आधुनिकीकरण
2. ट्रांजिट डाक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण
3. पंजीकरण छंटाई का कम्प्यूटरीकरण
4. प्रधान अभिलेख कार्यालयों / डिवीजन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण
5. एक्स-बी. आई.एस. मशीनों की संस्थाना

1.3 अप्रैल से दिसम्बर 2000 की अवधि के दौरान 34 लाख रुपये के वित्तीय परिष्यय से सर्किलों में 26 डाक कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया है और 64 लाख रुपये की लागत से 8 ट्रांजिट डाक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए उद्दिष्ट किया गया है। स्थल तैयार किए जा रहे हैं। डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर में आवश्यक साफ्टवेयर का मूल्यांकन किया जा रहा है। 81 लाख रुपये की लागत से चार कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण छंटाई केन्द्रों को कम्प्यूटरीकरण के लिए उद्दिष्ट किया गया है। कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण छंटाई के लिए साफ्टवेयर का उन्नयन किया गया है और हैदराबाद छंटाई कार्यालय में क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है। 61 लाख रुपये के परिष्यय से आठ प्रधान अभिलेख कार्यालयों (एच.आर.ओ.) को कम्प्यूटरीकरण के लिए उद्दिष्ट किया गया है। आवश्यक साफ्टवेयर का इन-हाउस विकास किया गया है और हैदराबाद में इसका क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। दो मौजूदा आर.एम.एस. यंत्रों में परिवर्तन के लिए रेलवे को 7 लाख रुपये की राशि जमा की गई है। इस वर्ष के दौरान 28 नए एयर ब्रेक मेल यंत्रों का विनिर्माण भी किया गया।

1.4 डाक भंडार डिपो के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के लिए एजुकेशनल कंसलटेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित एक नए साफ्टवेयर का सफल क्षेत्र परीक्षण किया गया है। इस साफ्टवेयर का प्रचालन करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिए गए हैं।

1.5 एयर लाइन प्राधिकारी को एक्सरे मशीनों पर अत्यधिक दबाव के कारण उनके द्वारा डाक का क्रमविक्षण करने में विलंब की समस्या को दूर करने हेतु तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा डाक/कार्गो के भारी परिमाण में निपटान करने वाली एजेंसियों से उनको अपनी एक्सरे मशीनें रखने के लिए उनसे अनुरोध करने की नीति के मद्देनजर दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई और गुवाहाटी हवाई अड्डों पर स्थित ट्रांजिट डाक कार्यालयों में एक्सरे-बी.आई.एस. मशीनें उपलब्ध कराने और उन्हें संस्थापित कराने का विभाग का प्रस्ताव है।

फिलैटली

1.6 अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2000 की अवधि के दौरान 45 स्मारक / विशेष डाक टिकट जारी किए गए।

1.7 फिलैटली सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में विशिष्ट व्यक्तियों पर आधारित डाक-टिकटों के विषयगत सेट (थेमैटिक सेट) निकाले जा रहे हैं ताकि इन डाक टिकटों का फिलैटली की दृष्टि से महत्व सुनिश्चित हो सके। 15 अगस्त को विभाग ने महान नेता : "सामाजिक एवं राजनीतिक" (चार स्टैम्पों का सेट) तथा 31 दिसम्बर, 2000 को "व्यक्तित्व आधारित शृंखला ऐतिहासिक" पर डाक टिकटों का सेट जारी किया।

1.8 डाक विभाग ने 2 अक्टूबर, 2000 को गांधीजी का चित्र लगा अन्तर्देशीय पत्र कार्ड जारी करके अन्तर्देशीय पत्र कार्ड का 50वां वर्ष मनाया।

1.9 इस अवधि के दौरान, विभाग ने कला एवं संस्कृति, वनस्पति / जीव-जन्तु, धरोहरों आदि पर जैसे - "मणिपुर एवं त्रिपुरा की प्राकृतिक संपदा" पर चार डाक टिकटों का सेट, "मवेशियों की देशी नस्लें" पर चार डाक टिकटों का सेट, "दून घाटी में रेलवे के सौ वर्ष", "सिडनी ओलम्पिक" पर चार टिकटों का सेट, अंतरिक्ष विषय पर तीन टिकटों का सेट, मधुबनी-



PART II

ACTIVITIES

(April - December 2000)

Expansion of postal network

1.1 During the period from April – December, 2000, 44 EDBOs and 9 DSOs have been opened against a target of opening of 500 Extra-departmental Branch Post Offices (EDBOs) and 50 Sub Post Offices (DSOs).

Computerisation of Mail offices

1.2 The activities covered under the above subject are as under:

1. Modernisation of Mail Offices
2. Computerisation of Transit Mail Offices
3. Computerisation of Registration Sorting Centres
4. Computerisation of Head Record Offices/ Divisional Offices
5. Installation of X-BIS Machines

1.3 During the period April to December 2000, 26 Mail Offices in the circles with an financial outlay of Rs.34 lakhs have been taken up and 8 Transit Mail offices have been identified for computerisation at the cost of Rs.64 lakhs. The sites are being developed. The necessary software is under evaluation at PTC Mysore. Four computerised Registration Sorting Centers have been identified for computerisation at the cost of Rs.81 lakhs. The software for computerised Registration Sorting has been upgraded and the field testing is being done at Hyderabad Sorting office. Eight Head Record Offices (HROs) have been identified for computerisation with an outlay of Rs.61 lakhs. Necessary software has been developed in-house and is undergoing field testing at Hyderabad. A sum of Rs.7 lakhs has been deposited with the Railway for conversion of two existing RMS vans. Fabrication of 28 New Air Brake Mail vans was also done during this year.

1.4 A new software developed by Educational Consultants of India Ltd. for computerisation and networking of Postal Store Depots, has been successfully field tested. Training have also been imparted to the staff for operating this software.

1.5 The Department, proposes to procure and install X-Ray BIS machines at the Transit Mail Offices at Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai and Guwahati Airports, to overcome the problem of delay in scanning of mails by Airline authorities due to over-pressure on their X-Ray machines and the policy of Bureau of Civil Aviation Security to ask the agencies handling heavy bulk of mails/cargo to own their own X-Ray machines.

Philately

1.6 During the period from April 2000 to December 2000, 45 commemorative/special postage stamps have been issued.

1.7 In accordance with the decision taken by the Philatelic Advisory Committee, personality based stamps are being brought out in thematic sets; to ensure philatelic relevance of these stamps. The department released sets of stamps titled "Great Leaders; Social and Political" (set of four stamps) on 15th August and "Personalities; Historical" on 31st December, 2000.

1.8 The Department of Posts observed 50 years of the inland letter cards this year by issuing inland letter card carrying the photograph of Gandhiji on 2nd October, 2000.

1.9 During the period, the Department released beautiful stamps on art & culture, flore & fauna, heritage etc. such as – set of four stamps on Natural Heritage of Manipur & Tripura, set of four stamps on Indigenous Breeds of cattle, 100 years of Railways in Doon Valley, set of four stamps on Sydney Olympics, set of three stamps on Space Theme, set of four

मिथिला चित्रकला पर चार डाक टिकटों का सेट तथा रत्न तथा आभूषण पर छः डाक टिकटों का सेट निकाला। मधुबनी-मिथिला चित्रकला और रत्न तथा आभूषण पर डाक टिकटों के सेट में मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत की समृद्ध कला एवं संस्कृति की झलक मिलती है।

1.10 वर्ष 1999 में जारी किए गए डाक टिकटों में से अत्यधिक लोकप्रिय डाक टिकटों का चयन करने के लिए विभाग ने अक्टूबर 2000 में डाक टिकट लोकप्रियता चुनाव का आयोजन किया।

1.11 अगस्त 2000 में "डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन" विषय पर देश भर में डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश भर के सभी सर्किलों से कुल 124 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। समिति के निर्णायकों ने सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के श्री सुभाष ई. पवार द्वारा तैयार डिजाइन को

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के रूप में चुना। प्रविष्टि को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यू.पी.यू. को भेजा गया।

1.12 डाक सप्ताह समारोह (9 से 14 अक्टूबर, 2000) के एक भाग के रूप में, देशभर में सर्किलवार डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन दो श्रेणियों में किया गया।

- (क) कनिष्ठ स्तर पर - 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए
- (ख) वरिष्ठ स्तर पर - 12 से 18 वर्ष तक के स्कूली बच्चों के लिए

प्रतियोगिता का विषय था :-

"विश्व को एक दूसरे के निकट लाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका"

1.13 संदर्भाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित सर्किल / राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

प्रदर्शनी का नाम	स्थान	अवधि
तानापेक्स 2000	कोयम्बतूर	02.08.2000 से 05.08.2000 तक
नागापेक्स 2000	कोहिमा	23.10.2000 से 25.10.2000 तक

विभाग द्वारा 14वीं एशियाई अंतर्राष्ट्रीय फिलैटली प्रदर्शनी 7 से 12 दिसम्बर, 2000 को नेताजी इंडोर स्टेडियम, कलकत्ता में आयोजित की गई।

व्यवसाय विकास

1.14 वर्ष के दौरान व्यवसाय विकास निदेशालय ने दो नए उत्पादों बधाई डाक और डाटा पोस्ट की शुरुआत की।

- (i) बधाई डाक एक विशिष्ट बधाई कार्ड होता है जिसके साथ डाक टिकट उभरा एक लिफाफा होता है। यह प्रयोक्ता के अनुकूल उत्पाद है। इस उत्पाद के इस्तेमाल का तरीका "खरीदिए और भेजिए" है।
- (ii) डाटा पोस्ट मूलतः किसी विशेष शहर/राज्यों के सभी नागरिकों के पत्तों का एक डाटा बेस है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में उसका पेशा/वित्तीय रूपरेखा, शौक और प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। इस प्रकार की सूचना सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी होगी और प्रत्यक्ष विपणन प्रयोजनों से उपयोगी होनी चाहिए।

1.15 व्यवसाय विकास समूह के पास डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, स्पीड, पोस्ट.ओर्ग., पर इसकी अपनी वेबसाइट है जो सभी प्रीमियम

उत्पादों का विपणन करता है और उत्पादों के ऑन-लाइन आदेश देने की अनुमति देता है। 200 विपणन एग्जीक्यूटिवों को विभिन्न स्पीड पोस्ट केन्द्रों में प्रीमियम उत्पादों के विपणन में गहन प्रशिक्षण दिया गया है।

1.16 डाक विभाग में व्यक्ति विश्वास के रूप में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने, जो अपने 12 लाख बिलों को पहले निजी कुरियर के माध्यम से वितरित किया करता था, इन बिलों के वितरण का कार्य दिल्ली स्थित डाकघरों को सौंप दिया। विशिष्ट दरों पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बिल वितरण के लिए यह एक विशेष सेवा है। इस अवधि के दौरान 13 नए राष्ट्रीय पोस्ट केन्द्र खोले गए हैं।

1.17 सितंबर 2000 में समाप्त छह महीने की अवधि के दौरान व्यवसाय विकास समूह ने पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि में 100.8 करोड़ रुपये की तुलना में 140 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया। यह 39.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.18 एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट में वर्ष के पूर्वार्ध में 239 प्रतिशत की पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक्सप्रेस पोस्ट में औसत मासिक राजस्व 17.7 लाख

stamps on Madhubani-Mithila Paintings, set of six stamps on Gems & Jewellery. The set of stamps on Madhubani-Mithila Painting and Gems & Jewelry reflect the rich art & culture of medieval as well as modern India.

1.10 A Stamp Popularity Poll was organized by the Department of Posts during October, 2000 for selecting the most popular stamp issued by the Department in the year 1999.

1.11 A nation-wide competition for design of stamps on the theme "Dialogue Among Civilization" was held in August, 2000. A total of 124 entries were received from the circles all over the country. The Committee of Judges selected the design prepared by Shri Subhash E. Pawar of C.B.D. Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra as the National Prize Winner entry. The

entry was sent to UPU for participation in the International Competition.

1.12 Another stamps design competition was held Circle-wise all over the country as a part of Postal Week celebration (9th to 14th October, 2000). The competition was held in two categories:

- (a) Junior level – for children upto 12 years, and
- (b) Senior level – for school children between 12 to 18 years.

The theme of the competition was:

"The role of Information Technology in bringing the world closer together"

1.13 The following Circle/State Level Exhibitions were held during the period under reference:

Name of the Exhibition	Place	Duration
TANAPEX 2000	Coimbatore	02-08-2000 to 05-08-2000
NAGAPEX 2000	Kohima	23-10-2000 to 25-10-2000

14th Asian International Philatelic Exhibition was organized by the Department at the Netaji Indoor Stadium, Calcutta during 7-12 December, 2000.

Business Development

1.14 During the year, Business Development Directorate launched two new products, namely, Greeting Post and Data Post.

- (i) Greeting Post is an unique greeting card with embossed envelope – a user friendly product. The by line for the product is 'Buy and Post'.
- (ii) The Data Post is basically a data base of addresses of all citizens of a particular city/states, incorporating profession/financial profiles in respect of each individual, his hobbies and preferences. This type of information will be socially and economically useful and should be useful for direct marketing purposes.

1.15 Business Development Group has its own web

site at www.speed.post.org which markets all the premium products and allows on-line ordering of products. 200 marketing executives have been given in-depth training in marketing of premium products in various Speed Post Centres.

1.16 As a measure of faith in the Department of Posts, MTNL which earlier despatch its 12 lakhs bills on private courier for delivery of its telephone bills, has handed over delivery of these bills to the post offices in Delhi. It is a special service for MTNL bill delivery at specific rates. During the period 13 new national Speed Post Centers have been opened.

1.17 During the six months ending September, 2000, Business Development Group generated a total revenue of Rs.140 crores as against Rs.100.8 crores in the same period during the previous year. This represents a growth of 39.03%.

1.18 Express Parcel Post has shown a remarkable growth in the first half of the year with 239% growth as compared to the corresponding period of the previous year. Average monthly revenue in Express

रुपये से बढ़कर 60 लाख रुपये हो गया है। बिजनेस पोस्ट में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि मॉडिया पोस्ट में 44 प्रतिशत और स्पीड पोस्ट में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1.19 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यू.पी.यू.) की 22वीं कांग्रेस का आयोजन 1999 में बीजिंग (चीन जनवादी गणराज्य) में आयोजित किया गया। भारत को प्रशासन परिषद् और डाक प्रचालन परिषद् के लिए पुनः चुना गया था। प्रशासन परिषद् एक विनियामक संस्था है जो कि यू.पी.यू. के कार्यकरण संबंधी नियम व विनियम तैयार करती है। डाक प्रचालन परिषद् पर डाक सेवा संबंधी प्रचालनात्मक, वाणिज्यिक, तकनीकी तथा आर्थिक मामलों का दायित्व है।

1.20 यू.पी.यू. के डाक प्रचालन परिषद् का वार्षिक सम्मेलन 1 से 11 मई, 2000 को बर्न (स्विटजरलैंड) में आयोजित किया गया। बैठक में भारत ने परिषद् की तीन समितियों, सेवा निधि की तदर्थ गुणवत्ता (क्यू.एम.एफ.) समिति, टर्मिनल इयूज एक्शन ग्रुप (टी.डी.ए.जी.) तथा तकनीकी सहयोग कार्य दल (टी.सी.ए.जी.) के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। डाक प्रचालन परिषद् 2000 ने पत्र-डाक विनियम, पार्सल डाक विनियम तथा डाक भुगतान विनियमों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया। डाक प्रचालन परिषद् द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव पहली जनवरी, 2001 से लागू हो जाएंगे।

1.21 प्रशासन परिषद् का वार्षिक सम्मेलन 9 से 20 अक्टूबर, 2000 को बर्न (स्विटजरलैंड) में आयोजित किया गया। भारत "सामान्य नीतिगत तथा सैद्धान्तिक मामलों" पर प्रशासन परिषद् की समिति-1 का अध्यक्ष है। एच.एल.जी. द्वारा यू.पी.यू. के पुनर्गठन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समिति अपना कार्य प्रारंभ करेगी। प्रशासन परिषद् की वित्त समिति (समिति-2) तथा तकनीकी सहयोग समिति (समिति-3) के कार्यों में भारत ने अहम भूमिका निभाई। समिति-2 की सिफारिशों पर आधारित, प्रशासन परिषद् ने यू.पी.यू. के वित्तीय नियमों में किए संशोधनों तथा 2001-2002 के दो वर्ष की अवधि के नियमित बजट का अनुमोदन किया। समिति-3 ने विशेष कार्यक्रम की सबसे कम विकसित देशों के पक्ष में कार्यान्वित करने का अनुमोदन किया। सार्वभौमिक सेवा के कार्य क्षेत्र तथा परिधि में विस्तार करने के मद्देनजर तथा संरचनात्मक सुधार एवं डाक विकास की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए इसने एल.डी.सी. के लिए वृहत स्तर पर अन्तर-क्षेत्रीय परियोजना बनाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो की योजना का समर्थन किया।

1.22 भारत ने यू.पी.यू. के उच्चस्तरीय ग्रुप की तीसरी, चौथी तथा पांचवीं बैठक जो क्रमशः मई, जुलाई तथा अक्टूबर, 2000 में आयोजित की गई थी, में भी हिस्सा लिया। उच्चस्तरीय ग्रुप, वरिष्ठ डाक अधिकारियों का ऐसा मंच है, जो कि यू.पी.यू. के भावी लक्ष्य तथा संरचना पर पुनः विचार करता है। उच्चस्तरीय ग्रुप ने यू.पी.यू. के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्तमान में यह यू.पी.यू. नियमों में नए सुधार लाने पर कार्य कर रहा है। आगे यू.पी.यू. के पुनर्गठन के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें गैर-सरकारी पणधारियों की अन्तर-सरकारी संस्थाओं की कार्य-प्रणाली में भी भागीदारी होगी। भारत ने बर्न (स्विटजरलैंड) में 5 से 6 अक्टूबर, 2000 में आयोजित ई.एम.एस. को-आपरेटिव की आम सभा की बैठक में भी भाग लिया। बैठक में विश्वभर में ई.एम.एस. सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई।

1.23 एशियाई प्रशान्त डाक यूनियन (ए.पी.पी.यू.) जो एशियाई तथा प्रशान्तीय क्षेत्रों के 28 देशों की एक सीमित यूनियन है, के कार्यों में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने एशियाई प्रशान्त डाक प्रशिक्षण केन्द्र के शासी निकाय की 30वीं बैठक तथा 12 से 18 सितम्बर, 2000 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तेहरान में आयोजित एशियाई प्रशान्त डाक यूनियन के आठवें कांग्रेस में भी भाग लिया। ए.पी.पी.यू. कांग्रेस, ए.पी.पी.यू. की सर्वोच्च संस्था है तथा प्रत्येक पांच वर्ष में इसकी बैठक का आयोजन होता है। इस कांग्रेस के दौरान ए.पी.पी.यू. के केन्द्रीय कार्यालय को मनीला से बदलकर बैंकाक में स्थापित करने तथा ए.पी.पी.यू. के केन्द्रीय कार्यालय तथा ए.पी.पी.टी.सी. दोनों के लिए सम्मिलित रूप से एक निदेशक के पद का निर्णय लिया गया। क्षेत्र में सदस्यीय देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई।

1.24 भारत ने, दिनांक 5-6 अक्टूबर, 2000 को मैडरिड (स्पेन) में आयोजित विश्व फिलैटली विकास संघ (डब्ल्यू.ए.डी.पी.) के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर श्री बी.एन. सोम, सचिव (डाक) को, डब्ल्यू.ए.डी.पी. के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। 2 से 5 अक्टूबर, 2000 को जेनेवा (स्विटजरलैंड) में आयोजित पोस्ट एक्सपो-2000 में भारत ने भाग लिया। 26 से 29 जून, 2000 को बर्लिन (जर्मनी) में आयोजित विश्व बचत बैंक संस्थान की 7वीं आम सभा में भी भारत ने भाग लिया।

Post has increased to Rs.60 lakhs from Rs.17.7 lakhs. Business Post growth was 45% followed by Media Post with 44% and Speed Post 33%.

International Relations

1.19 At the 22nd Congress of the Universal Postal Union (UPU), held at Beijing (People's Republic of China) in 1999, India was re-elected to the Council of Administration and to the Postal Operations Council. The Council of Administration is a regulatory body that frames rules and regulations regarding the functioning of UPU. The Postal Operations Council is responsible for operational, commercial, technical and economic matters concerning the postal service.

1.20 The Annual Session of the Postal Operations Council of the UPU was held at Berne (Switzerland) from 1-11 May, 2000. During the meeting, India played an active role in the work of the three committees of the Council, Ad-hoc Quality of Service Fund (QSF) committee, the Terminal Dues Action Group (TDAG) and the Technical Cooperation Action Group (TCAG). The POC 2000 examined the proposals relating to amendment of the letter post regulations, parcel post regulations and postal payment regulations. The new provisions adopted by the POC would come into force on 1st January, 2001.

1.21 The Annual Session of the Council of Administration (CA) was held at Berne (Switzerland) from 9-20 October, 2000. India is the Chairman of Committee 1 of the CA on "General Matters of Policy and Principle". This Committee will start its work after the HLG submits its report on restructuring of UPU. India played a significant role in the work of the Finance Committee (Committee 2) and the Technical Cooperation Committee (Committee 3) of the Council of Administration. Based on the recommendations of Committee 2, CA approved the amendments to the UPU Financial Regulations and adopted the regular budget for the two year period 2001-2002. Committee 3 approved the implementation of special programme in favour of the least developed countries (LDCs). It supported the International Bureau's plan to formulate a large scale inter-regional project for LDCs aimed at raising the scope and degree

of universal service and implementing the process of structural reform and postal development.

1.22 India participated in the 3rd, 4th & 5th meetings of the High Level Group of the UPU held in May, July and October, 2000 respectively. The High Level Group mandated to reconsider the future mission and structure of the UPU. The HLG has so far decided on a new mission statement for UPU. It is currently working on the recasting of UPU Acts. Further, efforts are on to work out a new structure for UPU whereby the non-governmental stakeholders will also have a say in the working of the inter-governmental body. India also participated in the meeting of the EMS Cooperative General Assembly held at Berne (Switzerland) from 5-6 October, 2000. During the meeting various measures were discussed to improve the quality of EMS Service worldwide.

1.23 India plays a meaningful role in the affairs of the Asian Pacific Postal Union (APPU), a restricted Union comprising of 28 countries of the Asian and the Pacific Region. India participated in the 30th meeting of the Governing Board of the Asian Pacific Postal Training Centre (APPTC) and the 8th Congress of the Asian Pacific Postal Union (APPU), held at Tehran, Islamic Republic of Iran from 12-18 September, 2000. The APPU Congress is the supreme organ of the APPU and its meeting is held every five years. During this Congress it was decided to shift the APPU Central Office from Manila to Bangkok and have a common Director for the APPU Central office and the APPTC. Meaningful discussions were also held on promoting technical cooperation between the member countries in the region.

1.24 India attended the Annual Session of the World Association for the Development of Philately (WADP) held at Madrid (Spain) from 5-6 October, 2000. Shri B.N. Som, Secretary (Posts), was elected the President of the WADP on this occasion. India participated at the POST EXPO 2000 held at Geneva (Switzerland) from 2-5 October, 2000. India participated in the 7th General Assembly of the World Savings Bank Institute held at Berlin (Germany) from 26-29 June, 2000.

1.25 भारत गणराज्य के संचार मंत्रालय तथा फेडरेशन के संचार तथा सूचना मंत्रालय के बीच 3 अक्टूबर, 2000 को डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहभागिता-1 पर एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत गणराज्य की ओर से माननीय संचार मंत्री श्री राम विलास पासवान तथा रूसी फेडरेशन की ओर से संचार व सूचना मंत्री श्री लियनिद डी. रीमैन द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार पर रूस के राष्ट्रपति महामहिम श्री ब्लादिमीर पुतिन के 2 अक्टूबर, 2000 के राजकीय दौर के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

1.26 संयुक्त राष्ट्र के विकास परियोजना के परियोजना समन्वयकर्ता श्री मार्क स्केर ने दिनांक 19 से 26 मई, 2000 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने कथित विषय पर भारत डाक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। यू.पी.यू. अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो के सहायक सलाहकार श्री एम. थिरेरी ब्यूसेन्ट ने दिनांक 2-10 अगस्त, 2000 को भारत का दौरा किया तथा भारत डाक के लागत-लेखा माडल तथा अन्य डाक प्रशासनों में उसकी अनुप्रयोज्यता पर विचार-विमर्श किया। न्यूजीलैंड पोस्ट से दिनांक 15 से 18 अगस्त, 2000 को एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया तथा व्यवसाय विकास कार्यनीति पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

1.27 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 30.10.2000 से 10.11.2000 तक पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद में कार्यपालक विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के लिए भारत द्वारा बंगलादेश, सुडान, कोमोरोस, जाम्बिया तथा केन्या के प्रतिभागियों को छह फैलोशिप प्रदान की गई।

1.28 16-18 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली में डाक और सम्बद्ध मामलों पर भारत-उज्बेक संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई। जनवरी, 1994 में तत्कालीन उज्बेक राष्ट्रपति के राजकीय दौरे के दौरान डाक और सम्बद्ध मामलों पर भारत गणराज्य और उज्बेक की सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय करार के क्रम में यह बैठक आयोजित की गई थी। फिलिपिन्स के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच डाक के तीव्र पारेषण, भारत डाक में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं, उज्बेक डाक के काउंटर और बचत बैंक कम्प्यूटरीकरण और भारत डाक के प्रीमियम उत्पादों और उनके विपणन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए व्यापक विचार-विमर्श किए गए। भारत डाक और उज्बेक

डाक ने ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं के अध्ययन पर अपनी-अपनी सहमति दी।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं

1.29 अन्तर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली (आई.पी.एस.) साइट, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (ई.एम.एस.) मदों के लिए ट्रेक व ट्रेस सुविधा उपलब्ध कराती है, को चेन्नई तथा कलकत्ता में तैयार किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली को चेन्नई में जनवरी 2001 में स्थापित किया जाएगा। यह मुम्बई तथा दिल्ली में पहले से ही कार्य कर रही है।

1.30 ई.एम.एस. (दस्तावेज तथा माल) तथा विदेशी पार्सलों (एयर/सर्फेस एयर लिफ्टेड तथा सर्फेस) की दरों में 1 नवम्बर, 2000 से संशोधन किए गए हैं। प्रत्येक सेवा को प्रदत्त प्राथमिकता के मदेनजर ई.एम.एस. की दरों को सबसे ऊपर रखते हुए तथा उसके पश्चात एयर, एस.ए.एल. व सर्फेस पार्सलों को क्रम में रखते हुए दरों को काफी युक्तिसंगत बनाया गया है। इसे ग्राहक को अपने पैसे का अधिकतम मूल्य देने के प्रयोजन से किया गया है।

1.31 1 नवम्बर, 2000 से पार्सलों के लिए सर्फेस एयर लिफ्टेड (एस.ए.एल.) डाक सेवा को 15 और देशों, नामतः ईरान, चीन, ब्राजील, बोत्सवाना, आस्ट्रेलिया, केन्या, ग्रीस, नार्वे, मैक्सिको, फिनलैंड, पुर्तगाल, रूस फेडरेशन, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड तथा जिम्बावे में प्रारम्भ किया गया है। पार्सलों के लिए एस.ए.एल. डाक सेवा अब 38 देशों में उपलब्ध है।

प्रीद्योगिकी उन्नयन

1.32 चालू वित्त वर्ष के दौरान बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क सहित 1000 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना किए जाने की संभावना है। वर्ष के दौरान उपग्रह मनीआर्डरों (एस.एम.ओ.) के लिए 88 सूक्ष्म भू-केन्द्रों, 466 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर (ई.एस.एम.ओ.) और 100 फ्रैंकिंग मशीनों का संस्थापन भी किया जाना है। इस वर्ष 100 प्रधान डाकघरों को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

1.33 दिनांक 30.12.2000 को सचिव (डाक) द्वारा महाराष्ट्र सर्किल के एक वेबसाइट, महाराष्ट्रपोस्ट.ओर्ग., की शुरुआत की गई। यह वेबसाइट डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करता है और महाराष्ट्र तथा गोवा में डाकघरों



1.25 Agreement on Cooperation in the field of Postal Services was signed between the Ministry of Communications of the Republic of India and the Ministry of Communications and Informatization of the Russian Federation on 3rd October, 2000. The agreement was signed by Shri Ram Vilas Paswan, Hon'ble Minister of Communications of the Republic of India and Mr. Leonid D. Reiman, Minister for Communications and Informatization of the Russian Federation. This agreement was signed during the State Visit of the Russian President H.E. Mr. Vladimir Putin to India beginning 2nd October, 2000.

1.26 Mr. Mark Scher, Project Co-ordinator, Postal Savings for Development project of the United Nations visited India from 19-26 May, 2000. He made a presentation on the subject to Senior Officers of the Department of Posts. Mr. Thierry Beaucant, Assistant Counsellor, International Bureau of the UPU visited India from 2 -10 August, 2000 to discuss a cost-accounting model for Department of Posts and its applicability in other postal administrations. A three-member delegation from New Zealand Post visited India from 15-18 August, 2000 to make presentations on Business Development Strategies.

1.27 An Executive Development Programme was organized at the Postal Staff College of India, Ghaziabad from 30.10.2000 to 10.11.2000 under the assistance in kind scheme of the Universal Postal Union. Six fellowships were granted by India for the programme to participants from Bangladesh, Sudan, Comoros, Zambia and Kenya.

1.28 The meeting of the Indo-Uzbek Joint Committee on Posts and Allied Matters was held at New Delhi from 16-18 January, 2001. This meeting was convened in pursuance of the bilateral agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Uzbekistan in the field of Posts and Allied Matters signed during the state visit of the Uzbek President in January, 1994. Wide-ranging discussions took place on cooperation of the fields of philately, speedy transmission of mail between the two countries, training facilities available in the Department of Posts, counter and savings bank computerisation of Uzbek Post and premium products

of Department of Posts and their marketing. India Post and Uzbek Post agreed to study the possibility of cooperation in the above mentioned fields.

International Postal Services

1.29 The site for the International Postal System (IPS) which provides track and trace facility for International Speed Posts (EMS) articles has been prepared at Chennai and Calcutta. IPS System will be installed in Chennai in January, 2001. It is already functioning in Mumbai and Delhi.

1.30 The rates of EMS (documents and merchandise) and Foreign parcels (Air/SAL & Surface) have been revised with effect from 1st November, 2000. The rates have been rationalized keeping in view the priority accorded to each service with rates of EMS at the high level followed by Air, SAL and Surface parcels. This has been done to provide the customer the maximum value for his money.

1.31 Surface Airlifted (SAL) Mail Service for parcels has been extended w.e.f. 1st November, 2000 to 15 more countries namely, Iran, China, Brazil, Botswana, Australia, Kenya, Greece, Norway, Mexico, Finland, Portugal, Russian Federation, South Africa, Thailand and Zimbabwe. With this, SAL Mail Service for parcels is now available to 38 countries.

Technology

1.32 During the current financial year, 1000 multipurpose counter machines including the S.B. LAN are likely to be installed. 88 Micro Earth Stations for Satellite Money Orders (SMO), 466 Extended Satellite Money Order (ESMO) and 100 Franking Machines are also to be installed during the year. 100 Head post offices are being fully computerised this year.

1.33 Maharashtra Postal Circle's website, maharashtrapost.org, was launched by the Secretary(Posts) on 30.12.2000. The website provides an overview of the services offered by the post office and carries information on the location, history and jurisdiction of post offices in Maharashtra and

के स्थान, इतिहास और अधिकार क्षेत्र संबंधी जानकारी प्रदान करता है। इस वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, डाक शुल्क दरों का परिकलन किया जा सकता है, फिलैटली अनुभाग से प्रपत्रों, चित्रों और अन्य डाक-टिकटों को भी डाउनलोड किया जा सकता है।

वित्तीय सेवाएं

1.34 अप्रैल 2000 से दिसंबर 2000 की अवधि के दौरान डाकघर बचत बैंक निम्नलिखित स्कीमों का प्रचालन करता रहा :

- बचत खाता योजना
- आवर्ती जमा योजना
- सावधि योजना : 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष
- मासिक आय योजना
- लोक भविष्य निधि योजना
- किसान विकास पत्र योजना
- राष्ट्रीय बचत पत्र
- राष्ट्रीय बचत योजना, 1992

1.35 बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और निजी आपरेटरों के आसन्न प्रवेश को ध्यान में रखते हुए डाकघर बचत बैंक ने नवीनतम

सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया है। अपनी ग्राहक सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। अनेक कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें पहले ही संस्थापित की जा चुकी हैं जिससे ग्राहकों को अपने लेन-देन का कार्य करने में सुविधा और तीव्रता प्राप्त हो गई है।

1.36 ग्राहकों की बढ़ी हुई अपेक्षाओं को पूरा करने, अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और डाकघर बचत बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता का उन्नयन करने की आवश्यकता समझते हुए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष सचिव (डाक) हैं और सदस्य वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बचत संगठन से हैं। समिति से यह अपेक्षित है कि वह डाकघर बचत बैंक को विनियमित करने वाले सांविधिक प्रावधानों की पुनरीक्षा करे, इसके अधिदेश में विस्तार का सुझाव दे और एक नई दृष्टि का निर्माण करे जिससे डाकघर बचत बैंक का नई सहस्राब्दि में प्रवेश हो सके।

डाक जीवन बीमा (पी.एल.आई.)

1.37 वर्ष 2000-2001 के व्यवसायिक लक्ष्य तथा अप्रैल से दिसंबर 2000 तक किया गया व्यवसाय तालिका सं. 15 में दिया गया है :

तालिका - 15			
डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय : 2000-2001			
श्रेणी	लक्ष्य (करोड़ रु. में)	उपलब्धियां (दिसम्बर 2000 तक)	
		पालिसियों की सं.	बीमित राशि (करोड़ रु.में)
डाक जीवन बीमा	1200	71518	639.74
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	600	57883	219.26

1.38 बीमा क्षेत्र में निजी आपरेटरों के प्रवेश के साथ प्रतियोगिता बढ़ी है। डाक जीवन बीमा ने डाक जीवन बीमा के विपणन के क्षेत्र में विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण की एक योजना आरंभ की है। बीमा एवं वित्त योजना कालेज, हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान सी.आई.एफ.पी. में 61 विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

1.39 देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण डाक जीवन

बीमा का व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से 1,75,036 अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण उन्हें बचत जुटाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बीमा कवर प्रदान करवाने में मदद करेगा।

1.40 डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कई परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इस वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के कम्प्यूटर केन्द्र का

Goa. On-line complaint, calculate postal tariffs, download forms and view and other stamps from the philately section can also be made on the website.

Financial Services

1.34 During the period April 2000 to December 2000, the Post Office Savings Bank continued to operate the following schemes:

- Savings Accounts Scheme
- Recurring Deposit Scheme
- Time Deposit Scheme: 1 Year
2 Years, 3 Years and 5 Years
- Monthly Income Scheme
- Public Provident Fund Scheme
- Kisan Vikas Patra Scheme
- National Savings Certificate
- National Savings Scheme, 1992

1.35 Keeping in view the increasing competition and the imminent entry of the private operators, Post Office Savings Bank has adopted the latest infor-

mation technology. With a view to bringing about a qualitative improvement in its customer services, an ambitious programme of computerising the Post Offices has been undertaken. A large number of computer based Multipurpose Counter Machines have already been installed which enable the customers to transact their business conveniently as well as expeditiously.

1.36 In recognition of the need to meet enhanced customer expectations, utilise the state of the art technology and upgrade the quality of service provided by the POSB, the Ministry of Finance, Government of India has recently constituted a High Powered Committee chaired by the Secretary(Posts) with members from Ministry of Finance, Reserve Bank of India, and the National Savings Organisation. The Committee is to review the statutory provisions governing the POSB, suggest enlargement of its mandate, and outline a new vision, which can take the POSB into the new millennium.

Postal Life Insurance (PLI)

1.37 The business targets for the year 2000-2001 and business secured from April to December 2000, is as given in Table No.15:

Category	Target (Rs. in crores)	Achievement (upto December, 2000)	
		No. of Policies	Sum assured (Rs.in crores)
PLI	1200	71518	639.74
Rural PLI	600	57883	219.26

1.38 With the entry of private operators in the Insurance sector competition has increased. The Postal Life Insurance has embarked upon a plan of training of Development Officers in the field of marketing of Postal Life Insurance. Training is being imparted at College of Insurance and Financial Planning, Hyderabad. During the year 61 Development Officers have been trained at CIFP.

1.39 With a view to giving thrust to the business

of Rural Postal Life Insurance in rural and backward areas of the country 1,75,036 Extra Departmental Agents have so far been trained. This training will help the mobilization of saving as well as providing insurance cover to the people in the rural areas.

1.40 A number of projects to computerise Postal Life Insurance and Rural Postal Life Insurance have been finalized. During the year the computer centre in Maharashtra has been upgraded. Computerisation

उन्नयन किया गया। 2000-2001 के दौरान सभी सर्किलों में ग्रामीण डाक जीवन का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूरा किए जाने की संभावना है।

मानव संसाधन विकास

1.41 विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित संस्थाएं हैं :-

- (i) पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद तथा
- (ii) क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा, मद्रुरै, मैसूर, सहारनपुर तथा वडोदरा

1.42 पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद द्वारा अप्रैल से दिसम्बर, 2000 की अवधि के दौरान सेवा में प्रवेश के समय के 4 और 12 सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में कुल 359 अधिकारियों ने भाग लिया। 197 अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया।

1.43 विदेश मंत्रालय के आई.टी.ई.सी. / एस.सी.ए.ए.वी. के तत्वावधान में "डाक सेवा में सूचना प्रौद्योगिकी" पर डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर 6 सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 16 देशों के 20 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।

1.44 यह अनुमान है कि इस वित्त वर्ष के दौरान 60 अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिए जाने के साथ-साथ 256 अधिकारियों को प्रवेश और सेवाकालीन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र

1.45 क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों में 1.4.2000 से 31.12.2000 की इस अवधि के दौरान कुल 8122 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अनुमान है कि 1.1.2001 से 31.3.2001 तक के चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त 2621 कर्मचारियों को भी प्रवेश और सेवाकालीन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कर्मचारी संबंध

1.46 इस अवधि के दौरान यूनियनों की मान्यता के लिए कर्मचारियों की 13 भिन्न श्रेणियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघ की मान्यता) नियमावली और अतिरिक्त विभागीय एजेंट (संघ की मान्यता) नियमावली के अंतर्गत पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई।

1.47 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान एफ.एन.पी.ओ., एन.एफ.पी.ई. और बी.पी.ई.एफ. के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें / विचार-विमर्श किए गए।

कर्मचारी कल्याण

1.48 वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकार द्वारा डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड को 2,47,00,000/- रुपये (दो करोड़ सैंतालिस लाख रुपये) का कुल अनुदान दिया गया।

खेलकूद

1.49 1 अप्रैल, 2000 से 31 दिसंबर, 2000 तक की अवधि के दौरान अखिल भारतीय डाक खेलकूद बोर्ड ने एथलेटिक्स और साइक्लिंग, वालीबाल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट और टेबल-टेनिस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

1.50 भोपाल में दिनांक 15.5.2000 से सातवीं अखिल भारतीय अकबर रफोक मेमोरियल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सी.पी.एम.जी., भोपाल हॉकी टीम ने यह प्रतियोगिता जीत ली। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

1.51 1.1.2001 से 31.3.2001 तक की अवधि के दौरान अखिल भारतीय डाक खेलकूद बोर्ड कबड्डी, फुस्रो, फुटबाल, बास्केटबाल, शतरंज और कैरम तथा भारोत्तोलन / पावरलिफ्टिंग / श्रेष्ठ शारीरिक सौष्ठव की प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा।

राजभाषा (रा.भा.)

1.52 वर्ष के दौरान भुवनेश्वर (उड़ीसा सर्किल), अम्बाला (हरियाणा सर्किल), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश सर्किल) और वडोदरा (क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय) में "राजभाषा सम्मेलन" का आयोजन किया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 10.7.2000 को डाक विभाग का, दिनांक 21.9.2000 को पंचमढ़ी डाकघर का, दिनांक 25.9.2000 को प्रधान डाकघर, उज्जैन का और दिनांक 18.10.2000 को वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक, औरंगाबाद के कार्यालय का निरीक्षण किया।

1.53 दिनांक 14 सितम्बर, 2000 को निदेशालय में हिन्दी दिवस मनाया गया। डाक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सदस्य (विकास), डाक सेवा बोर्ड ने सरकारी कामकाज में राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के समक्ष उप महानिदेशक (एम.

of RPLI work is likely to be completed in all circles during 2000-2001.

Human Resource Development

1.41 Training infrastructure of the Department consists of the following institutions;

- (i) Postal Staff College of India, Ghaziabad and
- (ii) Regional Postal Training Centers of Darbhanga, Madurai, Mysore, Saharanpur and Vadodara.

1.42 Postal Staff College of India, Ghaziabad conducted 4 induction and 12 In-service training course during the period April to December, 2000. In all, 359 officers participated in these courses. 197 officers have been imparted training in computers.

1.43 The Postal Training Centre, Mysore is conducting a 6 week course on 'Information Technology in Postal Service' under the auspices of ITEC/SCAAP programme of the Ministry of External Affairs. 20 participants from 16 countries are participating in the training programme.

1.44 It is anticipated that during this financial year 256 officers would be imparted training in induction and in-service programmes including 60 officers in computers.

Regional Postal Training Centres

1.45 In the Regional Postal Training Centers, a total of 8122 officials were imparted training during the period 1.4.2000 to 31.12.2000. It is anticipated that an additional number of 2621 officials would also be imparted training in induction and In-service programmes during the current financial year i.e. from 1.1.2001 to 31.3.2001.

Staff Relations

1.46 During the period, the process of re-verification under the Central Civil Services (Recognition of Service Association) Rules and Extra Departmental Agents (Recognition of Association) Rules in respect of 13 distinct categories of Staff for recognition of the Unions was initiated. The whole process has been completed during the year.

1.47 During the year under review, meetings/interviews were held with the representatives of the FNPO, NFPE and BPEF.

Staff Welfare

1.48 During the year 1999-2000 a total grant of Rs.2,47,00,000/- (Rupees two crores and forty seven lakhs) was given by the Government to the Postal Services Staff Welfare Board.

Sports

1.49 During the period from 1st April, 2000 to 31st December, 2000, All India Postal Sports Board organized Tournaments in Athletics and Cycling, Volleyball, Badminton, Hockey, Cricket and Table Tennis.

1.50 7th All India Akbar Rafiq Memorial Hockey Tournament was organised at Bhopal on 15-5-2000 and CPMG Bhopal hockey team won the tournament. The prize for the winner team was distributed by Shri Digvijay Singh, Chief Minister of Bhopal.

1.51 During the period from 1.1.2001 to 31.3.2001, All India Postal Sports Board will organise Tournaments in Kabaddi, Wrestling, Football, Basketball, Chess and Carom and Weightlifting/Powerlifting/Best Physique.

Official Language (OL)

1.52 During the year, 'RAJBHASHA SAMMELAN' was organised at Bhubaneswar (Orissa Circle), Ambala (Haryana Circle), Hyderabad (AP Circle) and Vadodara (Regional PMG Office). The Committee of Parliament on Official Language carried out inspection of Department of Posts on 10.7.2000 Post Office Panchmerhi on 21.9.2000, Head Post Office, Ujjain on 25.9.2000 and O/o Sr. Supdt. of Post Offices, Aurangabad on 18.10.2000.

1.53 Hindi Diwas was observed in the Directorate on 14th September, 2000. In a function held in Dak Bhawan, Member(D), Postal Services Board emphasized the need of compliance of the provisions of OL Act and Rules made thereunder in official work. Messages of Home Minister, Cabinet Secretary and Secretary(Posts) were read out by DDG (MM&TS) before the officers and staff of the Directorate. "HINDI FORTNIGHT" was also organized in the

एम.एंड टी.एस.) द्वारा गृहमंत्री, मंत्रिमंडल सचिव और सचिव (डाक) के संदेश पढ़े गए। दिनांक 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2000 तक डाक निदेशालय में "हिन्दी पखवाड़ा" का भी आयोजन किया गया।

1.54 वर्ष 1999-2000 के दौरान "क", "ख" और "ग" क्षेत्र में स्थित जिन सर्किलों ने हिन्दी में अपना सर्वाधिक कार्य किया है उन्हें "अखिल भारतीय डाक राजभाषा शील्ड योजना" के अंतर्गत राजभाषा शील्ड और नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रस्ताव है।

1.55 राजभाषा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों, राजभाषा नीति, के कार्यान्वयन तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन की स्थिति की पुनरीक्षा करने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर विभाग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण समय-समय पर किया जा रहा है।

1.56 14.9.99 से 14.9.2000 तक डाक विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समूची अवधि के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए डाक विभाग ने इस वर्ष इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार जीता। आने वाले समय में और भी बेहतर कार्य-निष्पादन करने के लिए हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं।



Postal Directorate from 3rd October to 17th October, 2000.

1.54 Under the "Akhil Bhartiya Dak Rajbhasha Shield Yojana", it is proposed to present Rajbhasha Shield and cash awards to the circles located in Region "A", "B" and "C" which have done their maximum work in Hindi during the year 1999-2000.

1.55 With a view to review the position of implementation of the Official Language Act and rules made thereunder, the official language policy and compliance of the Annual Programme issued by the Ministry of Home Affairs, Department of Official

Language, inspection of various offices of the Department is being carried out from time to time at the Directorate level.

1.56 The Golden Jubilee year of Rajbhasha has been observed by the Department of Posts and its Subordinate Offices from 14.9.99 to 14.9.2000. During the entire period various competitions and programmes were organised for promoting the use of Hindi. The Department of Posts won the IInd prize under Indira Gandhi Rajbhasha Shield Yojana this year for its outstanding work in the promotion of Hindi in the official work. We are striving hard to do still better in time to come.

तालिका - 16

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैराओं और 12.2.2001 तक बकाया पड़े पैराओं का ब्योरा

सी एवं ए जी रिपोर्ट संख्या एवं वर्ष	पैरा संख्या	विषय
1997 का 6	3.1	उपग्रह मनीआर्डर योजना
1999 का 6	59	1.19 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि
1999 का 6	61	भूमि का अविवेकशील प्रापण एवं अभ्यर्पण
1999 का 6	65	स्रोत पर आयकर नहीं काटना
2000 का 6	52	डाक सिविल विंग का कार्यकरण

तालिका - 17

31.3.2000 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

ग्रुप	अनुसूचित जाति	कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत
ग्रुप "क"	87	10.99 %	33	4.17 %
ग्रुप "ख"	270	14.41 %	77	4.11 %
ग्रुप "ग"	43045	18.28 %	15235	6.47 %
ग्रुप "घ" (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	10595	19.21 %	3731	6.76 %
ग्रुप "घ" (सफाई कर्मचारी)	831	79.44 %	62	5.92 %

तालिका - 18

31.3.2000 को भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और महिला कर्मचारियों की संख्या

ग्रुप	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग भूतपूर्व सैनिक	महिला
ग्रुप "क"	1	-	86
ग्रुप "ख"	-	-	121
ग्रुप "ग"	2258	69	27588
ग्रुप "घ" (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	464	18	4978
ग्रुप "घ" (सफाई कर्मचारी)	1	-	393

Table 16

Details of Paras in Report of Comptroller and Auditor General of India and still Outstanding as on 12.2.2001

C & AG Report No. & Year	Para No.	Subject
6 of 1997	3.1	Satellite Money Order Scheme
6 of 1999	59	Loss of revenue of Rs.1.19 crore
6 of 1999	61	Injudicious procurement & surrender of land
6 of 1999	65	Non-deduction of Income Tax at source
6 of 2000	52	Working of Postal Civil Wing

Table 17

Number of Employees: Scheduled Castes/Tribes as on 31.3.2000

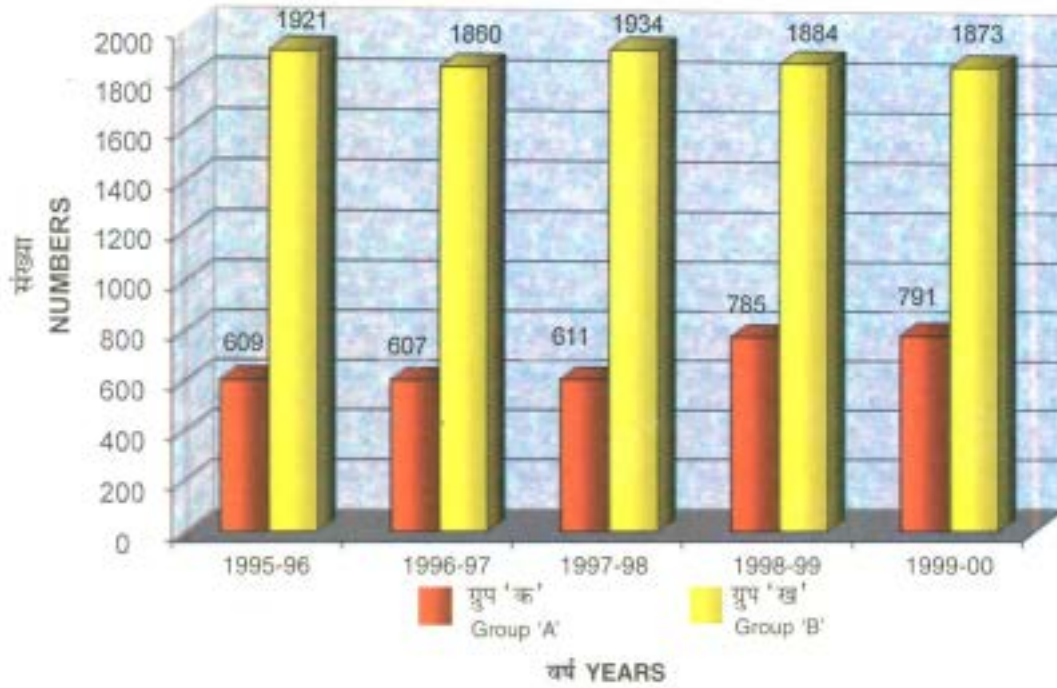
Group	Scheduled Castes	Percentage to total number of employees	Scheduled Tribes	Percentage to total number of employees
Group 'A'	87	10.99%	33	4.17%
Group 'B'	270	14.41%	77	4.11%
Group 'C'	43045	18.28%	15235	6.47%
Group 'D' (excluding sweeper)	10595	19.21%	3731	6.76%
Group 'D' (Sweeper)	831	79.44%	62	5.92%

Table 18

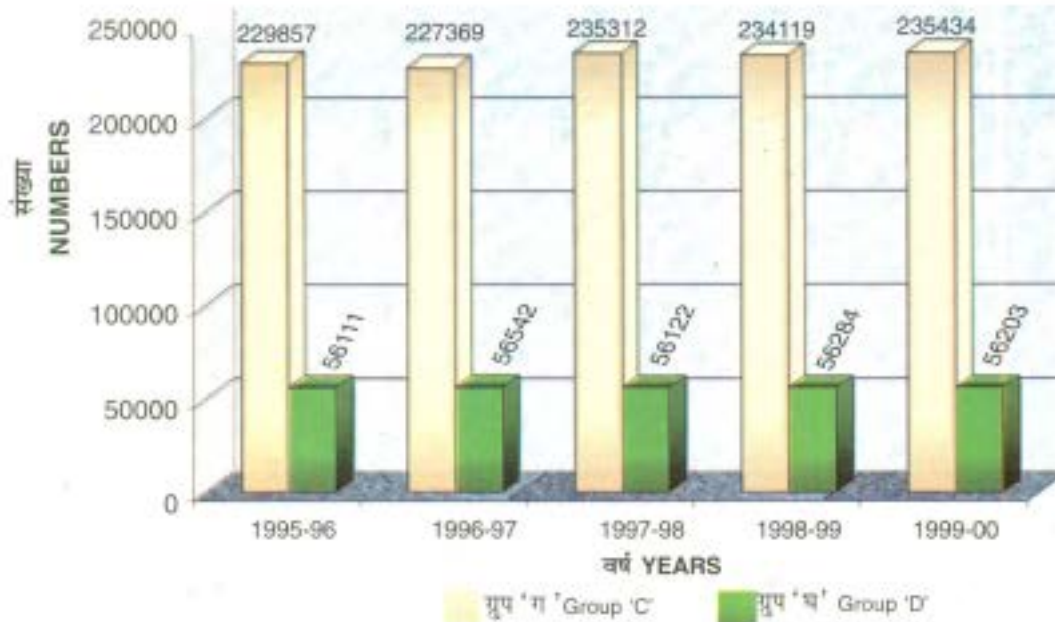
Number of Employees: Ex-servicemen, Disabled Ex-servicemen and Women, as on 31.3.2000

Group	Ex-servicemen	Disabled Ex-servicemen	Women
Group 'A'	1	-	86
Group 'B'	-	-	121
Group 'C'	2258	69	27588
Group 'D'(excluding Sweeper)	464	18	4978
Group 'D' (Sweeper)	1	-	393

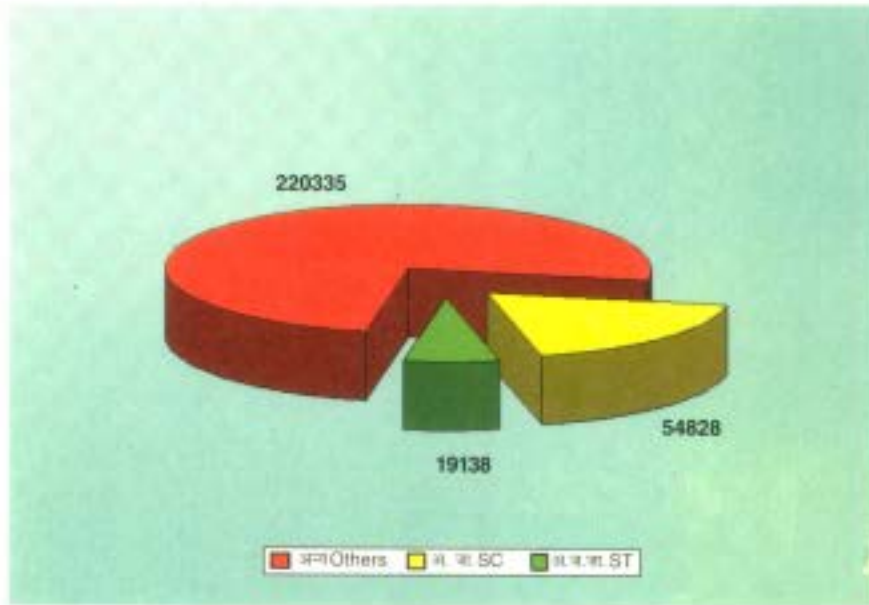
राजपत्रित अधिकारी
GAZETTED STAFF



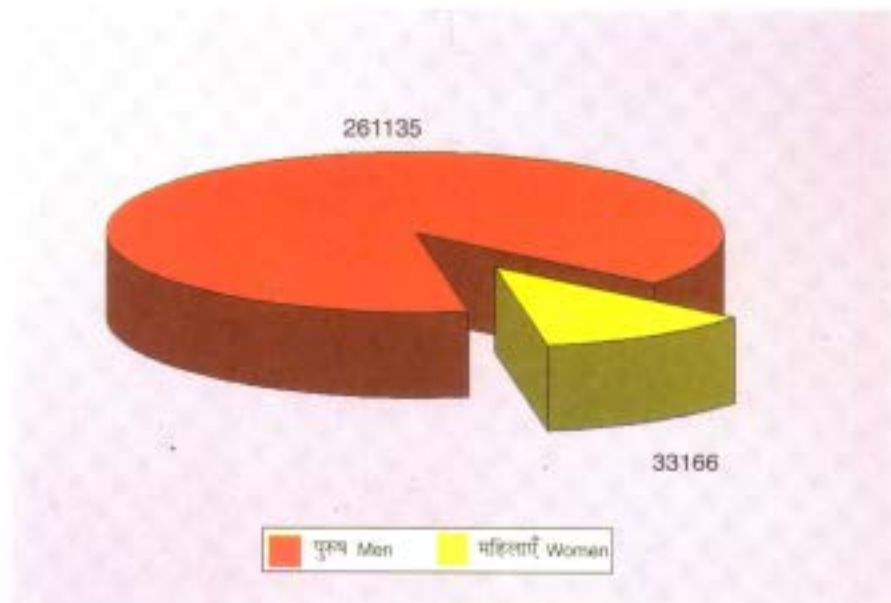
अराजपत्रित कर्मचारी
NON-GAZETTED



31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अ. जा/अ.ज.जाति (विभागीय)
SC/ST EMPLOYEES AS ON 31.3.2000 (DEPARTMENTAL)



31.3.2000 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारी (विभागीय)
WOMEN EMPLOYEES AS ON 31.03.2000
(DEPARTMENTAL)



तालिका - 19
कार्मिक : 31.3.2000 को वास्तविक संख्या
(विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण पर गए कार्मिकों सहित)

क. विभागीय			
राजपत्रित	ग्रुप "क"	ग्रुप "ख"	कुल
भारतीय डाक सेवा समूह "क"			
सचिव (डाक)	1	-	1
सदस्य, डाक सेवा बोर्ड	3	-	3
प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल	3	-	3
वरिष्ठ उप महानिदेशक / मुख्य पोस्टमास्टर जनरल	22	-	22
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	64	-	64
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	146	-	146
वरिष्ठ समयमान	61	-	61
कनिष्ठ समयमान	194	-	194
डाक सेवा ग्रुप "ख"	-	814	814
डाक-तार लेखा एवं वित्त सेवा			
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	1	-	1
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	10	-	10
वरिष्ठ समयमान	23	-	23
कनिष्ठ समयमान	19	-	19
वरिष्ठ लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी	-	231	231
सहायक लेखा अधिकारी	-	554	554
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	17	58	75
सिविल विंग			
मुख्य अभियंता	2	-	2
अन्य	57	142	199
अन्य सामान्य केन्द्रीय सेवाएं	168	74	242
कुल (राजपत्रित)	791	1873	2664
अराजपत्रित	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'	कुल
निदेशालय	435	145	580
डाकघर	2,03,346	33,467	2,36,813
रेल डाक सेवा	26,487	19,680	46,167
मेल डाक सेवा	1,857	477	2,334
अन्य	3,309	2,434	5,743
कुल (अराजपत्रित)	2,35,434	56,203	2,91,637
कुल विभागीय (क)			2,94,301
ख. अतिरिक्त विभागीय			3,09,649
कुल योग (क+ख)			6,03,950

Table 19

Personnel: Actual strength as on 31.3.2000
(including those on deputation and training outside the Department)

A. DEPARTMENTAL			
GAZETTED	GROUP "A"	GROUP "B"	TOTAL IN-
DIAN POSTAL SERVICE GROUP "A"			
Secretary (Posts)	1	-	1
Member, Postal Services Board	3	-	3
Principal Chief Postmaster General	3	-	3
Senior DDG/Chief PMG	22	-	22
Senior Administrative Grade	64	-	64
Junior Administrative Grade	146	-	146
Senior Time Scale	61	-	61
Junior Time Scale	194	-	194
POSTAL SERVICE GROUP "B"	-	814	814
P&T ACCOUNTS & FINANCE SERVICE			
Senior Administrative Grade	1	-	1
Junior Administrative Grade	10	-	10
Senior Time Scale	23	-	23
Junior Time Scale	19	-	19
Senior Accounts Officer/Account Officer	-	231	231
Asstt. Accounts Officers	-	554	554
CENTRAL SECRETARIAT SERVICE	17	58	75
CIVIL WING			
Chief Engineer	2	-	2
Others	57	142	199
OTHER GENERAL CENTRAL SERVICES	168	74	242
TOTAL (GAZETTED)	791	1873	2664
NON GAZETTED	GROUP "C"	GROUP "D"	TOTAL
Directorate	435	145	580
Post Office	2,03,346	33,467	2,36,813
Railway Mail Service	26,487	19,680	46,167
Mail Motor Service	1,857	477	2,334
Others	3,309	2,434	5,743
TOTAL (NON GAZETTED)	2,35,434	56,203	2,91,637
TOTAL DEPARTMENTAL (A)			2,94,301
B. EXTRA DEPARTMENTAL			3,09,649
GRAND TOTAL (A+B)			6,03,950

तालिका - 20

डाकघरों, कार्मिकों तथा मेल परियात की संख्या : एक रूपरेखा 1947-48 से 1999-2000 तक

वर्ष	डाकघरों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	मेल परियात (करोड़ रु० में)
1947-48	23,344		220.4
1950-51	36,094	1,53,000	235.0
1960-61	76,839	3,00,000	416.5
1970-71	1,09,059	4,23,000	645.7
1980-81	1,39,224	5,63,000	1,062.7
1990-91	1,48,719	5,92,000	1,468.3
1994-95	1,52,792	5,97,175	1,360.8
1995-96	1,52,781	5,98,323	1,395.8
1996-97	1,53,021	5,94,685	1,509.6
1997-98	1,53,454	6,04,257	1,574.9
1998-99	1,54,149	6,02,987	1,576.7
1999-2000	1,54,551	6,03,950	1,578.2

प्रति दिन निपटाई गई महानगरीय डाक
METRO MAIL HANDLED PER DAY

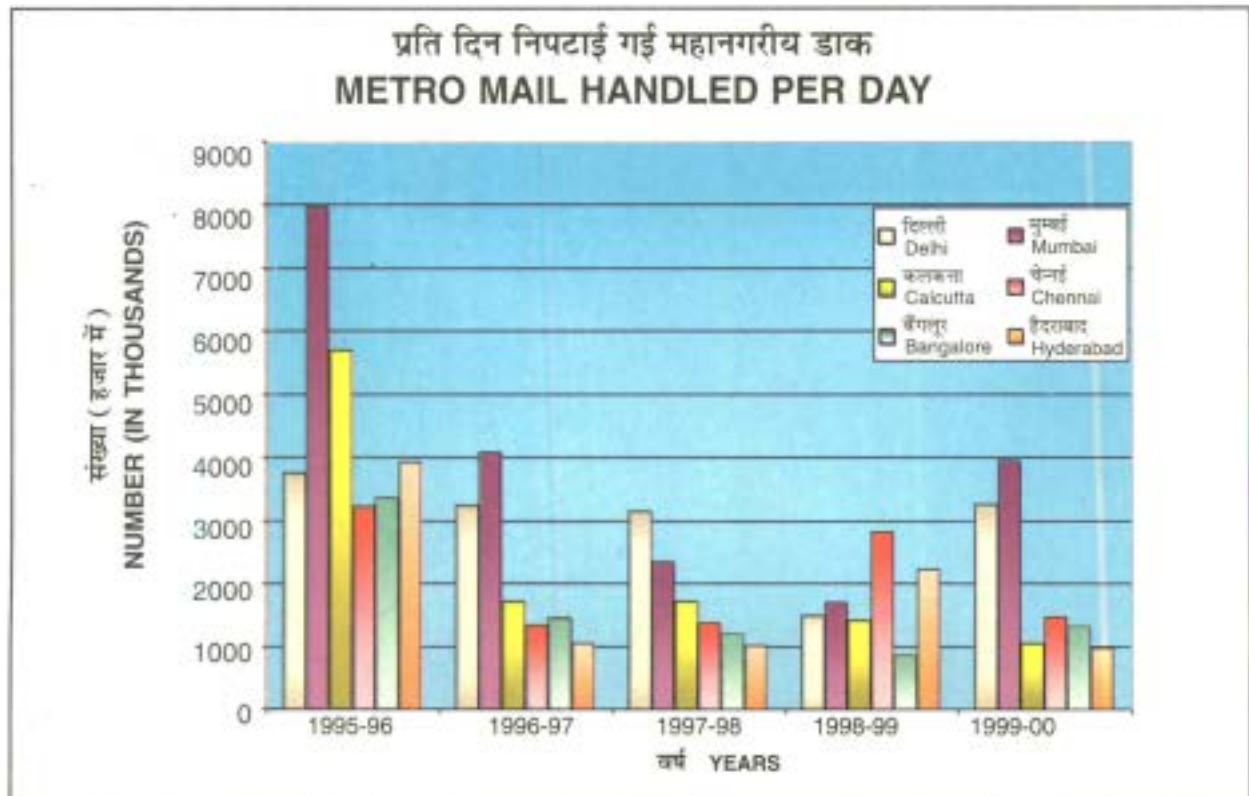
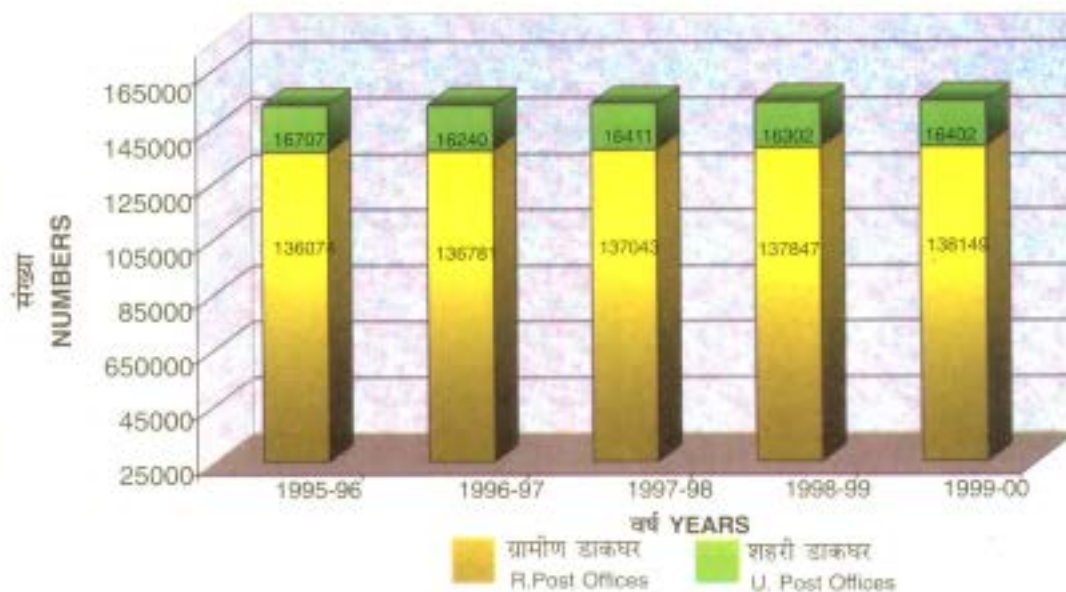


Table 20

Number of Post Offices, Personnel and Mail Traffic:
A Profile 1947-48 to 1999-2000.

Year	No. of Post Offices	Personnel employed	Mail Traffic (in Crores)
1947-48	23,344		220.4
1950-51	36,094	1,53,000	235.0
1960-61	76,839	3,00,000	416.5
1970-71	1,09,059	4,23,000	645.7
1980-81	1,39,224	5,63,000	1,062.7
1990-91	1,48,719	5,92,000	1,468.3
1994-95	1,52,792	5,97,175	1,360.8
1995-96	1,52,781	5,98,323	1,395.8
1996-97	1,53,021	5,94,685	1,509.6
1997-98	1,53,454	6,04,257	1,574.9
1998-99	1,54,149	6,02,987	1,576.7
1999-2000	1,54,551	6,03,950	1,578.2

डाकघरों की संख्या
NUMBER OF POST-OFFICES





तमिलनाडु सर्किल में तिरुपत्तूर ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए ए.एस. दुता, सदस्य (कार्मिक)। उसे देखते हुए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, श्री के. आर. रामबाद।
Shri S.C. Dutta, Member (P) inaugurating the Tiruppattur Customer Care Center in Tamil Nadu Circle. Looking on is CPMG, Shri K.R. Rambad.



कालीकट में केरल डाक सर्किल के वेबसाइट "केरलापोस्ट.ओर्ग" के उद्घाटन के अवसर पर श्री गौतम गुप्ता, सदस्य (प्रबन्धन)।
Shri Gautam Gupta, Member (O) at the inauguration of the Kerala Postal Circle website "keralapost.org" at Calicut.



डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर में “ डाक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी ” पर अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागी ।
 Participants in the International course on “Information Technology in Postal Services” at Postal Training Center, Mysore.



जम्मू एवं कश्मीर सर्किल की लद्दाख डिवीजन में बर्फानी झंस्कार नदी पर बनी “चादर लाइन” पर डाक ले जाता हुआ डाक वाहक ।
 Mail Runner carrying mail on “Chadar Line” formed on frozen Zanskar river in Ladakh Division of J & K Circle .



मैसूर स्थित डाक प्रशिक्षण कालेज-पूर्ववर्ती पैलेस और हैरिटेज बिल्डिंग।

The Postal Training College at Mysore - an erstwhile Palace and an Heritage Building.